{ विश्वास वही रफ्तार नई }

बालाघाट
गुरुवार 03 सितम्बर 2026
भाद्रपद कृष्ण 05 विक्रम सम्वत 2083
वर्ष 16, अंक 340
पृष्ठ 12
मूल्य ₹ 7.00

पद्मेश मीडिया समूह का प्रकाशन

बालाघाट एक्सप्रेस

हिन्दी दैनिक

सेंसेक्स	-	76,944.28
निफ्टी	-	24,055.80
सोना	-	1,62,946
चांदी	-	2,50,000
डॉलर	-	94.94

/padmeshmedia /padmeshmedia epaper.balaghatexpress.in E-mail: balaghatexpress@gmail.com

खास खबर

तमिलनाडु के 52 मंदिरों में स्मार्टफोन बैन

चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 52 प्रमुख मंदिरों में स्मार्टफोन ले जाने और इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। यह नियम लागू हो गया है। नए नियम के मुताबिक, श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश से पहले स्मार्टफोन काउंटर पर जमा करना होगा। इसके लिए हर फोन पर 5 रुपए चार्ज देना होगा। बिना कैमरे वाले मोबाइल फोन मंदिर के अंदर ले जाने की अनुमति होगी। मंदिर परिसर में फोटो खींचने, रील बनाने और वीडियो रिकॉर्ड करने पर रोक लगा दी गई है। इस नियम के तहत वीआईपी, बड़ी हस्तियों और मशहूर लोगों की फोटो या वीडियो बनाने की भी इजाजत नहीं होगी। हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स मंत्री रमेश ने यह जानकारी दी।

सेना की बोट डूबी, 2 जवान लापता

यमुनानगर। हरियाणा के यमुनानगर जिले में हथिनीकुंड बैराज के पास मंगलवार शाम यमुना नदी में सेना की बोट डूबने से लापता दो जवानों का 15 घंटे बाद पता नहीं लग पाया है। मंगलवार शाम को 5 बजे शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन रातभर चला। हेलिकॉप्टर से भी निगरानी की गई। हरियाणा के अलावा यूपी की एसडीआरएफ टीमें भी जुटी हैं। लोकल गोताखोरों को भी लगाया गया है। बैराज से निकलने वाली पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहर के किनारों पर सर्चलाइटों से निगरानी की गई। आज नहरों में पानी की सप्लाई कम करके दोबारा कोशिश होगी। सेना के वन पैरा स्पेशल फोर्स के बाढ़ बचाव दल के अभ्यास के दौरान यह हादसा हुआ था। हादसे में सेना के पांच जवान पानी में डूबने लगे थे। इनमें से तीन जवान करीब 600 मीटर तक तेज बहाव में तैरकर पश्चिमी यमुना नहर (डब्ल्यूजेसी) के गेट से बाहर निकलने में सफल रहे। लापता जवानों की पहचान महाराष्ट्र निवासी आर्यन पाटिल और जम्मू-कश्मीर के अखनूर निवासी अजय के रूप में हुई है।

सीएम विजय विधानसभा-सचिवालय शिफ्ट करने का कर सकते हैं ऐलान

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय विधानसभा और सचिवालय को ऐतिहासिक फोर्ट सेंट जॉर्ज परिसर से बाहर शिफ्ट करने की योजना का ऐलान कर सकते हैं। सरकार नए इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए पट्टिनपक्कम, नंदनबक्कम, कोयंबेडु और गिंडी में हाईवे विभाग की जमीन समेत चार जगहों पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फोर्ट सेंट जॉर्ज दशकों से तमिलनाडु सरकार और विधानसभा का मुख्यालय रहा है। यह घोषणा ऐसे समय हो सकती है, जब पारंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर राज्य में राजनीतिक बहस चल रही है। सीएम विजय ने पर्यावरण, कृषि भूमि और स्थानीय लोगों की आजीविका पर असर का हवाला देते हुए प्रोजेक्ट रद्द करने का ऐलान किया था।

कुछ ना कहना

राममंदिर के पहले सीईओ बने पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा

चंपत राय की जगह गोविंद देव गिरि महासचिव

अयोध्या। अयोध्या राम मंदिर के पहले सीईओ (चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर) के नाम का ऐलान कर दिया गया है। बुधवार को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा के नाम पर मुहर लगाई। जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में पश्चिमी वायु कमान को लीड किया था। वह देवरिया के रहने वाले हैं।

चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तीसरी बैठक चल रही है। इसमें ट्रस्ट के 3 नए ट्रस्टियों की घोषणा कर दी गई है। पहली बार महिला को भी शामिल किया गया। दिल्ली के महेश भागचंदका, अयोध्या के एडवोकेट मदन मोहन पांडेय और आरएसएस से जुड़ी शिकोहाबाद की निर्मला यादव को ट्रस्टी बनाया गया है। महेश भागचंद का विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल के रिश्तेदार हैं। 2020 में राम मंदिर के भूमि पूजन के धार्मिक अनुष्ठानों में वह मुख्य यजमान रहे थे। इसके बाद 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के दौरान भी यजमान रहे। 7 जून को चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया था। मामले में 8 आरोपी जेल में हैं। इससे पहले 2 जुलाई को हुई बैठक में महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया गया था। रिटायर्ड आईएफएस कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव बनाया गया। वहीं, 26 जुलाई को 9 संतों की धार्मिक समिति बनाई गई थी।

मैं ऐसा मंदिर चाहता हूं...

ट्रस्ट से जुड़े लोगों के मुताबित ट्रस्ट को सीईओ पद के लिए कुल 5585 आवेदन मिले थे। जिसमें जितेंद्र मिश्रा का भी आवदेन था। इन आवेदनों की जांच ट्रस्ट के सचिवालय ने समीर पांडा के नेतृत्व में की। इसके लिए AI, सूचना तकनीक, व्यक्तिगत बातचीत और सत्यापन जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया गया। ट्रस्ट से जुड़े लोगों के मुताबिक जितेंद्र मिश्रा को भी बाकी उम्मीदवारों की तरह ही स्क्रीनिंग, सत्यापन और ऑनलाइन मूल्यांकन से गुजरना पड़ा। अगस्त महीने में अयोध्या में आमने-सामने इंटरव्यू हुआ। वह अंतिम रूप से चुने गए 16 उम्मीदवारों में शामिल थे। ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने बताया कि एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा (रिटायर्ड) के लिखित आवेदन में एक वाक्य ऐसा था जो किसी विजन स्टेटमेंट से ज्यादा संकल्प जैसा लगता है। उन्होंने लिखा था कि -

मैं ऐसा मंदिर चाहता हूं जहां हर श्रद्धालु को सुरक्षा, सम्मान और उच्च स्तर के आध्यात्मिक दर्शन का अनुभव हो। ट्रस्ट को मिलने वाले हर रुपये का पूरी पारदर्शिता के साथ इस्तेमाल हो। साथ ही मंदिर की परंपराओं और सुरक्षा व्यवस्था का संचालन ऐसी अनुशासनपूर्ण व्यवस्था के तहत हो, जो लंबे समय तक राष्ट्रीय महत्व रखने वाली संस्था के अनुरूप हो।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में तीन नए सदस्य नियुक्त

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बुधवार को तीन नए सदस्यों की नियुक्ति की है। नए ट्रस्टियों में दिल्ली के महेश भागचंदका, अयोध्या के मदन मोहन पांडे और शिकोहाबाद की निर्मला यादव शामिल हैं। इनमें से एक सदस्य को विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के दिवंगत नेता अशोक सिंघल का रिश्तेदार बताया जा रहा है।

दरअसल, कुछ महीने पहले राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी को लेकर विवाद सामने आया था। इस मामले के बाद मंदिर के रोजमर्रा के प्रबंधन से लेकर दान और उपहारों के व्यवस्थित रखरखाव तक व्यवस्था में बदलाव की मांग उठी थी। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी को लेकर हुए विवाद के बाद ट्रस्ट के कामकाज और प्रबंधन व्यवस्था को लेकर सवाल उठे थे। इस मामले में आठ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। विवाद के बीच चंपत राय के महासचिव पद से इस्तीफा देने की भी बात सामने आई थी। अब ट्रस्ट में तीन नए सदस्यों की नियुक्ति और पहले सीईओ के चयन की प्रक्रिया को मंदिर प्रशासन को और व्यवस्थित एवं पेशेवर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

दिशा सालियान मौत की जांच सीबीआई करेगी

-2020 में एक्टर की मौत से 6 दिन पहले 14वीं मंजिल से गिरी थीं

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी। कोर्ट ने यह फैसला दिशा के पिता की याचिका पर सुनाया। इसमें उन्होंने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे। दिशा की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड में एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने से हुई थी। घटना के छह दिन बाद, 14 जून 2020 को सुशांत सिंह भी मुंबई के बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत मिले थे। दिशा केस की शुरुआती जांच करीब तीन महीने में बंद कर दी गई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर अलग-अलग दावे सामने आने के बाद 2023 में इसे दोबारा खोला गया और एसआईटी बनाई गई। तब से जांच जारी है।

जस्टिस एसवी कोतवाल और आरआर भोसले की बेंच ने 28 अगस्त को दिशा मामले की जांच हत्या के एंगल से कराने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने फैसले में सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी को मामले की जांच की जिम्मेदारी देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सिर्फ स्न्ढ्ढक्र में नाम होने से कोई व्यक्ति आरोपी नहीं माना जाएगा। अगर जांच में कुछ नहीं मिलता है तो सीबीआई को समरी रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। हाईकोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान, पंचनामा और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट समेत जांच के कई पहलुओं पर सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा कि परिवार के संदेह जताने के बावजूद स्न्ढ्ढक्र क्यों दर्ज नहीं की गई। पुलिस ने पहले ष्ठक्र दर्ज की थी और बाद में मौत को आत्महत्या बताया। कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि एडीआर की जांच इतनी लंबी क्यों चली।

पिता का आरोप- केस को दबाने की कोशिश की गई

दिशा के पिता सतीश सालियान ने हाईकोर्ट में नए सिरे से जांच की मांग की थी। उनका आरोप है कि दिशा के साथ गैंगरेप और हत्या हुई और मामले को दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने आदित्य ठाकरे समेत अन्य लोगों के खिलाफ स्न्ढ्ढक्र की मांग की थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिशा के पिता सतीश सालियान भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं 6 साल से इसका इंतजार कर रहा था। खुश होने की कोई वजह नहीं है। मैंने अपनी बेटी को खोया है। आज मुझे राहत महसूस हो रही है। मैंने हाथ जोडक़र जज के प्रति आभार जताया।

अमेरिका में एचडीएफसी बैंक के खिलाफ जांच शुरू

नए अध्यक्ष के साथ मतभेद से मची भगदड़

मुंबई। भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी बैंक के खिलाफ अमेरिका में शेयरधारकों के हितों से जुड़े संभावित उल्लंघन की जांच शुरू हो गई है। जुलाई 2026 में अमेरिका की तीन अलग-अलग कानून फर्मों ने जांच शुरू कर दी है। जांच महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से जुड़े करीब 45 करोड़ के भुगतान के आरोप की जांच कर रही है। इस राशि को मार्केटिंग खर्च के रूप में दिखाया गया, जो बैंकिंग नियमों का उल्लंघन है। एचडीएफसी का कारोबार सारी दुनिया में फैला हुआ है भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है।

अमेरिकी कानून के अंतर्गत जांच इस बात पर केंद्रित है। क्या एचडीएफसी बैंक ने अमेरिकी प्रतिभूति कानूनों के तहत निवेशकों को जानकारी समय पर उपलब्ध कराई थी। बैंक के आंतरिक लेन देन की जानकारी अमेरिकी निवेशकों को दी गई थी। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है। एचडीएफसी बैंक के अमेरिकी शेयर बाजार में ॅष्ठक्र एडीआर (अमेरिकन डिपाजिटरी रिसीप्ट) मे सूचीबद्ध हैं। अमेरिकी बाजार में सूचीबद्धता के कारण बैंक को वहां के प्रतिभूति कानूनों के अनुसार समस्त जानकारी देना और नियमों का पालन करना पड़ता है। इस विवाद के बीच एचडीएफसी बैंक के शेयर मे भी गिरावट शुरू हो गई है। 27 अगस्त 2026 को जारी एजेंसी के समाचार के अनुसार बैंक के शेयर ढाई साल के निचले स्तर पर पहुंच गए थे। रही सही कसर बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन ने अचानक पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बैंक के नए अध्यक्ष राजीव कुमार के साथ बैंक के अधिकारियों का तालमेल नहीं बैठ रहा है। जिसके कारण बैंक में आंतरिक विवाद शुरू हो गए हैं।

सिब्बल का आरोप : मतदाता सूची में हेरफेर के लिए बना एसआईआर

सुप्रीम कोर्ट से लगाई रोक की गुहार

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग द्वारा हो रही एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस प्रक्रिया को मतदाता सूची में हेरफेर की एक सोची-समझी कवायद बताया है, जिसका उद्देश्य भाजपा को आगामी चुनावों में फायदा पहुंचाना है। वरिष्ठ वकील सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से इस पूरी प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।

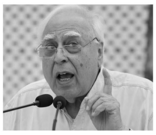

पूर्व केंद्रीय मंत्री की यह टिप्पणी मीडिया रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें दावा किया गया था कि झारखंड के गोड्डा जिले में भाजपा के एजेंट अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि स्थानीय बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) इसका विरोध कर रहे हैं। वरिष्ठ वकील सिब्बल ने घटनाक्रम को बहिष्कार की राजनीति करार दिया, जिसमें बड़े पैमाने पर मुसलमानों को निशाना बनाकर उनके नाम सूची से हटवाए जा रहे हैं।

सिब्बल ने कहा कि एसआईआर सिर्फ बहाना है, जिसके जरिए मतदाता सूची में छेड़छाड़ कर भाजपा को चुनाव जीतने में मदद की जा रही है। उन्होंने चुनाव आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार पर भी आरोप लगाए। सिब्बल ने कहा कि झारखंड और दिल्ली में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के पीछे ज्ञानेश कुमार का मकसद है, ताकि भाजपा के लोगों को उन मतदाताओं के नाम काटने का मौका मिल सके जो उन्हें वोट नहीं देते हैं, चाहे वे मुस्लिम हों या कांग्रेसी।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस पर दुख व्यक्त किया कि अदालतें इसतरह के गंभीर मुद्दों का संज्ञान नहीं ले रही हैं। उन्होंने जोर दिया कि यदि किसी गरीब व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से कट जाता है, तब उस गरीब इंसान को भारी नुकसान होता है, क्योंकि उसके पास अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते। इसलिए, सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से इस हेरफेर को रोकने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने का आग्रह किया है।

पीएनबी करेंसी चेस्ट में 17 करोड़ के नकली नोट, सभी 500 रुपये के

340 बंडलों में मिले फर्जी नोट, एक बंडल में पांच लाख रुपये

सहारनपुर। सोफिया मार्केट स्थित पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट में करीब 17 करोड़ रुपये के नकली नोट मिलने से बैंकिंग व्यवस्था में हड़कंप मच गया है। ऑडिट के दौरान सामने आए सभी नोट 500 रुपये के बताए जा रहे हैं। 340 बंडलों में मिले इन नोटों में ज्यादातर नए हैं, जबकि कुछ पुराने नोट भी जांच के दायरे में आए हैं। इतनी बड़ी मात्रा में एक ही मूल्यवर्ग के नकली नोट मिलने से किसी बड़े नेटवर्क की आशंका गहरा गई है।

मामले की जांच के लिए आरबीआई और पीएनबी मुख्यालय के 21 अधिकारियों की संयुक्त टीम लगाई गई है। टीम प्रत्येक नोट की बारीकी से जांच करने के साथ उसके सीरियल नंबर, स्रोत और बैंकिंग चैनल की पड़ताल कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक 500 रुपये के एक बंडल में 1,000 नोट यानी पांच लाख रुपये होते हैं। नोटों की जांच के लिए करीब 23 मशीनों का इस्तेमाल किया गया। जांच टीम यह पता लगाने में जुटी है कि इतने बड़े पैमाने पर नकली नोट करेंसी चेस्ट तक कैसे पहुंचे। आशंका है कि इन्हें अलग-अलग बैंक शाखाओं के माध्यम से जमा कराया गया हो और किसी स्तर पर इनकी पहचान नहीं हो सकी। पुराने और नए दोनों तरह के नकली नोट मिलने से यह भी जांच की जा रही है कि क्या लंबे समय से नकली करेंसी को धीरे-धीरे बैंकिंग व्यवस्था में खपाया जा रहा था। एलडीएम नवनीत शर्मा ने मीडिया को बताया, ऑडिट में जांचे गए सभी नोट 500 रुपये के हैं और कुल 340 बंडल मिले हैं। पुलिस ने मामले में वरिष्ठ मंडल प्रबंधक कार्यालय से जुड़े रवि कुमार कांसे, करेंसी चेस्ट प्रबंधक सुशील कुमार और जगाधरी करेंसी चेस्ट प्रबंधक अमित कुमार की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस संभावित ठिकानों के साथ मोबाइल लोकेशन के आधार पर भी आरोपितों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल इसी करेंसी चेस्ट से नकली करेंसी की रकम और बढ़ने की संभावना कम है, लेकिन एहतियातन अन्य करेंसी चेस्ट को भी अलर्ट किया गया है।

बीसीआई के अहम फैसलों में अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल की होगी भागीदारी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के कामकाज को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब तक नए सिरे से निर्वाचित बीसीआई का गठन नहीं हो जाता, तब तक उसके सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले अटॉर्नी जनरल आर.वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के समक्ष रखे जाएंगे। उन्हें बीसीआई की संबंधित बैठकों में भी आमंत्रित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने यह महत्वपूर्ण आदेश दिया है।

शीर्ष अदालत ने राज्य बार काउंसिलों को दो सप्ताह के भीतर अपने प्रतिनिधि चुनने का निर्देश दिया है। जिन राज्य बार काउंसिलों का पुनर्गठन हो चुका है, उन्हें अपनी संरचना अधिसूचित होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर अपने वैधानिक पदाधिकारियों और बीसीआई के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना होगा। सभी राज्य बार काउंसिलों को इस संबंध में अपनी अनुपालन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करनी होगी। इन रिपोर्टों के मिलने के बाद अदालत बीसीआई के पुनर्गठन के मुद्दे पर विचार करेगी। दरअसल सुनवाई के दौरान बीसीआई चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के कार्यकाल को लेकर गंभीर सवाल उठे। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीसीआई नियमों के तहत इनका कार्यकाल केवल दो वर्ष का है, जबकि 21 अप्रैल 2025 की अधिसूचना के जरिए पांच वर्ष (2030 तक) बढ़ाया गया है।

फर्जी टोल वसूली घोटाला : ईडी ने की ताबड़तोड़ छापेमारी

देशभर के 14 ठिकानों पर कार्रवाई

लखनऊ। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में एक बड़े फर्जी टोल कलेक्शन घोटाले के सिलसिले में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। एजेंसी ने आज सुबह से ही देश भर में लगभग 14 ठिकानों पर सघन सर्च ऑपरेशन चलाया। सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के सर्वर के समानांतर फर्जी/पायरेटेड सॉफ्टवेयर बनाकर की जा रही अवैध वसूली से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की जा रही है।

इस घोटाले का खुलासा पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने किया था, जिसमें सामने आया था कि टोल वसूली का सिर्फ 5प्रतिशत हिस्सा ही सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता था, जबकि शेष 95 प्रतिशत राशि का बड़ा गबन किया जा रहा था। आरोपी एनएचएआई के सिस्टम को बायपास कर फर्जी फास्टैग का इस्तेमाल कर ओवरलोडेड और वाणिज्यिक वाहनों को निकालते थे, जिससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था। प्रवर्तन निदेशालय इस पूरे नेटवर्क में धोखाधड़ी से लाभ उठाने वाले अंतिम लाभार्थियों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) की धारा 17 के तहत की जा रही इस कार्रवाई में उत्तर प्रदेश के वाराणसी समेत राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और कोलकाता स्थित परिसरों पर तलाशी ली जा रही है। छापेमारी के दौरान डिजिटल रिकॉर्ड, बैंक खातों के दस्तावेज और बेनामी संपत्तियों से जुड़े कागजात खंगाले जा रहे हैं।

बच्चों के बढ़ते अपहरण पर सख्त कानून की मांग, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल

-मानव तस्करी के मामलों में ओडिशा, बिहार, तेलंगाना और महाराष्ट्र

नई दिल्ली। देश में बच्चों के बढ़ते अपहरण के मामलों पर लगाम लगाने के लिए कानून सख्त करने की मांग वाली जनहित याचिका बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है। वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में संगठित गैर-कानूनी गोद लेने के रैकेट, अंतरराज्यीय चाइल्ड ट्रैफिकिंग नेटवर्क, और शोषण, अंगों की ट्रेडिंग व मेडिकल ट्रायल के लिए बच्चों के बड़े पैमाने पर अपहरण पर गंभीर चिंता जाहिर की गई।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस लापता, किडनैप हुए और अगवा किए गए बच्चों के मामलों में तत्काल एफआईआर दर्ज करने और त्वरित जांच करने में असफल रही है। देर से जांच और लंबे ट्रायल के कारण संगठित किडनैपिंग माफिया को अपना गैर-कानूनी धंधा फलने-फूलने में मदद मिलती है। इस संबंध में, याचिकाकर्ता ने कई अहम मांगें की हैं, जिसमें बच्चों के अपहरण की जांच एसीपी या एसएचओ स्तर के अधिकारी से कराने की बात प्रमुख है। इसके अतिरिक्त, अपहरण के मामलों को एक साल के भीतर निपटाने के लिए एमएलए-एमपी कोर्ट की तर्ज पर विशेष अदालतों के गठन और अपहरणकर्ताओं के परिवार के सदस्यों की संपत्ति जब्त करने का आग्रह किया गया है। दायर याचिका में बिहार के चौंकाने वाले आंकड़े सामने रखे गए हैं, जहां 2013 से प्रति वर्ष लगभग 15,000 लापता मामले दर्ज होते हैं, जिसमें अधिकांश बच्चे होते हैं और उनमें से मुश्किल से 50 प्रतिशत ही मिल पाते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि मानव तस्करी के सर्वाधिक मामले ओडिशा, बिहार, तेलंगाना और महाराष्ट्र में दर्ज होते हैं। नाबालिग लड़कों की तस्करी में ओडिशा और फिर बिहार शीर्ष पर हैं, जबकि लड़कियों की तस्करी में राजस्थान में सर्वाधिक मामले आते हैं। इन बच्चों को अक्सर भीख मांगने, बाल मजदूरी, वेश्यावृत्ति या अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों में धकेला जाता है। याचिका में हालिया मामले का भी उल्लेख किया गया है, जहां 5 जून 2026 को दिल्ली पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। यह गिरोह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे पांच राज्यों में सक्रिय था, जो आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के नवजात बच्चों को अगवा कर 8 से 10 लाख रुपये में बेचता था।

बच्चों की अचानक बढ़ी भीड़ से शुरुआती दौर में बिगड़ी व्यवस्था

अब जिला अस्पताल में पर्याप्त इंतजाम, करीब 400 बच्चों का हो चुका उपचार, सिविल सर्जन ने रखा पक्ष ,बोले -आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों के बीमार होने के कई कारण संभव

पदमेश न्यूज़। बालाघाट। आदिवासी अंचलों में बड़ी संख्या में बच्चों के बीमार होकर जिला अस्पताल पहुंचने के मामले के बीच बुधवार को जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. निलय जैन ने प्रेस वार्ता कर अस्पताल की व्यवस्थाओं और उपचाररत बच्चों की स्थिति को लेकर जानकारी दी। उन्होंने स्वीकार किया कि बच्चों की संख्या अचानक बढ़ने से शुरुआती दौर में अस्पताल की व्यवस्थाओं पर दबाव आया और कुछ समय के लिए स्थिति अव्यवस्थित हुई, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने तत्काल अतिरिक्त इंतजाम कर स्थिति को संभाल लिया। सिविल सर्जन के अनुसार वर्तमान में बच्चों के उपचार के लिए जिला अस्पताल में पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है।

अचानक ने बढ़ी बीमार बच्चो की संख्या

डॉ. जैन ने बताया कि शुरुआत में इक्का-दुक्का बच्चे ही उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंच रहे थे। उस समय उपलब्ध संसाधनों के अनुसार व्यवस्थाएं पर्याप्त थीं। लेकिन बाद में आदिवासी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में बच्चे एक साथ अस्पताल पहुंचने लगे, जिससे मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई। इसके चलते बेड, चिकित्सकीय स्टाफ और अन्य संसाधनों पर दबाव आया। अस्पताल प्रबंधन ने स्थिति को देखते हुए व्यवस्थाओं को प्राथमिकता के आधार पर पुनर्गठित किया और उपचार की व्यवस्था को सामान्य किया।

करीब 400 बच्चों का किया जा चुका उपचार

सिविल सर्जन के मुताबिक अब तक करीब 400 बच्चों को जिला अस्पताल में उपचार दिया जा चुका है। इनमें अधिकांश बच्चे उपचार के बाद स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में उपचार के दौरान एक बच्चे की मौत हुई, जबकि अन्य बच्चों को चिकित्सकीय निगरानी और आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया गया।उन्होंने कहा कि उपचार के दौरान मृत बच्चे की स्थिति गंभीर थी और उसे कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं। चिकित्सकों ने बच्चे को बचाने के लिए उपचार किया, लेकिन उसकी स्थिति गंभीर होने के कारण उसे बचाया नहीं जा सका।

अचानक बढ़ी संख्या बनी थी चुनौती

डॉ. जैन ने कहा कि एक साथ बड़ी संख्या में बच्चों के अस्पताल पहुंचने से प्रारंभिक स्तर पर व्यवस्थाओं के सामने चुनौती खड़ी हुई थी। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने इसे देखते हुए चिकित्सकीय स्टाफ, बेड, उपचार और अन्य जरूरी सुविधाओं को व्यवस्थित किया।उन्होंने दावा किया कि वर्तमान में जिला अस्पताल में बच्चों के उपचार के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। भर्ती बच्चों की नियमित निगरानी की जा रही है और आवश्यकता के अनुसार चिकित्सकों द्वारा उपचार किया जा रहा है।

एक नहीं, कई कारणों से बिगड़ सकती है बच्चों की सेहत

आदिवासी अंचलों में बच्चों के लगातार बीमार होने के कारणों पर सिविल सर्जन ने कहा कि किसी बच्चे की तबीयत खराब होने के पीछे एक से अधिक कारण हो सकते हैं। उन्होंने शुद्ध पेयजल, खान-पान, आसपास का वातावरण और अन्य स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों को महत्वपूर्ण बताया।उन्होंने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में स्वास्थ्य के अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं तो वहां एक के बाद दूसरे बच्चे के बीमार होने की स्थिति बन सकती है। इसलिए बच्चों के बीमार होने के पीछे किसी एक कारण को जिम्मेदार मानना उचित नहीं होगा। चिकित्सकीय जांच के आधार पर ही बीमारी के कारणों को स्पष्ट किया जा सकता है।

भर्ती बच्चों पर लगातार नजर, गंभीर स्थिति में तत्काल उपचार

सिविल सर्जन ने बताया कि जिला अस्पताल में भर्ती बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति पर चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है। बच्चों की आवश्यकता के अनुसार उपचार, जांच और चिकित्सकीय निगरानी उपलब्ध कराई जा रही है।उन्होंने कहा कि अस्पताल में बच्चों के साथ आने वाले परिजनों को भी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। किसी बच्चे की स्थिति गंभीर होने पर चिकित्सकों द्वारा तत्काल उपचार शुरू किया जा रहा है।

व्यवस्था सुधारने पर अस्पताल प्रबंधन का जोर

डॉ. जैन ने कहा कि बच्चों की संख्या में अचानक वृद्धि से उत्पन्न स्थिति से अस्पताल प्रबंधन ने सीख लेते हुए व्यवस्थाओं को और मजबूत किया है। वर्तमान में बच्चों के उपचार को लेकर किसी प्रकार की कमी नहीं होने देने का प्रयास किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य बीमार बच्चों को समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराना और उन्हें स्वस्थ अवस्था में घर भेजना है। साथ ही आदिवासी क्षेत्रों से आने वाले बच्चों की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य अमले द्वारा आवश्यक निगरानी और उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

रतनारा में नशे के खिलाफ महिलाओं का हुंकार- निकाली विशाल रैली

नशा मुक्त गांव के संकल्प के साथ सड़कों पर उतरी महिलाएं कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पहले ही उठा चुकी हैं आवाज

पदमेश न्यूज। बालाघाट। हट्टा थाना क्षेत्र के ग्राम रतनारा में नशे के खिलाफ ग्रामीण महिलाओं ने अब आर पार की लड़ाई का संकल्प लेते हुए मंगलवार 2 सितंबर को विशाल रैली निकाली। नशे के बढ़ते प्रचलन से गांव के सामाजिक वातावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को लेकर महिलाओं

ने एकजुट होकर ग्रामीणों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। रैली के दौरान महिलाओं ने नशा मुक्ति के समर्थन में नारे लगाते हुए पूरे गांव में जागरूकता का संदेश पहुंचाया।गौरतलब है कि ग्राम रतनारा कीमहिलाओं ने 1 सितंबर को जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गांव में नशे के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताई थी। महिलाओं ने प्रशासन से ग्राम को नशा मुक्त बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की थी। महिलाओं का कहना था कि नशे के कारण गांव का वातावरण लगातार प्रभावित हो रहा है और इसका सबसे अधिक असर परिवारों एवं युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है। ज्ञापन के अगले ही दिन महिलाओं ने अपने अभियान को और मजबूती देते हुए 2 सितंबर को ग्राम में विशाल रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सहभागिता कर यह स्पष्ट संदेश दिया कि वे अपने गांव को नशे के दुष्प्रभाव से मुक्त कराने के लिए एकजुट हैं।

नशे के खिलाफ महिलाओं ने बुलंद की आवाज

रैली के दौरान महिलाओं ने हाथों में जागरूकता संबंधी संदेश लेकर ग्रामीणों को नशे से होने वाले सामाजिक एवं पारिवारिक नुकसान के प्रति जागरूक किया। महिलाओं ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि इसका असर पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। नशे की वजह से आर्थिक स्थिति बिगड़ने के साथ ही पारिवारिक विवाद और सामाजिक अशांति जैसी समस्याएं भी बढ़ती हैं। महिलाओं ने युवाओं को नशे से दूर रहने और शिक्षा रोजगार एवं सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने का संदेश दिया। रैली के माध्यम से ग्रामीणों से भी अपील की गई कि वे नशे के खिलाफ इस मुहिम में सहयोग करें और गांव को नशा मुक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाएं।

कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर की थी कार्रवाई की मांग

ग्राम की महिलाओं ने 1 सितंबर को आयोजितजनसुनवाई में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की मांग की थी। महिलाओं ने प्रशासन का ध्यान ग्राम में नशे के कारण उत्पन्न हो रही परिस्थितियों की ओर आकर्षित करते हुए कहा था कि यदि समय रहते इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इसका दुष्प्रभाव आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ सकता है। महिलाओं की इस पहल के बाद अब गांव में नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान तेज होता नजर आ रहा है। 2 सितंबर को निकाली गई विशाल रैली इसी अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी रही।

नशा मुक्त रतनारा का लिया संकल्प

रैली के माध्यम से महिलाओं ने स्पष्ट संदेश दिया कि ग्राम रतनारा को नशा मुक्त बनाने के लिए वे लगातार प्रयास करती रहेंगी। महिलाओं की इस एकजुटता और पहल की ग्रामीणों के बीच भी चर्चा रही। महिलाओं ने कहा कि गांव के बेहतर भविष्य और बच्चों की सुरक्षित जिंदगी के लिए नशे के खिलाफ सामूहिक प्रयास जरूरी है। रतनारा में महिलाओं द्वारा निकाली गई यह रैली नशे के खिलाफ जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अब ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रशासन भी महिलाओं की मांग को गंभीरता से लेते हुए गांव में नशे के अवैध कारोबार एवं नशे की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।

ग्रामीणों की मांग पर विधायक विवेक पटेल का बड़ा तोहफा, कायदी में 15 लाख की सड़क स्वीकृत

डॉ. अभिजीत बाटे और जनपद सदस्य जितेंद्र राजपूत की पहल लाई रंग, पीपल पेड़ से जीतू नेवारे के मकान तक बनेगी सीसी सड़क

पद्मेश न्यूज। बालाघाट/वारासिवनी। जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम कायदी के ग्रामीणों के लिए लंबे समय से चली आ रही सड़क की मांग अब पूरी होने जा रही है। ग्रामीणों की मांग और जनप्रतिनिधियों की पहल पर वारासिवनी विधायक विवेक विक्की पटेल ने तत्काल 15 लाख रुपये की लागत से सीसी सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर ग्रामीणों को बड़ी सौगात दी है। ग्राम कायदी निवासी डॉ. अभिजीत बाटे एवं जनपद सदस्य जितेंद्र सिंह राजपूत ग्रामीणों के साथ वारासिवनी जनसंपर्क के दौरान विधायक विवेक विक्की पटेल से मिले। इस दौरान उन्होंने ग्राम की विभिन्न समस्याओं को विधायक के समक्ष रखा। इनमें सड़क की समस्या को प्रमुखता से उठाते हुए ग्रामीणों ने तत्काल सड़क निर्माण की मांग की।ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम कायदी में पीपल पेड़ से तालाब पार होते हुए जीतू नेवारे के मकान तक सड़क निर्माण की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। बारिश सहित अन्य समय में इस मार्ग से आवागमन में ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता था।ग्रामीणों की समस्या सुनने के बाद विधायक विवेक विक्की पटेल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल 15 लाख रुपये की लागत से सीसी सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी। सड़क स्वीकृति की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई।

मांग रखी, विधायक ने तत्काल पूरी की

ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण की मांग को लेकर वे विधायक के समक्ष पहुंचे थे, जहां विधायक ने उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए बिना किसी देरी के सड़क की स्वीकृति प्रदान की। इससे ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।सड़क निर्माण होने से ग्रामवासियों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी और वर्षों पुरानी समस्या का समाधान होगा। ग्रामीणों ने सड़क की तत्काल स्वीकृति प्रदान करने पर विधायक विवेक विक्की पटेल का आभार व्यक्त किया।इस दौरान डॉ. अभिजीत बाटे, जनपद सदस्य जितेंद्र सिंह राजपूत सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे।

थानेगांव के युवाओं की अनोखी पहल, 4 परिवारों को दी 27,800 रूपये की आर्थिक सहायता

आकस्मिक निधन पर पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हो रहे युवा, स्वच्छता, शिक्षा, ग्राम विकास और समाजसेवा को लेकर शुरू किया अभियान

पद्मेश न्यूज। लांजी। गांव में किसी परिवार पर अचानक दुख का पहाड़ टूटने पर उसे अकेला न महसूस होने देने के उद्देश्य से थानेगांव के युवाओं ने अनोखी पहल की शुरुआत की है। स्वच्छता, शिक्षा, ग्राम विकास एवं समाज सेवा के लक्ष्य को लेकर आदर्श युवा शक्ति समिति थानेगांव कल्याण कोष के माध्यम से गांव के जरूरतमंद परिवारों की मदद की जा रही है। बीते 15 दिनों में गांव के चार सदस्यों के आकस्मिक निधन के बाद युवाओं ने सहयोग राशि एकत्रित कर उनके परिवारों को कुल 27 हजार 800 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। समाजसेवी सुनील येड़े ने बताया कि युवाओं द्वारा शुरू की गई इस पहल के तहत ग्राम में किसी भी परिवार के सदस्य का आकस्मिक निधन होने पर समस्त ग्राम के युवाओं द्वारा सहयोग के रूप में समर्पण राशि जमा की जाती है। इसके बाद एकत्रित राशि मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है, ताकि विपरीत परिस्थिति में परिवार को कुछ राहत मिल सके। अब तक स्व. श्री हरिचंद जी नारनौरे के परिवार को 4 हजार रुपए, स्व. देवकी बाई शोभाराम जी चौहान के परिवार को 4 हजार रुपए, स्व. श्री बाबूराव जी सोमनकर के परिवार को 8 हजार रुपए तथा स्व. श्री अशीष खुन्नीराम जी नारनौरे के परिवार को 11 हजार 800 रुपए की सहायता प्रदान की जा चुकी है। इस तरह चार परिवारों को कुल 27 हजार 800 रुपए की सहायता दी गई है। युवाओं की यह पहल लगातार जारी है और समिति के कल्याण कोष में सहयोग राशि भी बढ़ रही है। युवाओं का कहना है कि यह केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि संकट की घड़ी में परिवारों के साथ खड़े होने और उन्हें सामाजिक सहयोग एवं सुरक्षा का भरोसा देने का प्रयास है।

परसवाड़ा क्षेत्र में बाघ की दहशत, ग्रामीणों ने जताया आक्रोश

सेरपार में दो बैलों पर हमला, एक का शव मिला, भोरवाही के खेत में भी दिखे थे पदचिन्ह शक्ति घाट के पास घटना से ग्रामीणों में आक्रोश, वन विभाग ने लगाए सीसीटीवी कैमरे

पदमेश न्यूज़। बालाघाट। पिछले कुछ महीनो से जिले की अलग-अलग तहसीलों के ग्रामीण क्षेत्रो में बाघ की मौजूदगी, लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रही है।जहां बाघ के हमले से जनहानि हो रही है तो वही स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है।जंगल से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिनों बाघ की मौजूदगी कि सामने आ रही घटनाओं के बीच अब परसवाड़ा क्षेत्र के सेरपार और खरपड़िया के बीच आने वाले शक्ति घाट के समीप सम्भवत: एक बाघ ने दो बैलों का शिकार कर लिया।इस घटना सामने आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि क्षेत्र में कई दिनों से बाघ की मौजूदगी की सूचना मिल रही थी, इसके बावजूद समय रहते प्रभावी निगरानी नहीं की गई।

एक बैल जा मिला शव, दूसरे की तलाश जारी

प्राप्त जानकारी के अनुसार सेरपार निवासी टीकम राहंगडाले का खेत बाकाराम परते ने अधिया बटई में लिया है।जानकारी के अनुसार शक्ति घाट के समीप ही बाकाराम के दोनो बैल चर रहे थे। इसी दौरान किसी जंगली जानवर ने दोनों पर हमला कर दिया। घटना के बाद एक बैल का शव बरामद हुआ है, जबकि दूसरे बैल की तलाश की जा रही है। ग्रामीणों का दावा है कि जिस क्षेत्र में यह घटना हुई है, वहां पिछले कुछ दिनों से बाघ की गतिविधियां लगातार देखी जा रही हैं।

भोरवाही में दिखा था बाघ

ग्रामीणों के अनुसार कुछ दिन पूर्व परसवाड़ा के समीप ग्राम भोरवाही के खेत में लोगों ने बाघ को देखा था। इसके बाद से ही आसपास के गांवों में बाघ की मौजूदगी को लेकर चर्चा और चिंता बनी हुई थी। दो दिन पहले ग्राम सेरपार के नाले में भी बाघ के पदचिह्न देखे जाने की बात सामने आई थी। इसके बाद अब शक्ति घाट के पास दो बैलों पर हमले की घटना ने ग्रामीणों की चिंता और बढ़ा दी है।ग्रामीणों का कहना है कि जब लगातार बाघ की मौजूदगी के संकेत मिल रहे थे, तब वन विभाग को संवेदनशील क्षेत्र में निगरानी बढ़ानी चाहिए थी। अब पालतू मवेशियों पर हमला होने के बाद लोगों को अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है।

आज बैल का शिकार हुआ, कल इंसान का नंबर न आ जाए

घटना स्थल पर पहुंचे ग्रामीणों ने वन विभाग के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि विभाग को लगातार मिल रही बाघ की सूचना को गंभीरता से लेना चाहिए था। ग्रामीणों ने सवाल उठाते हुए कहा कि बाघ ने आज बैल का शिकार किया है, क्या विभाग इंसान के शिकार का इंतजार कर रहा है।ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि क्षेत्र में मौजूद बाघ की तत्काल निगरानी कर उसे सुरक्षित रूप से आबादी वाले क्षेत्र से दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि खेतों और जंगल से लगे इलाकों में ग्रामीणों का रोजाना आना-जाना रहता है। ऐसे में बाघ की मौजूदगी लोगों के लिए गंभीर खतरा बन सकती है।

वन विभाग मौके पर पहुंचा, बाघ या तेंदुआ पर संशय

घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। हालांकि विभाग ने फिलहाल बैल के शिकार को लेकर यह पुष्टि नहीं की है कि हमला बाघ ने किया है या तेंदुए ने।वन विभाग के अनुसार मौके पर मिले बैल के शव पर फिलहाल खरोंच के निशान दिखाई दे रहे हैं। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है। विभाग द्वारा घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, ताकि क्षेत्र में आने वाले वन्यप्राणी की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और यह स्पष्ट हो सके कि बैल का शिकार बाघ ने किया है या तेंदुए ने।

लगातार सामने आ रही वन्यप्राणी की गतिविधियां

परसवाड़ा क्षेत्र में पिछले कुछ समय से वन्यप्राणियों की मौजूदगी को लेकर ग्रामीणों में चिंता बनी हुई है। बाघ के दिखाई देने, पदचिह्न मिलने और अब मवेशियों पर हमले की घटना ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग को केवल घटना के बाद मौके पर पहुंचने के बजाय पहले से निगरानी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए।

फिलहाल वन विभाग की निगाहें घटनास्थल के आसपास लगाए जा रहे कैमरों पर हैं। कैमरों की निगरानी से ही यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि क्षेत्र में सक्रिय वन्यप्राणी बाघ है या तेंदुआ। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग से रात के समय गश्त बढ़ाने और आबादी वाले क्षेत्रों में तत्काल निगरानी व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।

07 से 12 सितंबर तक होगी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2026

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2026 का आयोजन 07 से 12 सितंबर 2026 तक किया जा रहा है। परीक्षा के लिए बालाघाट में पीएम श्री जटाशंकर त्रिवेदी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इस केंद्र पर कुल 51 परीक्षार्थी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा 07 से 12 सितंबर तक प्रतिदिन प्रात: 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पूर्व पहुंचने तथा आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के सुचारू एवं व्यवस्थित संचालन के लिए बालाघाट जिले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी डॉ. श्रीकांत पाण्डे को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। प्रेक्षक द्वारा परीक्षा की व्यवस्थाओं एवं संचालन पर निगरानी रखी जाएगी। कलेक्टर कुमार सत्यम के मार्गदर्शन में परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा, बैठक व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न कराई जा सके।

नाम सूधार सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं शालिनी भगत पिता देव करण भगत वार्ड न. 05 ग्राम अंसेरा तहसील वारासिवनी जिला बालाघाट म.प्र. की निवासी हुँ।

मेरे आधार कार्ड,पेन कार्ड,वोटर आईडी में मेरा सरनेम(उपनाम) भगत लिखा हुआ है। किन्तु मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा सरनेम भगत दर्ज नही है। शालिनी एवं शालिनी भगत उक्त दोनो नाम मेरे स्वयं के है।

अत: मुझे शालिनी एवं शालिनी भगत उक्त दोनो ही नाम से जाना व पहचाना जावें।

आवेदक
शालिनी भगत
ग्राम अंसेरा तह. वारासिवनी
जिला बालाघाट(म.प्र)

नाम जन्मतिथि सूधार सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमति छाया पति रामप्रसाद कोटांगले वार्ड न. 09 ग्राम बेहरई पोष्ट कनकी तहसील लालबर्रा जिला बालाघाट म.प्र. की निवासी हुँ।

मेरे बेटे का नाम जन्म प्रमाण पत्र में विनय कोटांगले एवं जन्मतिथि 29/06/2005 दर्ज है जो कि सही है। किन्तु मेरे बेटे के आधार कार्ड में नाम ऋटिवश विजय कुमार एवं जन्मतिथि 05/05/2005 दर्ज हो गया है जो कि पूर्णत: गलत है ।

अत: मेरे बेटे के आधार कार्ड में सही नाम विजय कोटांगले और जन्मतिथि 29/06/2005 दर्ज किया जावे।

आवेदक
श्रीमति छाया कोटांगले
ग्राम बेहरई तह. लालबर्रा
जिला बालाघाट(म.प्र)

बारबेड वायर (कांटेदार तार) एवं चेन लिंक जाली उचित दाम पर उपलब्ध
लघु उद्योग निगम भोपाल से संबद्ध
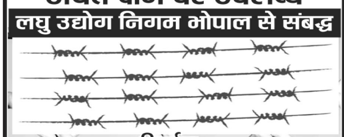
निर्माता
तिरूपति इंजीनियरिंग वर्क्स
मयूर टॉकिज के सामने हनुमान चौक, बालाघाट
फोन:- 07632-243531
मो:- 8989976858, 9425139998

बालाघाट सिटी न्यूज़
3
पद्मेश न्यूज
बालाघाट एक्सप्रेस
/padmeshmedia /padmeshmedia epaper.balaghatexpress.in E-mail: balaghatexpress@gmail.com

न्यूज गैलरी

नेशनल लोक अदालत की तैयारियों को लेकर अधिवक्ताओं के साथ बैठक आयोजित

पदमेश न्यूज़। बालाघाट। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार आगामी 12 सितंबर 2026, शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर बैठक आयोजित की गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्राणेश कुमार प्राण के मार्गदर्शन में आयोजित

बैठक की अध्यक्षता विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) रघुबीर प्रसाद पटेल ने की। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सतीष शर्मा भी उपस्थित रहे। बैठक में आगामी नेशनल लोक अदालत की तैयारियों एवं आयोजन से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान उपस्थित अधिवक्ताओं को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण से होने वाले लाभों की जानकारी दी गई। साथ ही अधिक से अधिक प्रकरणों का राजीनामा एवं आपसी सहमति के माध्यम से निराकरण कराने में सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा की गई। बैठक के दौरान अधिवक्ता श्री व्ही. एस. परिमल, खगेन्द्र चुरहे, आनन्द टेम्भरे, सुभाष तुरकर, सुभाष शुक्ला, श्री व्हाय. डी. टेंभरे एवं श्री जे.पी. मातरे सहित अन्य अधिवक्तागण उपस्थित रहे। अधिकारियों ने कहा कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को आपसी सहमति एवं राजीनामे के आधार पर प्रकरणों के शीघ्र एवं सरल निराकरण का अवसर मिलता है। बैठक में अधिवक्ताओं से 12 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए सक्रिय सहयोग करने का आह्वान किया गया।

बालाघाट बंद आज, केमिस्ट एसोसिएशन ने भी बंद को दिया समर्थन

कहा- सहायता राशि नहीं, पहले तय हो जिम्मेदारी, जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल निष्पक्ष जांच कर वास्तविक दोषियों पर कार्रवाई की मांग, दोपहर 1 बजे तक बंद रहेंगी जिले की दवा दुकानें

सिटी रिपोर्टर।
पदमेश न्यूज़। बालाघाट।

वनांचल क्षेत्रों में मासूम बैगा बच्चों की हुई मौतों का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है बच्चों की मौत को लेकर सामाजिक संगठनों और विभिन्न वर्गों के बाद अब बालाघाट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए 3 सितंबर को प्रस्तावित बालाघाट बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है बुधवार को एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुरेश सोनी एवं पदाधिकारी प्रियांक वर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इतने मासूम बच्चों की मौत के बाद भी यदि जिम्मेदारी तय नहीं होती है तो यह बेहद गंभीर और चिंताजनक स्थिति है।

3 सितंबर को दोपहर 1 बजे तक बंद रहेंगी दवा दुकानें

बालाघाट बंद को समर्थन देते हुए केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि 3 सितंबर को एसोसिएशन से जुड़ी दवा दुकानें दोपहर 1 बजे तक बंद रहेंगी। इस दौरान संगठन की ओर से दिवंगत मासूम बच्चों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि बंद का समर्थन किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि मासूम बच्चों की मौत के मामले में न्यायपूर्ण जांच और जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर किया जा रहा है। संगठन ने आमजन की भावनाओं और पीड़ित परिवारों के दर्द को देखते हुए बंद के समर्थन की बात कही।

स्वास्थ्य व्यवस्था की भी हो समीक्षा

केमिस्ट एसोसिएशन ने शासन से मांग की कि वनांचल क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था की भी व्यापक समीक्षा की जाए। दूरस्थ गांवों में दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकीय सेवाएं, जांच सुविधाएं, स्वास्थ्यकर्मियों की मौजूदगी और जरूरत के समय मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाए, ताकि भविष्य में किसी परिवार को अपने मासूम बच्चे की जान न गंवानी पड़े।

घटना को सामान्य ना माना जाए

पदाधिकारियों ने कहा कि बच्चों की मौत जैसी संवेदनशील घटना को किसी भी स्तर पर सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार को निष्पक्ष जांच के साथ-साथ कमियों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। संगठन ने दोहराया कि जांच में जो भी जिम्मेदार पाया जाए, उसकी जवाबदेही तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होनी चाहिए

एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि बच्चों की मौत के मामले को केवल आर्थिक सहायता देकर खत्म नहीं किया जा सकता। सरकार और प्रशासन को यह पता लगाना होगा कि आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों बनीं, बच्चों को समय पर उपचार और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं मिल सकीं और व्यवस्था के किस स्तर पर कमी रही। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच कर वास्तविक जिम्मेदारों की जवाबदेही तय की जाए।

29 मासूमों की मौत ने खड़े किए गंभीर सवाल, एसोसिएशन बोला हो कार्यवाही

केमिस्ट एसोसिएशन ने बालाघाट में 29 मासूम बैगा बच्चों की मौत का उल्लेख करते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की मृत्यु सामान्य घटना नहीं मानी जा सकती। यह पूरे जिले के लिए चिंता और संवेदना का विषय है। संगठन ने मांग की कि जांच में स्वास्थ्य सेवाओं, उपचार व्यवस्था, दवाओं की उपलब्धता, पोषण, मैदानी स्वास्थ्य अमले की भूमिका तथा प्रशासनिक स्तर पर संभावित लापरवाही सहित प्रत्येक पहलू को शामिल किया जाए पदाधिकारियों ने कहा कि घटना के कारणों की तह तक पहुंचना जरूरी है। यदि कहीं लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारी-कर्मचारी की जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

सिर्फ मुआवजा देने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती

एसोसिएशन ने स्पष्ट कहा कि मृत बच्चों के परिजनों को आर्थिक सहायता देना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन मुआवजा घटना की जवाबदेही का विकल्प नहीं हो सकता। पीड़ित परिवारों को सहायता के साथ यह भी जवाब मिलना चाहिए कि उनके बच्चों की जान किन परिस्थितियों में गई और समय रहते आवश्यक चिकित्सा सुविधा क्यों नहीं मिल पाई। पदाधिकारियों ने कहा कि जांच में यदि कोई निर्दोष है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो वास्तव में जिम्मेदार हैं, उनकी पहचान कर उनके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत से जुड़े मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि गंभीर घटनाओं में शासन स्तर पर तत्काल जिम्मेदारी निर्धारित करना जरूरी है।

सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने सौपा ज्ञापन

7 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की लगाई गुहार

पदमेश न्यूज़। बालाघाट। वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न सूत्रीय मांगे पूरी न होने से सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ प्रदेश सरकार से खासा नाराज है जहा आवेदन निवेदन पर भी कोई सुनवाई न होने पर अपनी नाराजगी जताते हुए जिला इकाई ने प्रदेश के सेवानिवृत्त इंजीनियरों से जुड़ी लंबित समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव सहित संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। संघ ने 7 सूत्रीय मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शीघ्र आदेश जारी करने का आग्रह किया है। जिला समिति ने बुधवार को सौंपे गए ज्ञापन में प्रदेश के हजारों सेवानिवृत्त इंजीनियरों के हितों से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं संघ ने मध्यप्रदेश राज्य के पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान महंगाई राहत देने की मांग प्रमुखता से रखी है। संघ के अनुसार केंद्र के समान महंगाई राहत दिनांक 1 जनवरी 2026 से प्रदान किए जाने संबंधी आदेश शीघ्र जारी किया जाना चाहिए।

20 लाख रुपए तक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा की मांग

सेवानिवृत्त इंजीनियरों ने स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पेंशनरों को 20 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के आदेश जारी करने की मांग की है पदाधिकारियो ने बताया कि उम्रदराज पेंशनरों को गंभीर बीमारी अथवा आकस्मिक उपचार की स्थिति में आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। इसीलिए 20 लाख रुपए तक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाना चाहिए।

35 वर्ष की सेवा पर चतुर्थ समयमान वेतनमान

संघ ने 35 वर्ष की शासकीय सेवा पूर्ण करने वाले डिप्लोमा धारी उपयंत्री संवर्ग के कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान प्रदान करने की मांग की है संघ ने 14 अगस्त 2023 का संदर्भ देते हुए इस संबंध में आदेश जारी करने का आग्रह किया गया है।

80 वर्ष की उम्र के बजाय चरणबद्ध अतिरिक्त पेंशन की मांग

संघ ने वर्तमान में 80 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन व्यवस्था में संशोधन की मांग भी की है। प्रस्ताव के अनुसार 65, 70, 75 और 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद प्रत्येक पांच वर्ष में पांच प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन प्रदान की जाए। संघ का कहना है कि इससे वरिष्ठ पेंशनरों को बढ़ती उम्र के साथ बढ़ते चिकित्सा एवं दैनिक खर्चों में राहत मिल सकेगी।

काल्पनिक वेतन वृद्धि और अंतर राशि का भुगतान हो

ज्ञापन में 30 जून और 31 दिसंबर के न्यायालयीन प्रकरणों में काल्पनिक वेतन वृद्धि के लिए प्रशासनिक स्वीकृति एवं आंशिक संशोधन के प्रस्ताव को शासन से शीघ्र मंजूरी देने की मांग की गई है। साथ ही न्यायालय के आदेशानुसार पेंशन पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण की अंतर राशि के भुगतान के लिए भी आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

लंबित एरियर्स का भुगतान शीघ्र करने की मांग

संघ ने छठवें एवं सातवें वेतन आयोग के लंबित एरियर्स के भुगतान का मुद्दा भी उठाया है। ज्ञापन में बताया गया है कि छठवें वेतन आयोग के 32 माह तथा सातवें वेतन आयोग के 27 माह के लंबित एरियर्स का भुगतान किया जाना बाकी है। संघ ने इसके लिए शीघ्र आदेश जारी करने की मांग की है।

पदोन्नति पर लगी रोक से प्रभावित कर्मचारियों को दे राहत

संघ ने अपनी सातवीं मांग में वर्ष 2016 से पदोन्नति पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध का मुद्दा उठाया है। संघ का कहना है कि इसके कारण हजारों कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो गए। ऐसे कर्मचारियों में जिनकी 2016 के बाद 35 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी है, उन्हें चतुर्थ समयमान वेतनमान प्रदान किए जाने की मांग की गई है।

मांग पूरी होने से हजारों कर्मचारियों को मिलेगी राहत

संघ पदाधिकारियो ने बताया की सेवानिवृत्त इंजीनियरों ने अपने सेवाकाल में प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब सेवानिवृत्ति के बाद उनकी लंबित मांगों का निराकरण करना शासन की जिम्मेदारी है संघ पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि शासन उनकी 7 सूत्रीय मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेते हुए आवश्यक आदेश जारी करेगा। उनका कहना है कि मांगों के निराकरण से प्रदेशभर के हजारों सेवानिवृत्त इंजीनियरों और पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा।

ओबीसी जनगणना को लेकर आर-पार की तैयारी

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने सौपा ज्ञापन, जनगणना में ओबीसी की अलग और वैज्ञानिक गणना की मांग, 6 सूत्रीय मांगो को लेकर सौपा ज्ञापन मांग पूरी न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी

पदमेश न्यूज़। बालाघाट। जनगणना-2027 में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की जातिवार जनसंख्या की गणना को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने आंदोलन का ऐलान किया है। संगठन की ओर से राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर ओबीसी की अलग से जनगणना कराने सहित 6 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि देश में ओबीसी की वास्तविक जनसंख्या का वैज्ञानिक, सटीक और विश्वसनीय आंकड़ा सामने आना आवश्यक है, ताकि उसी के आधार पर नीतियों का निर्माण किया जा सके।

ओबीसी की अलग जनगणना कराने की मांग

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने मांग की है कि जिस प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनगणना अलग तरीके से की जाती है, उसी पद्धति से ओबीसी की भी अलग जनगणना कराई जाए। संगठन का कहना है कि केवल जाति आधारित आंकड़े सामने आने से ही ओबीसी की वास्तविक सामाजिक एवं जनसंख्या स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

हर जाति के लिए अलग कोड की मांग

ज्ञापन में प्रत्येक राज्य के लिए आधिकारिक एवं व्यापक मास्टर जाति निर्देशिका तैयार करने की मांग भी की गई है। संगठन के मुताबिक अलग-अलग राज्यों में जातियों के नाम, उपनाम और स्थानीय पहचान को लेकर होने वाली विसंगतियों को दूर करने के लिए एक मानकीकृत व्यवस्था जरूरी हैमोर्चा ने जनगणना प्रक्रिया में प्रत्येक जाति को विशिष्ट कोड प्रदान करने की मांग रखी है। इसके साथ ही वर्तमान अनिर्धारित 'ओपन कॉलम' व्यवस्था के स्थान पर मानकीकृत विकल्प आधारित प्रणाली अपनाने की मांग की गई है, ताकि जातिवार आंकड़ों के संकलन में भ्रम और त्रुटियों की संभावना कम हो।

जातियों के सत्यापन के लिए बने संस्थागत व्यवस्था

ज्ञापन में असूचीबद्ध एवं स्थानीय जातियों के सत्यापन के लिए स्पष्ट संस्थागत व्यवस्था बनाने की मांग की गई है। मोर्चा का कहना है कि जाति संबंधी आंकड़ों के संकलन और सत्यापन की प्रक्रिया पारदर्शी एवं विश्वसनीय होनी चाहिए संगठन ने जाति संबंधी डेटा के संग्रहण, सत्यापन और संकलन की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, सुरक्षित और ऑडिट योग्य बनाए जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि जनगणना-2027 में जाति संबंधी आंकड़ों की शुद्धता बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके लिए स्पष्ट और मानकीकृत प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

मांग पूरी न होने पर करेंगे बड़ा आंदोलन

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि प्रथम चरण में 25 अगस्त को ज्ञापन सौंपे जाने के बाद अब 2 सितंबर से आंदोलन के दूसरे चरण के तहत जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर अनिश्चितकालीन क्रमिक धरना-प्रदर्शन किया जाना था लेकिन बरसात के चलते यह नहीं हो सका जिसके कारण ज्ञापन सौपा गया है जल्द ही आंदोलन के तीसरे चरण की योजना बनाई जाएगी। संगठन ने उक्त मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन करने और मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है।

जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया हरछठ पर्व

संतान की दीर्घायु के लिए मांओं ने किया 'हरछठ' का पूजन, परिवार की सुख समृद्धि की मांगी गई मन्नतें

पदमेश न्यूज़। बालाघाट। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी जिला मुख्यालय सहित अन्य तहसील व ग्रामीण अंचलों में हिंदू धर्मालंबी महिलाओं द्वारा हरछठ का पर्व हर्सोल्लास के साथ मनाया गया। जहां जगह-जगह विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, तो वही माताओ ने संतान की दीर्घायु उज्वल भविष्य और परिवार की सुख समृद्धि के लिए विशेष पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगी जहां माओ ने निर्जल व्रत रख सामूहिक रूप से विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए तो वही सामूहिक पूजा में हिस्सा लेकर विशेष प्रार्थना की गई नगर में सुबह से देर शाम तक हरछठ पर्व की धूम देखने को मिली।

धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप मनाया गया पर्व

हिंदू पंचांग के मुताबिक, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला हरछठ (हलषष्ठी) सौभाग्यवती माओ ने बुधवार को यह पर्व मनाया जहा विधिविधान से व्रतधारी महिलाओ ने विशेष पूजन अर्चन कर संतान की दीर्घायु के लिए प्राथनाएं की व्रताया जा रहा है कि यह पर्व भगवान श्रीकृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलरामजी के जन्मोत्सव रूप में भी मनाया गया। हरछठ के दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और उसके स्वास्थ्य जीवन की कामना के लिए व्रत रखकर पूजन आदि करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान हलधर यानी कि बलराम जी उनके पुत्रों को लंबी आयु प्रदान करते हैं। वहीं संतान प्राप्ति की भी कामना पूरी करते हैं। इस दिन अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना के साथ माताएं पूरे मन से पूजन करती हैं। बालाघाट में यह पर्व बड़ी ही आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ व्रतधारी महिलाओं के घर में मनाया गया बुधवार को व्रतधारी माताओं द्वारा घर में पूजन कर अन्य महिलाओं को पूजा के लिए आमंत्रित किया और सामूहिक रूप से पूजन उपरांत उन्हें बांस से बनी टोकरी में लाई, महुआ, चने और पूजन में चढ़े फलों का प्रसाद वितरित किया। वहीं अन्य सुहाग की सामग्रियों का आपसी में आदान प्रदान किया गया इस दौरान भजन कीर्तन सहित अन्य आयोजन भी सम्पन्न कराए गए।

संतान की दीर्घायु और उज्वल भविष्य के लिए की गई प्राथनाएं- व्रतधारी महिलाए

पर्व विशेष को लेकर की गई औपचारिक चर्चा के दौरान व्रतधारी महिलाओ ने बताया कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को पुत्र की दीर्घायु और उज्जवल भविष्य के साथ ही माताएं यह पूजन करती हैं। यह व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। इस पूजन में व्रतधारी महिलाएं बिना जोते परसोड़ के चावल और भैंस के दूध या दही का ही सेवन करती है संतान की दीर्घायु और उज्जवल भविष्य के लिए प्राथनाएं की जाती है।

उपयंत्री के भरोसे जनपद पंचायत लालबर्रा की व्यवस्था

सहायक यंत्री व मुख्य कार्यपालन अधिकारी दोनों की कमान संभाल रहे एक ही उपयंत्री, वित्तीय प्रभार तहसीलदार को, प्रशासनिक उदासीनता पर उठे सवाल

रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। लालबर्रा।

जनपद पंचायत लालबर्रा इन दिनों गंभीर प्रशासनिक संकट और अव्यवस्था के दौर से गुजर रही है। प्रशासनिक अनदेखी का आलम यह है कि पूरे जनपद का जिम्मा पूर्णकालिक (स्थाई) अधिकारियों की बजाय व्यवस्था एक उपयंत्री के कंधों पर डाल दिया गया है। जनपद पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) और सहायक यंत्री (एई) जैसे दो अति-महत्वपूर्ण पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं। इन दोनों ही जिम्मेदार पदों का प्रभार उपयंत्री घनश्याम भालेकर को सौंप दिया गया है जिन्हे प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियों के लिए वित्तीय प्रभार तहसीलदार के पास है। इस तरह से लालबर्रा जनपद पंचायत में स्थाई (पूर्णकालिक) मुख्य कार्यपालन अधिकारी और सहायक यंत्री दोनों महत्वपूर्ण पद रिक्त पडे हुए है। प्रशासनिक कार्य एवं 77 ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे है। जिससे ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन के द्वारा लालबर्रा जनपद पंचायत कार्यालय में स्थाई मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पदस्थापना अब तक नही की गई है। जनप्रतिनिधियों ने शासन-प्रशासन से लालबर्रा जनपद पंचायत में स्थाई मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पदस्थापना करवाने की मांग की है ताकि प्रशासनिक कार्य एवं पंचायत स्तर के कार्य प्रभावित न हो सके।

पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पदस्थापना की उठी मांग

आपकों बता दे कि लालबर्रा जनपद के अंतर्गत आने वाली सभी 77 ग्राम पंचायतों में विकास की रफ्तार थम सी गई है क्योंकि जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मंडलोई एवं सहायक यंत्री श्रीमती नागेश्वर का स्थानांतरण प्रशासनिक व्यवस्था के तहत पूर्व में हो चुका है। उनके स्थान पर अब तक दुसरे अधिकारी नही आये है। ऐसी स्थिति में एक ही अधिकारी (उपयंत्री) के पास दो पदों की जिम्मेदारी होने के कारण न तो तकनीकी मूल्यांकन समय पर हो पा रहा है और न ही प्रशासनिक फाइलों का निपटारा संभव हो पा रहा है। वहीं वित्तीय अधिकार तहसीलदार के पास होने से ग्राम पंचायतों को छोटी-छोटी राशि के आहरण और विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इस त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था का सीधा असर ग्रामीण अंचलों के विकास कार्यों पर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, सीसी रोड, नाली निर्माण और जल संरक्षण जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं तकनीकी स्वीकृति सहित अन्य कार्य प्रभावित हो रहे है। वहीं अपनी शिकायतों और समस्याओं को लेकर जनपद कार्यालय पहुंचने वाले ग्रामीणों को जिम्मेदार अधिकारी न मिलने से परेशान होना पड़ रहा है।

शासन-प्रशासन की नाकामी उजागर

लालबर्रा जैसी विशाल जनपद पंचायत को इस तरह प्रभार के भरोसे छोड़ना शासन और जिला प्रशासन की गंभीर उदासीनता और प्रशासनिक नाकामी को उजागर करता है। एक तरफ रा%य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के बड़े-बड़े दावे करती है। वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर पूर्णकालिक अधिकारियों की पदस्थापना तक नहीं की जा पा रही है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की इस उदासीनता का खामियाजा क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। यदि जल्द ही लालबर्रा जनपद पंचायत में पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालन अधिकारी और सहायक यंत्री की नियुक्ति नहीं की गई, तो ग्रामीण अंचलों में आक्रोश बढ सकता है। इसलिए ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि, जनपद सदस्य एवं जागरूक नागरिकों ने शासन-प्रशासन से लालबर्रा जनपद पंचायत में रिक्त मुख्य कार्यपालन एवं सहायक यंत्री के पद पर स्थाई (पूर्णकालिक) अधिकारियों की पदस्थापना या फिर प्रभारी सीईओं को ही प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रभार दोनों देने करने की मांग की है।

जनपद एवं पंचायत स्तर के कार्य हो रहे प्रभावित - अनीस

पांढरवानी सरपंच अनीस खान ने बताया कि जनपद पंचायत के सीईओं का स्थानांतरण होने के बाद सीईओं का प्रशासनिक प्रभार सहायक यंत्री (उपयंत्री श्री भालेकर) को सौंप दिया गया है। जबकि वित्तीय अधिकार तहसीलदार महोदय को दिये गये है। सहायक यंत्री और तहसीलदार दोनों के पास अपने मूल दायित्वों का पहले से ही काफी दबाव रहता है। प्रशासनिक अनुभव और पूर्ण समय की कमी के कारण जनपद पंचायत के विकास कार्य, सामग्री भुगतान तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे है। श्री खान ने बताया कि लालबर्रा ब्लॉक के अंतर्गत 77 ग्राम पंचायतें आती हैं, जो कि एक काफी बड़ा क्षेत्र है। इतने बड़े जनपद का कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए एक पूर्णकालिक और अनुभवी मुख्य कार्यपालन अधिकारी का होना बेहद आवश्यक है। अगर नये स्थाई सीईओं की पदस्थापना में समय लग रहा है तो बालाघाट जिले के ही किसी अन्य जनपद पंचायत के पदस्थ सीईओं को लालबर्रा का अतिरिक्त प्रभार दिया जाना चाहिए। पूर्णकालिक सीईओं के नही होने से हो रही परेशानियों संबंध में शीघ्र ही क्षेत्रीय विधायक महोदया और जिला प्रशासन को अवगत करवाकर स्थाई सीईओं की पदस्थापना की मांग करेंगे ताकि ग्राम पंचायतों के विकास कार्य प्रभावित न हो सके।

स्थाई सीईओं की पदस्थापना करें प्रशासन - देवीलता

जनपद अध्यक्ष श्रीमती देवीलता ग्वालवंशी ने बताया कि जनपद पंचायत लालबर्रा में पूर्व में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मंडलोई जी थे एवं सहायक यंत्री श्रीमती नागेश्वर थी। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था के तहत उनका स्थानांतरण हो चुका है परन्तु उनके स्थान पर अब तक पूर्णकालिक अधिकारियों की पदस्थापना नही हो पाई है। जिससे प्रशासनिक एवं निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे है और सरपंच सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजनों को परेशानी हो रही है। प्रशासन से मांग है कि स्थाई (पूर्णकालिक) मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पदस्थापना जल्द करें।

हर्षोल्लास एवं भक्तिभाव के साथ मनाया गया हरछठ पर्व

पुत्र की दीर्घायु और सुख-समृध्दि के लिए माताओं ने रखा हलषष्ठी का निर्जला व्रत

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को नगर मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में महिलाओं द्वारा 2 सितंबर को पुत्र की दीर्घायु, संतान प्राप्ति और परिवार की सुख-समृध्दि के लिए हरछठ (हलषष्ठी) का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास एवं

भक्तिभाव के साथ मनाया गया। यह पर्व भगवान श्रीकृष्ण के बड़े भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस अवसर पर नगर मुख्यालय स्थित स्व. श्याम अवधवाल के निवास एवं अमोली में संतोष अवधिया के निवास पर महिलाओं ने एकत्रित होकर विधि-विधान से हरछठ माता की पूजा-अर्चना की। सुबह से ही व्रतधारी माताओं ने निर्जला उपवास रखकर अपने पुत्रों के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की कामना की। चर्चा में व्रतधारी महिलाओं ने बताया कि इस दिन महिलाएं प्रात:काल स्नान आदि करने के बाद अपने पुत्रों की दीर्घायु की कामना करते हुए निर्जला व्रत रहती है, इस दौरान उनके द्वारा भैंस के गोबर से लीपकर चौक बनाने के उपरांत मिट्टी की सहायता से हरछठ को गाड़ा जाता है जिसे हल्दी से पीला किया गया। कपड़ा चढ़ाया जाता है एवं गुल्ली के तेल से दीपक प्रज्जवलित किया जाता है। इस पूजा में भैंस का गोबर, दूध, दही सहित सात प्रकार का भुना हुआ अनाज गेहूं, चना, मटर, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि चढाया जाता है इसके बाद हलषष्ठी माता की कथा सुनाई जाती है। आगे बताया कि हरछठ माता की पूजा अर्चना कर पुत्र की दीर्घायु की कामना कर उनके स्वास्थ्य व भविष्य की उज्जवल कामना की गई। इस व्रत में बिना हल चले हुए अनाज का उपयोग किया जाता है और व्रत करने वाली महिलाएं पसाई के चांवल का सेवन करती है। यह व्रत महिलाएं पुत्र की दीर्घायु व संतान प्राप्ति के लिए करती है। इस अवसर पर अमोली में श्रीमती संध्या अवधिया, कला यादव, वंदना यादव, शिवानी अवधिया, चांदनी यादव, सुमन दुलारे, गायत्री सोनी, शिल्पा धार्मिक, रेषु अवधवाल, सोनम दुलारे, साधना अवधिया, कामनी अवधिया, नेहा, रश्मि अवधिया, बिरन रोकड़े सहित अन्य महिलाएं उपस्थित रहे।

हल और मूसल से जुड़ा है हलषष्ठी का महत्व

आपकों बता दे कि भगवान बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने वाला हलषष्ठी (हरछठ) पर्व प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 2 सितंबर को हिंदू धर्मावलंबियों के द्वारा भक्तिभाव एवं विधि विधान के साथ मनाया गया। वहीं शास्त्रों के अनुसार भगवान बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल और मूसल है। जिस कारण उन्हे हलधर भी कहा जाता है। इसी वजह से इस तिथि को हलषष्ठी या हरछठ के रूप में पूजा जाता है। यानि की इस दिन को हलषष्ठी या हरछठ के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत में हल से जुते हुए किसी भी अन्न या फल का उपयोग वर्जित रहता है। व्रतधारी महिलाएं पारंपरिक रूप से पसाई के चांवल का ही सेवन करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान बलराम के साथ-साथ भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश, कार्तिकेय जी, नंदी और सिंह की पूजा करने से संतान को दीर्घायु, आरोग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पूजन के समापन पर माताओं ने अपने पुत्रों के सिर पर हल्दी का टीका लगाकर उनके दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। वहीं इस व्रत में उपयोग होने वाली पूजन सामग्रियों में भैंस का गोबर, दूध, बिना हल के जोते हुए अनाज, लाई, चना, महुआ, गुल्ली का तेल सहित अन्य सामग्री का उपयोग किया गया। व्रतधारी महिलाओं के द्वारा हरछठ माता की पूजा अर्चना कर पुत्र की दीर्घायु की कामना कर उनके स्वास्थ्य व भविष्य की कामना की गई।

आदिवासी बच्चों की असमय मौतों से आक्रोश व्याप्त, लालबर्रा बंद आज

म.प्र. आदिवासी विकास परिषद ने लालबर्रा बंद पर दुकानदार एवं व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर सहयोग करने की अपील की

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। बिरसा विकासखंड के सुदूर वनांचल कोरका, कोंडेकसा एवं बोदरी सहित अन्य वनग्राम में बैगा जनजाति के परिवारों पर आई दु:ख की घड़ी ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। क्षेत्र में अज्ञात बीमारी के कारण अब तक 29 बच्चों की मृत्यु की दु:खद घटना के बाद कई परिवार गहरे सदमे और संकट से गुजर रहे हैं। इस तरह से आदिवासी बच्चों की लगातार हो रही अज्ञात मौतों को लेकर आदिवासी समाज का गुस्सा फूट पड़ा है। प्रशासनिक उपेक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली से नाराज आदिवासी समाज, एसटी, एससी, ओबीसी के सहयोग से जिला बंद का आव्हान किया गया है। इसी कड़ी में आदिवासी विकास परिषद लालबर्रा ने 3 सितंबर को लालबर्रा बंद का आव्हान किया है। बंद के साथ ही पूरे नगर में विशाल धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन कर शासन-प्रशासन के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज करवाया जायेगा। आदिवासी समुदाय के पदाधिकारियों ने 3 सितंबर को लालबर्रा बंद को दुकानदारों, व्यापारियों से अपने-अपने प्रतिष्ठान बंद कर सहयोग करने की अपील की है। इस अवसर पर मृत बच्चों को श्रध्दांजली अर्पित की जायेगी और स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति विरोध प्रदर्शन किया जायेगा।

प्रशासनिक लापरवाही से बनी गंभीर स्थिति

म.प्र. आदिवासी विकास परिषद लालबर्रा के पदाधिकारियों ने बताया कि बिरसा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से बच्चे अज्ञात बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। साथ ही यह भी आरोप लगाया है कि बार-बार गुहार लगाने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की ओर से रोकथाम के लिए कोई ठोस या प्रभावी कदम नहीं उठाये जा रहे है। प्रशासन की इस उदासीनता के कारण मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे समूचे आदिवासी समाज में गहरा आक्रोश और भय का माहौल है। आगे बताया कि लगातार बच्चों की हो रही मौतों और प्रशासन की नींद न खुलने के विरोध में यह कदम उठाना पड़ा है। 3 सितंबर को बालाघाट जिला के साथ ही लालबर्रा भी बंद रहेगा। इस बंद को सफल बनाने के लिए स्थानीय व्यापारियों, बस संचालकों और आम जनता से समर्थन की अपील की गई है। वहीं 3 सितंबर की सुबह से ही लालबर्रा के मुख्य बाज़ारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और परिवहन सेवाओं पर इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है। आदिवासी समाज की प्रमुख मांग है कि बिरसा क्षेत्र में तत्काल विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भेजकर बच्चों की मौतों के सही कारणों का पता लगाये जाये, प्रभावित गांवों में आपातकालीन स्वास्थ्य शिविर लगाकर हर बच्चे की जांच और मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त दंडात्मक कार्यवाही, मृत बच्चों के परिजनों को तत्काल उचित आर्थिक मुआवजा प्रदान करने की मांग की है। वहीं समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों का कहना है कि यदि बंद और धरना प्रदर्शन के बाद भी शासन-प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाये तो इस आंदोलन को राज्य स्तर पर और अधिक उग्र किया जायेगा।

आज लालबर्रा रहेगा बंद - अनिल

म.प्र. आदिवासी विकास परिषद लालबर्रा के सचिव अनिल उइके ने बताया कि बिरसा तहसील के वनांचल गांवों में कुछ महीनों से आदिवासी बच्चों की दूषित पानी या फिर अज्ञात बीमारी के चलते लगातार मौते हो रही है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग बीमारी की रोकथाम नही कर पा रही है, जिससे आदिवासी समाज में आक्रोश व्याप्त है। श्री उइके ने बताया कि 3 सितंबर को आदिवासी समाज, एसटी, एससी, ओबीसी के द्वारा बालाघाट जिला बंद का आव्हान किया गया है। इसी कड़ी में लालबर्रा भी 3 सितंबर को बंद का आव्हान किया गया है, इस बंद को लालबर्रा मुख्यालय के दुकानदार एवं व्यापारियों से अपील की गई है कि वे अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर बिरसा विकासखंड में जिन बच्चों की अज्ञात बीमारी के चलते मौत हुई है उन्हे श्रध्दांजली अर्पित करने एवं विरोध प्रदर्शन में सहयोग करें। सरकार से मांग है कि बिरसा क्षेत्र के वनग्रामों की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करें और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही करें।

महाविद्यालय में भगवान बलराम जयंती कार्यक्रम का हुआ आयोजन

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार भारतीय ज्ञान परम्परा प्रकोष्ठ के अन्तर्गत नगर मुख्यालय स्थित शासकीय महाविद्यालय में 2 सितंबर को भगवान बलराम जयंती मनाई गई। यह कार्यक्रम प्रभारी प्राचार्य डॉ. देवराज चौरे की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। जिसमें सर्वप्रथम उपस्थितजनों ने माँ सरस्वती, भगवान बलराम के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। भगवान बलराम की जयंती पर उनके जीवनलीलाओं के बारे में विद्यार्थियों को विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी डॉ. प्रदीपकुमार भिमटे ने भगवान बलराम जी के जीवन वृत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भगवान बलराम भारतीय कृषक समाज के आराध्य देवता है जिनकी पूजा हरछट के रूप में की जाती है। डॉ. निर्मल कीर्ति गेडाम अपने व्याख्यान में भगवान बलराम के जन सामान्य और कृषकों के लिए किये गये कार्यो के बारे में जानकारी प्रदान की। प्रभारी प्राचार्य डॉ. देवराज चौरे ने विद्यार्थियों को भगवान बलराम जी को शौर्य और साहस का प्रतीक बताया और कहा कि बलरामजी बल, धर्म और कृषि के प्रतीक है। भगवान बलराम जयंती कार्यक्रम का मंच संचालन डॉ. कामाक्षा बिसेन एवं आभार प्रदर्शन भारतीय ज्ञान परम्परा का प्रकोष्ठ प्रभारी नरेश सौलखे के द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्राध्यापक सुमन बरवा, डॉ. सुरेन्द्रकुमार खण्डायत, डॉ. ऋषिकेष पटेल, श्रीमती संध्या भलावे, मनीष शिवहरे, श्रीमती अनिभा शरणागत, डॉ. आशा कारे, पीतम मुरते, यादोराव राजुरकर, व्यंकट नगपुरे, श्रीमती सरिता ऐड़े, लकेश गेड़ाम, रामदयाल मथारे, श्रीमती वंदना कुर्वे, मिनेश पंचेश्वर, प्रशिक हुमनेकर, निशांत तलवरे एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

मेहंदीवाड़ा में नल-जल योजना बेहाल ग्रामीण परेशान

ग्रामीणों का पंचायत एवं विभाग पर अनदेखी, कार्य में लापरवाही का आरोप

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। वारासिवनी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मेहंदीवाड़ा में शासन की महत्वाकांक्षी नल जल योजना विभागीय लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। हर घर नल, हर घर जल का नारा यहाँ पूरी तरह खोखला साबित हो रहा है। आलम यह है कि गाँव के कई हिस्सों में योजना का पानी पहुँच ही नहीं रहा है ,वहीं निर्माण एजेंसी के द्वारा पाइपलाइन बिछाने के नाम पर की गई अधूरी खुदाई ने बारिश के मौसम में रास्तों को जर्जर कर दिया है। इस अव्यवस्था से परेशान और आक्रोशित ग्रामीणों ने पंचायत एवं संबंधित विभाग पर भारी अनदेखी का आरोप लगाया है।

बिना तैयारी के काम और दोषपूर्ण एस्टीमेट

प्राप्त जानकारी के अनुसार मेहंदीवाड़ा की मुख्य बस्ती में लाखों रुपये की लागत से नल जल योजना स्वीकृत की गई थी। आरोप है कि शुरुआत में विभाग के द्वारा बिना किसी व्यवस्थित सर्वे के मात्र अनुमानित एस्टीमेट के आधार पर काम शुरू करा दिया गया। योजना के तहत पानी की टंकी का निर्माण तो कर दिया गया लेकिन ना तो पुरानी जर्जर पाइपलाइन को बदला गया और ना ही गाँव में नई पाइपलाइन का उचित विस्तार किया गया। नतीजतन टंकी का सुचारू संचालन नहीं हो सका और ग्रामीण पानी की बूंद बूंद को तरसते रहे। योजना की विफलता को देखते हुए विभाग ने बचे हुए काम को पूरा करने के लिए एक रिवाइज्ड एस्टीमेट तैयार किया। इसके तहत नई पाइपलाइन बिछाई जानी थी लेकिन निर्माण कंपनी ने भरी बरसात के बीच बस्ती के अंदर और नदी की ओर जाने वाले रास्तों पर खुदाई शुरू कर दी। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जगह जगह गड्ढे खोदकर और आधा अधूरा पाइप डालकर काम को बीच में ही रोक दिया गया है। इससे आवागमन के लायक बचे रास्ते भी कीचड़ में तब्दील हो गए हैं और ग्रामीणों का पैदल चलना तक मुहाल हो गया है। लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद नल जल योजना का लाभ नही मिलने से ग्रामीण आज भी कुओं और अन्य पारंपरिक जल स्त्रोतों से पानी ढोने को मजबूर हैं। अपनी इन दैनिक समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने कई बार ग्राम पंचायत और संबंधित विभाग से शिकायत की लेकिन अब तक जिम्मेदारों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है और उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द अधूरे कार्य को पूर्ण कर सभी घरों तक पानी पहुँचाया जाए और खोदे गए रास्तों को दुरुस्त किया जाए।

ग्रामवासियों को नही मिल रहा नल जल योजना से पानी ग्रामीणों में आक्रोश-राजू लिमजे

राजू लिमजे ने बताया की गांव में नल जल योजना का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है कहीं पानी मिल रहा है कहीं पानी नहीं मिल रहा है। जगह.जगह खोदकर रख दिया गया है वहां मलमा भी भर गया है गांव वालों को समस्या हो रही है क्योंकि हर गली में नाली खोदी गई है। नल वाला हिस्सा बुझ गया है पाइप तो लगा दिए हैं पर समस्या यह है कि लोग अब नदी के घाट या अपने खेत बड़ी मुश्किल से जा रहे हैं। पहले जल्दी में योजना बनाए थे जिसमें कई काम छूट गए थे वह अब कर रहे हैं तो उसमें भी कहीं पानी मिला है कहीं नहीं मिला है। यह लोग नदी वाले कुएं या अन्य स्थानों से पानी ला रहे हैं यह पीएचई काम कर रही है पर पंचायत का भी ध्यान नहीं है। ढेकेदार के आदमी दो दिन आते हैं १५ दिन काम बंद रहता है ऐसा रुक.रुक कर चल रहा है हर कोई परेशान है।

इनका कहना है

नई नल जल योजना की मोटर जल गई थी तो मिस्त्री नहीं आया बोर भी बैठ गया तो मशीन की जरूरत थी। पहले जो योजना का एस्टीमेट कैसा बना है तो पता नहीं अभी फि र एक दूसरा एस्टीमेट बना है। बरसात में काम चालू हुआ है पुरानी पाइपलाइन से अभी हम पानी दे रहे हैं और साफ सफाई की व्यवस्था कर रहे हैं।

किशोर तामेश्वर
सरपंच प्रतिनिधि मेहंदीवाड़ा

प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज़ साधना भवन में आध्यात्मिक उल्लास से मनाया रक्षाबंधन पर्व

पवित्रता प्रेम और नैतिक मूल्यों को अपनाने का लिया संकल्प

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थानीय सेवाकेंद्र साधना भवन में रक्षाबंधन का पावन पर्व अत्यंत आध्यात्मिक उल्लास, अलौकिक प्रेम एवं शांतिपूर्ण

वातावरण में गरिमामय ढंग से संपन्न हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र के अनेक भाई बहनों ने सहभागिता कर आध्यात्मिक ऊर्जा एवं भाईचारे की भावना का अलौकिक अनुभव किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से उपस्थित बी के उर्वशी दीदी ने सभी उपस्थित भाई.बहनों को मंगलमय रक्षासूत्र बांधकर इस पावन पर्व के सच्चे आध्यात्मिक महत्व से अवगत कराया। बी के उर्वशी दीदी ने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व केवल स्थूल रूप से भाई बहन के पवित्र रिश्ते तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वयं को विकारों, नकारात्मक विचारों और सामाजिक बुराइयों से सुरक्षित रखने का एक दृढ़ आध्यात्मिक संकल्प है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में समाज को आपसी प्रेम, सद्भाव, शांति और उच्च नैतिक मूल्यों की परम आवश्यकता है। सच्चा रक्षाबंधन तब सिद्ध होता है जब हम अपने मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों की बलि देकर जीवन में पवित्रता, सकारात्मकता और शांति को स्थान देते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने दीदी से रक्षासूत्र बंधवाकर अपने जीवन में श्रेष्ठ एवं सकारात्मक संकल्पों को धारण करने का वचन लिया। ब्रह्मकुमारी बहनों ने इस बात पर जोर दिया कि रक्षाबंधन का यह पावन अवसर हमें स्वयं के भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाने और समाज में विश्व बंधुत्व तथा शांति का संदेश प्रसारित करने की प्रेरणा देता है। पूरे आयोजन के दौरान साधना भवन का प्रांगण आध्यात्मिक तरंगों, शांति और असीम भाईचारे की भावना से सराबोर रहा। अंत में सभी उपस्थित भाई.बहनों ने गहन योग और ध्यान के माध्यम से परमपिता परमात्मा की आध्यात्मिक शांति का प्रत्यक्ष अनुभव किया।

हलषष्ठी पर्व पर माताओं ने रखा संतान की दीर्घायु का व्रत

महिलाओ ने पूजा-अर्चना कर मांगी सुख समृद्धि

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। नगर सहित संपूर्ण अंचल में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर २ सितंबर को हलषष्ठी हल छठ का पावन पर्व अपार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर माताओं ने निर्जला व्रत धारण कर अपनी संतान के दीर्घायु जीवन, उत्तम स्वास्थ्य और प्रगति की भगवान शिव एवं माता पार्वती से कामना की।

विधि विधान से हुआ पूजन और कथा का वाचन

पर्व के दौरान नगर के विभिन्न वार्डों और ग्रामीण इलाकों में महिलाओं ने अपने अपने घरों के आंगन में सामूहिक रूप से एकत्र होकर पूजन स्थल सजाया। पूजन सामग्री के रूप में पलाश के पत्ते, कुश की कांडी, महुआ की डालियों सहित ६ प्रकार की लाही, चना और बटरा , मटर जैसी वस्तुएं विशेष रूप से अर्पित की गईं। माताओं ने पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद हलषष्ठी व्रत कथा का श्रवण किया, तत्पश्चात आरती उतारकर प्रसाद वितरित किया गया। मान्यता हैं की हलषष्ठी का व्रत संतान रक्षा और उनकी उन्नति के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं हल से जुते हुए किसी भी अनाज का सेवन नहीं करती हैं। धार्मिक मान्यताओं में इस व्रत का संबंध महाभारत काल की पौराणिक कथाओं से भी जोड़ा जाता है। नगर के लगभग हर क्षेत्र में महिलाओं ने एकल अथवा सामूहिक रूप से इस धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न कराया। पड़ोस की महिलाओं ने एक साथ बैठकर भजन कीर्तन और पूजन में सहभागिता निभाई। दिनभर चले इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान समूचे वारासिवनी क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना रहा।

व्रत में माता पार्वती भगवान शिव की पूजा की जाती है -ममता सोलंकी

ममता सोलंकी ने बताया कि हम सभी महिला एकत्रित होकर हलषष्ठी की पूजा कर रहे हैं। यह पूजा बच्चों की लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य की कामना से की जाती है। जिसमें महिलाएं सुबह से व्रत धारण करती है और उसके बाद पलाश और कुश सहित अन्य सामग्रियों से पूजा सजाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस व्रत से बच्चे समझदार होते हैं इसमें हल और नागर से जूता हुआ अनाज का भोजन नहीं किया जाता है, पसोड के चावल जो तालाब में होते है उसी का भोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा है जिसके लिए हर महिला हलषष्ठी व्रत धारण कर पूजा अर्चना करती है। इस दौरान २४ घंटे का उपवास रखा जाता है इसमें पसोड के चावल का भोजन करते हैं। २४ घंटे बाद ही इसी व्रत को तोड़ते हैं इस दौरान खेत में कदम नहीं रखते हैं। इस व्रत में माता पार्वती भगवान शिव की पूजा की जाती है।

भाजपा आरंभा मण्डल की आवश्यक कामकाजी बैठक सम्पन

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। वारासिवनी विधानसभा के अंतर्गत भाजपा मंडल आरंभा की कामकाजी महत्वपूर्ण बैठक ग्राम आरंभा में रमेश जैतवार के निवास पर संपन्न हुई । इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष किशोर अमूले ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा आधारित राजनीतिक दल है।राष्ट्र प्रथम की अवधारणा हमारे सिद्धांतों में शामिल है। हम सभी परिवारए वंशए जाति से परे प्रथम राष्ट्रए द्वितीय दलए उसके बाद स्वयं की भावना से कार्य करते हैं। भाजपा का विजय मंत्र हैए बूथ जीतो चुनाव जीतो ए हमे सभी बूथों की संरचना पूर्ण कर बूथ पर ही सभी कार्य करना है। जिसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से हमे सभी बूथों पर एक साथ बैठने का मौका मिलता हैं।यह अनिवार्य है कि हम आपस मे संवाद करे और माह के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री के साथ एक बार पारिवारिक रूप से एक साथ एक स्थान पर बैठे। इस बैठक में भाजपा जिला उपाध्यक्ष किशोर अमूले, भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य संतोष आड़े , रमेश जैतवार,ललित ठाकुर,कैलाश नगपुरे, तिवारीलाल लिल्हारे, रमेश नगपुरे, मनजीत सिंह परमार, मानसिंह बिसेन, नरेंद्र ठाकरेले, रेखलाल लिल्हारे,पवन डहारे,संतोष पेंढारकर,युवराज कावरे,दशरथ कावडे,धनेंद्र बंसोड, सुखचंद जैतवार, सोहनलाल डहाके,देवीलाल पटले,मुकेश लिमजे, मोहित सिंह राजपूत, महेश टेंभरे, विवेक वाटकर,भावनलाल बिसेन,रमेश ठाकुर, कुंवरलाल, मकरध्वज बिसेन, कन्हैयालाल बघेले सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

राजा भोज महाविद्यालय में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम आयोजित

विद्यार्थी जीवन में शिक्षा के साथ कौशल और व्यक्तित्व विकास पर दें ध्यान- गौरव पारधी

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। राजा भोज शासकीय महाविद्यालय कटंगी में सत्र २०२६-२७ के स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के नवप्रवेशित छात्र छात्राओं के लिए प्रवेश उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं महाविद्यालय जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष,कटंगी खैरलांजी विधायक गौरव सिंह पारधी शामिल हुए। उन्होंने मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर महाविद्यालय परिवार द्वारा विधायक गौरव पारधी सहित उपस्थित अतिथियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। गौरव पारधी ने नवप्रवेशित विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए कहा कि महाविद्यालय में प्रवेश उनके जीवन की नई शैक्षणिक यात्रा की शुरुआत है। उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ

कौशल एवं व्यक्तित्व विकास पर ध्यान देने तथा शासन की छात्र हितैषी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासन एवं परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का आह्वान किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। महाविद्यालय के प्राचार्य अनिल कुमार शेण्डे ने नवप्रवेशित विद्यार्थियों को छात्र जीवन की गरिमा बनाए रखने तथा महाविद्यालयीन जीवन की नई चुनौतियों का सजगता एवं अनुशासन के साथ सामना करने के लिए प्रेरित किया। सुश्री कविता अहिगारे ने नई शिक्षा नीति एवं नवीन विषय पाठ्यक्रमं के संबंध में विद्यार्थियों को आवश्यक जानकारी दी। कार्यक्रम प्रभारी डा कुसुमलता उइके ने नवप्रवेशित विद्यार्थियों का अभिनंदन करते हुए विद्यार्थी जीवन में संघर्ष,अनुशासन एवं सफलता के महत्व पर विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में अनुज अग्रवाल, टेलेन्द्र बाघमारे,वैभव गुप्ता,विशाल कोठारी, टी पी बिसेन,संदीप शर्मा,अधीर कुमार घोडेश्वर सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

आजादी के बाद से ग्राम कायदी में प्रशासन ने नहीं बनाई पक्की सड़क

ग्रामीणों की मांग पर विधायक पटेल ने निधि से दिया १५ लाख रुपए

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। वारासिवनी ग्रामीण क्षेत्रों में खस्ताहाल व गड्ढों से भरी सड़को के कारण स्कूली बच्चों,राहगीरो और वाहन चालकों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आजादी के बाद से ग्रामीणों ने प्रशासन और पूर्व मंत्री से लगातार पक्की सड़क बनवाने मांग की थी। मगर किसी ने भी ग्रामीणों की मांग पर ध्यान नहीं दिया। समय समय पर ग्रामीणों ने प्रशासन को भी चेताया,मगर प्रशासन भी कोई हल नहीं निकाल पाया। बुधवार को जनपद सदस्य जितेंद्र सिंह राजपूत और स्व. प्रमोद सिंह बाटे के पुत्र डॉक्टर अभिजीत बाटे ग्राम वासियों के साथ विधायक जनसंपर्क कार्यालय पहुंचे और विधायक विवेक पटेल को ग्राम की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया और ग्राम पंचायत कायदी में पीपल पेड से नेवारे के मकान तक तत्काल पक्की सड़क बनवाने की मांग की। विधायक विवेक पटेल ने ग्रामीणों की लगातार मांग और जर्जर सड़क की समस्याओं को देखते हुए तत्काल १५ लाख रुपयों की स्वीकृति प्रदान की है। ग्राम वासियों ने विधायक विवेक पटेल का आभार जताया है।

दिव्या के इस्तीफे को विपक्ष का हथियार नहीं बनने देगी सरकार!

आप जानते हैं कि यूपीएससी परीक्षा पास करने के लिए हर साल तेरह लाख से अधिक बच्चे तैयारी करते हैं हर साल भारत में लगभग 11 लाख से 13 लाख छात्र यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं। यानि हर साल औसतन 11 से 13 लाख उम्मीदवार फॉर्म भरते हैं।प्रारंभिक परीक्षा में इनमें से लगभग 50ल से 55ल छात्र ही (यानी करीब 5 से 6 लाख) वास्तव में परीक्षा देने आते हैं।मुख्य परीक्षा- प्रारंभिक परीक्षा पास करके लगभग 14,000 से 15,000 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा तक पहुँचते हैं। इसके बाद लगभग 2,500 से 3,000 छात्र साक्षात्कार के लिए चुने जाते हैं। आखिर में लगभग 800 से 1,000 उम्मीदवारों का चयन अंतिम सूची में होता है।दर्जनों अभ्यर्थी हर साल इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने असफल रहने या बार बार असफल होने पर अवसाद ग्रस्त होकर कई बार सुसाइड तक कर लेते हैं। यह सब बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जिस भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होने के लिए करीब पंद्रह लाख युवा हर साल सपना देखते हैं दिन रात भूख- प्यास त्यौहार - उत्सव सब की चकाचौंध से किनारा कर सिर्फ एक नियुक्ति पाना जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं लेकिन यदि कोई भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी जिसकी 17 साल सेवा बाकी हो जिनको कई पदोन्नति भी मिल सकती है पूरे होशो हवास में सिर्फ तेरह साल की सर्विस कर प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दे तो इसे किस तरह देखा जाएगा? यूपी कैडर की 2013 बैच की आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने रविवार 30 अगस्त 2026 को प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया। वर्तमान समय में वह राजस्व विभाग में विशेष सचिव पद पर तैनात थीं। दिव्या मित्तल ने बाद सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट लिखकर अपने इस्तीफे की जानकारी शेयर की।इस्तीफे से सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस गंभीर मामले में राज्यपाल को पत्र लिखकर अधिकारियों के सम्मान की रक्षा की मांग की है। आपको बता दें कि मिर्जापुर और देवरिया की जिलाधिकारी रह चुकीं दिव्या मित्तल अपने कार्यकाल और जनसरोकार से जुड़े कामों को लेकर चर्चा में रही हैं। आप जानते हैं कि सिर्फ शोहरत और दौलत हासिल कर लेना ही की बार व्यक्ति की आत्मसंतुष्टि नहीं कर पाता है। दरअसल जिसको हासिल नहीं होता है वह खोजने पाने के लिए बेचैन हो जाता है लेकिन जिसे हासिल होता है उसे वह प्राप्त भी कई बार मिथ्या नज़र आता है। दिव्या मित्तल पहले उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जिलाधिकारी रह चुकी हैं। मई के पहले सप्ताह में उन्हें देवरिया के जिलाधिकारी पद से हटाकर राजस्व विभाग में तैनाती दी गई थी। डीएम पद से हटाए जाने के बाद उनकी कुछ सोशल मीडिया पोस्ट भी चर्चा में रही थीं। अब उनके इस्तीफे के बाद एक बार फिर उनकी कार्यशैली, पिछली तैनातियों और इस्तीफे की वजह को लेकर बहस शुरू हो गई है। फिलहाल इस्तीफे की असली वजह क्या है, इस पर दिव्या मित्तल की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने बीते रविवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देने की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी थी। हालांकि, उन्होंने अपने इस्तीफे की कोई वजह नहीं बताई। इसके बाद सोशल मीडिया से लेकर यूपी की सियासत तक उनके इस फैसले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।

विधिक मापविज्ञान (भारतीय मानक समय) नियम, 2026 ने खोला एक राष्ट्र, एक समय का नया अध्याय!

डिजिटल भारत की नई समय -क्रांति, अब पूरे देश की घड़ी होगी एक! -समग्र व्यापक विश्लेषण

वैश्विक स्तरपर आज का भारत तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी,डिजिटल अर्थव्यवस्था और आधुनिक संचार व्यवस्था के दौर से गुजर रहा है। कभी देश में एक राष्ट्र, एक चुनाव,एक राष्ट्र, एक कर,एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड एक राष्ट्र,एक ग्रिड,एक राष्ट्र, एक बाजार,एक राष्ट्र, एक कानून/समान नागरिक संहिता यानें यूनिफार्म सिविल कोड यानी समान नागरिक कानून की बहस/प्रस्ताव।एक राष्ट्र एक समय,पूरे देश की महत्वपूर्ण आधिकारिक और तकनीकी प्रणालियों के लिए आईएसटी को साझा समय-संदर्भ बनाना,जैसी अवधारणाओं पर चर्चा होती है,इसी व्यापक सोच की अगली महत्वपूर्ण कड़ी अब एक राष्ट्र, एक समय के रूप में सामने आ रही है। इसका सीधा अर्थ है कि भारत में कानूनी,प्रशासनिक, व्यावसायिक और महत्वपूर्ण तकनीकी कार्यों के लिए भारतीय मानक समय यानी आईएसटी को एक समान आधिकारिक समय-संदर्भ बनाया जाएगा।सुनने में यह केवल घड़ी का समय एक करने जैसा लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह भारत की डिजिटल और तकनीकी व्यवस्था को अधिक सुरक्षित,सटीक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह चाहूंगा कि सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भारत में समय की आधिकारिक व्यवस्था क्या है। देश में भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम (आईएसटी) लागू है,जो पूरे भारत के लिए एक ही आधिकारिक समय है।सामान्य जीवन में हम मोबाइल,कंप्यूटर,घड़ी या टीवी पर यही समय देखते हैं। लेकिन आधुनिक डिजिटल व्यवस्था में केवल घंटे और मिनट महत्वपूर्ण नहीं हैं। बैंकिंग लेन-देन, शेयर बाजार, इंटरनेट नेटवर्क,रेलवे सिग्नल, बिजली ग्रिड, डिजिटल भुगतान और सरकारी सर्वर जैसी प्रणालियों में सेकंड के छोटे हिस्से तक का समय महत्वपूर्ण हो सकता है। किसी डिजिटल लेन-देन का सही समय दर्ज होनाकई बार यह तय करता है कि भुगतान पहले हुआ या बाद में, आदेश कब दिया गया या किसी सिस्टम में कोई घटना ठीक किस समय हुई।टेलीकॉम ऑपरेटरों (जैसे बीएसएनएल, जिओ,एयरटेल) को अपने सर्वर्स और नेटवर्क टावरों को भारतीय परमाणु घड़ियों (एटॉमिक क्लॉक्स) के समय के साथ सिंक करना होगा।सटीक बिलिंग- डेटा उपयोग और कॉलिंग की समय-सीमा आधारित बिलिंग में ग्राहकों को अधिक पारदर्शिता मिलेगी। साथियों, इसी आवश्यकता को देखते हुए उपभोक्ता मामले विभाग ने 27 अगस्त 2026 को विधिक मापविज्ञान (भारतीय मानक समय) नियम, 2026 की अधिसूचना जारी की है। इन नियमों का उद्देश्य देशभर में कानूनी, प्रशासनिक,व्यावसायिक और अन्य आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भारतीय मानक समय को एक समान समय - संदर्भ के रूप में स्थापित करना है। नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 180 दिन बाद लागू होंगे।यह 180 दिनों की अवधि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार,कंपनियों,संस्थानों और तकनीकी प्रणालियों को अपने सर्वर,नेटवर्कसॉफ्टवेयर और समय-संबंधी व्यवस्थाओं में आवश्यक बदलाव करने का अवसर मिलेगा। साथियों, एक राष्ट्र,एक समय की जरूरत आज इसलिए बढ़ गई है क्योंकि भारत अब केवल भौतिक अर्थव्यवस्था नहीं रहा।देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्साडिजिटल नेटवर्क पर चलता है।एक व्यक्ति अपनेमोबाइल से कुछ सेकंड में दूसरे शहर में पैसा भेज सकता है। शेयर बाजार में हजारों लेन-देन अत्यंत कम समय में हो सकते हैं। बैंक के सर्वर देश के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद हो सकते हैं। मोबाइल नेटवर्क लाखों उपकरणों को एक साथ जोड़ते हैं।बिजली ग्रिड लगातार उत्पादन और खपत का संतुलन बनाए रखते हैं। रेलवे और विमानन व्यवस्था समय के बेहद सटीक तालमेल पर निर्भर करती है। ऐसे में यदि अलग-अलग प्रणालियां अलग-अलग समय स्रोतों पर निर्भर हों और उनमें सूक्ष्म अंतर हो, तो डिजिटल रिकॉर्ड और विभिन्न प्रणालियों के बीच समन्वय प्रभावित हो सकता है।यही कारण है कि एक समान समय-संदर्भ केवल घड़ी मिलाने का मामला नहीं है, बल्कि डिजिटल भारत की आधारभूत संरचना को मजबूत करने का विषय है। बैंकिंग और डिजिटल भुगतान में प्रत्येक लेन-देन का टाइम- स्टैम्प महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति के खाते से पैसा कट गया लेकिन सामने वाले खाते में राशि कुछ देर बाद दिखाई दी, तो दोनों प्रणालियों में दर्ज समय की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।एक विश्वसनीय और समान समय व्यवस्था ऐसे तकनीकी विवादों के समाधान को बहुत अधिक सटीकता से व्यवस्थित बना सकती है। साथियों इसका असर शेयर बाजार परिवहन व दूर संचार पर भी महत्वपूर्ण हो सकता है। आधुनिक शेयर बाजार में हजारों और लाखों ऑर्डर बहुत कम समय में दर्ज होते हैं। किस ऑर्डर को पहले दर्ज किया गया,किस समय कारोबार हुआ और किसी विशेष गतिविधि का टाइम- स्टैम्प क्या था,ये सभी बातें बाजार की पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण हैं।भारतीय मानक समय पर आधारित अधिक सटीक समय-सिंक्रोनाइजेशन से वित्तीय बाजारों में रिकॉर्डिंग और निगरानी की व्यवस्था मजबूत हो सकती है।परिवहन क्षेत्र में भी इसका महत्व कम नहीं है। रेलवे में सिग्नलिंग, ट्रेन संचालन और समय- सारणी के लिए सटीक समय जरूरी है। हवाई अड्डों पर उड़ानों, सुरक्षा प्रक्रियाओं और विभिन्न परिचालन गतिविधियों का समन्वय समय के आधार पर होता है। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ट्रकों, मालगाड़ियों और अन्य परिवहन माध्यमों की वास्तविक समय में निगरानी की जाती है। इसलिए समान और विश्वसनीय समय-संदर्भ सप्लाई चेन को अधिक प्रभावी बनाने में मदद कर सकता है।दूरसंचार और इंटरनेट की दुनिया में समय-सिंक्रोनाइजेशन और भी महत्वपूर्ण है। मोबाइल नेटवर्क के अलग-अलग टावरों और नेटवर्क उपकरणों को एक- दूसरे के साथ तालमेल बनाकर काम करना पड़ता है। डेटा सेंटर और कंप्यूटर नेटवर्क भी समय के सटीक रिकॉर्ड पर निर्भर करते हैं। यही कारण है कि भारत में अपने विश्वसनीय समय-स्रोतों का विकास रणनीतिक महत्व रखता है।भविष्य में महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए विदेशी समय-स्रोतों पर निर्भरता कम करना भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत कर सकता है। साथियों, इसी संदर्भ में भारत की स्वदेशी उपग्रह प्रणाली नाविक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। नाविक भारत की क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है, जिसे इसरो ने विकसित किया है। उपग्रह-आधारित प्रणालियों से सटीक समय-संदर्भ प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ भारत अपने वैज्ञानिक और मेट्रोलॉजी संस्थानों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर सटीक भारतीय मानक समय के प्रसार का बुनियादी ढांचा विकसित कर रहा है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण प्रणालियों को विश्वसनीय भारतीय समय-स्रोत उपलब्ध कराना है।इसी दिशा में वाइट रैबिट तकनीक भी महत्वपूर्ण है।सरल भाषा में समझें तो यह अत्यंत सटीक नेटवर्क टाइम- सिंक्रोनाइजेशन तकनीक है, जो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के माध्यम से बहुत छोटे समय-अंतर को भी मापने और नियंत्रित करने में सक्षम है। जुलाई 2026 में बेंगलुरु स्थित क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला में वाइट रैबिट आधारित भारतीय मानक समय प्रसार प्रदर्शन नेटवर्क का शुभारंभ किया गया। इसके माध्यम से बैंकिंग, दूरसंचार, बिजली, परिवहन और डिजिटल गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में आईएसटी के सुरक्षित और सटीक प्रसार की क्षमता का सटिका से प्रदर्शन किया गया। साथियों बिजली क्षेत्र में भी एक राष्ट्र, एक समय का प्रभाव दिखाई देगा। भारत का बिजली ग्रिड विशाल और जटिल है। अलग-अलग क्षेत्रों में बिजली उत्पादन, वितरण और खपत को लगातार संतुलित करना पड़ता है। ग्रिड के विभिन्न हिस्सों से आने वाले डेटा को सही समय के साथ रिकॉर्ड करना आवश्यक है। सटीक समय- सिंक्रोनाइजेशन से बिजली व्यवस्था की निगरानी, समस्या की पहचान और ग्रिड संचालन में बेहतर समन्वय संभव हो सकता है।सरकारी और कानूनी रिकॉर्ड के लिए भी एक समान समय-संदर्भ महत्वपूर्ण है। सरकारी आदेश, डिजिटल दस्तावेज, आवेदन, लाइसेंस, भुगतान, रिकॉर्ड और विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं में समय दर्ज होता है। जब पूरे देश में आधिकारिक कार्यों के लिए एक समान भारतीय मानक समय का उपयोग होगा, तो रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित हो सकती है। आपातकालीन सेवाओं में भी समय का महत्व अत्यधिक होता है, जहां कुछ सेकंड या मिनट का अंतर महत्वपूर्ण परिणाम सटीकता से पैदा कर सकता है। साथियों हालांकि इस व्यवस्था को लागू करना केवल नियम जारी करने से पूरा नहीं होगा। अगले 180 दिन तकनीकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। सरकारी विभागों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, डेटा सेंटरों, दूरसंचार कंपनियों, परिवहन संस्थानों और अन्य महत्वपूर्ण संगठनों को अपनी वर्तमान समय-स्रोत व्यवस्था की समीक्षा करनी होगी। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके सर्वर,नेटवर्क उपकरण सॉफ्टवेयर और टाइम-सिंक्रोनाइजेशन प्रणालियां नए नियमों के अनुरूप हों। यही वह चरण होगा जहां एक राष्ट्र, एक समय की अवधारणा कागज से निकलकर वास्तविक डिजिटल बुनियादी ढांचे में दिखाई देगी। साथियों,भारत में एक राष्ट्र की अवधारणा के साथ कई क्षेत्रों में एकरूपता लाने की कोशिशें पहले भी हुई हैं। एक राष्ट्र, एक कर के रूप में जीएसटी ने अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को एक बड़े साझा ढांचे में लाने का प्रयास किया। एक राष्ट्र, एक चुनाव का विचार देश में चुनावों के समय और प्रक्रिया को एक साथ करने की बहस से जुड़ा है। इसी क्रम में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड ने लाभार्थियों को देश के अलग-अलग हिस्सों में खाद्यान्न सुविधा से जोड़ने की दिशा में काम किया। अब एक राष्ट्र, एक समय भौतिक नहीं बल्कि डिजिटल और तकनीकी एकरूपता का नया अध्याय खोलता है।इस पहल का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आधुनिक भारत में समय स्वयं एक डिजिटल संसाधन बन चुका है।पहले समय का मतलब केवल घड़ी की सुई था, लेकिन आज समय बैंकिंग रिकॉर्ड है, डिजिटल भुगतान का प्रमाण है।

-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी

दुनिया जब बुरे दौर में है तब भारत के आर्थिक उजाले

-ललित गर्ग

दुनिया आज जिस दौर से गुजर रही है, वह आर्थिक और सामरिक दोनों दृष्टियों से असाधारण चुनौतियों का दौर है। रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रभाव, पश्चिम एशिया में तनाव, अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा, वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता, आपूर्ति शृंखला में व्यवधान और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने दुनिया की बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के सामने कठिन प्रश्न खड़े कर दिए हैं। ऐसे समय में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस मजबूती का परिचय दिया है, वह केवल एक आर्थिक आंक?ा नहीं, बल्कि बदलते भारत की सामर्थ्य का प्रमाण है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की 7.8 प्रतिशत वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत को ऐसी उम्मीद के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसकी ओर दुनिया आश्चर्य और विश्वास दोनों के साथ देख रही है। इस विकास दर ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक शक्ति और आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी है एवं एक उजाला बिखेरा है। यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वृद्धि ऐसे समय दर्ज हुई है, जब परिस्थितियां सामान्य नहीं थीं। महंगाई, ऊर्जा संकट, भू-राजनीतिक तनाव और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उतार-च?ाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास पथ मजबूत बना रहा। पिछले वर्ष इसी तिमाही में विकास दर 6.9 प्रतिशत थी। यानी एक वर्ष में आर्थिक वृद्धि की गति में उल्लेखनीय सुधार दिखाई दिया है। घरेलू मांग की मजबूती, सरकारी पूंजीगत व्यय, विनिर्माण, निर्माण और निर्यात जैसे क्षेत्रों का योगदान इस प्रदर्शन के पीछे महत्वपूर्ण रहा है। आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ तभी समझ में आता है, जब उसे उसके वैश्विक संदर्भ में देखा जाए। आज दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं केवल आर्थिक नीतियों से प्रभावित नहीं हो रहीं, बल्कि युद्ध, कूटनीतिक तनाव, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक संबंध भी उनकी दिशा तय कर रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक एवं रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। पश्चिम एशिया का तनाव ऊर्जा बाजार और वैश्विक आपूर्ति तंत्र के लिए चिंता पैदा करता है। इन परिस्थितियों में भारत का अपेक्षाकृत तेज आर्थिक विकास यह संकेत देता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने लिए ऐसे मजबूत घरेलू आधार तैयार किए हैं, जो बाहरी झटकों को सहने की क्षमता रखते हैं। यही वह परिवर्तन है जो भारत को केवल एक बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में आगे ले जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका विशाल घरेलू बाजार है। करोड़ों उपभोक्ताओं की मांग, बढ़ता मध्यम वर्ग, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार, बुनियादी ढांचे पर निवेश और बदलती उपभोग संस्कृति ने अर्थव्यवस्था को आंतरिक गति प्रदान की है। जब वैश्विक बाजार अनिश्चित हों, तब घरेलू मांग अर्थव्यवस्था के लिए सुरक्षा-कवच का काम करती है। इसीलिए वर्तमान विकास दर में घरेलू मांग की मजबूती को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। इस आर्थिक प्रदर्शन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि वृद्धि केवल एक क्षेत्र के सहारे नहीं टिकी है। विनिर्माण क्षेत्र में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि इस बात का संकेत है कि भारत धीरे-धीरे उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लंबे समय तक भारत की अर्थव्यवस्था को मुख्यत: सेवा क्षेत्र की शक्ति के रूप में देखा जाता रहा, लेकिन अब देश में उत्पादन बढ़ाने, घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने और बुनियादी ढांचे के विस्तार की दिशा में किए गए प्रयासों से औद्योगिक क्षेत्र के लिए नई संभावनाएं पैदा हुई हैं। निर्माण क्षेत्र भी रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सड़कें, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, आवास, औद्योगिक गलियारे और डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश का प्रभाव केवल आर्थिक वृद्धि के आंकड़ों में नहीं दिखाई देता, बल्कि उससे भविष्य की आर्थिक क्षमता भी निर्मित होती है। भारत की वर्तमान आर्थिक यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनाई गई नीतियों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले वर्षों में सरकार ने बुनियादी ढांचे, डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन, विनिर्माण, नए उद्यम, आत्मनिर्भरता, ऊर्जा सुरक्षा और औपचारिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर लगातार जोर दिया है। जनधन खातों से लेकर डिजिटल भुगतान तक और राजमार्गों से लेकर रेलवे के आधुनिकीकरण तक, आर्थिक गतिविधियों का एक व्यापक तंत्र तैयार हुआ है। वस्तु एवं सेवा कर ने देश के बड़े बाजार को अधिक एकीकृत करने में भूमिका निभाई है। दिवाला एवं दिवालियापन संहिता जैसी व्यवस्थाओं ने कारोबारी वातावरण को अधिक व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं ने अनेक क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन और निवेश को बढ़ावा दिया है। इन नीतियों का वास्तविक मूल्यांकन केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि उनके परिणामों से होना चाहिए। सकल घरेलू उत्पाद के ताजा आंकड़े इस दिशा में एक सकारात्मक संकेत अवश्य देते हैं। आम नागरिक के लिए आर्थिक विकास का अर्थ तभी सार्थक है, जब उसके जीवन में रोजगार के अवसर बढ़ें, आय में वृद्धि हो, महंगाई नियंत्रित रहे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हों तथा जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार आए। सकल घरेलू उत्पाद हमें अर्थव्यवस्था की गति बताता है, लेकिन यह नहीं बताता कि उस विकास का लाभ समाज के विभिन्न वर्गों तक किस प्रकार पहुंच रहा है। इसलिए भारत की अगली चुनौती तेज विकास से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। आर्थिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी रोजगार है। विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र का विस्तार इसलिए आशाजनक है क्योंकि ये बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन भविष्य में भारत को ऐसे उद्योगों की आवश्यकता होगी, जो बड़ी संख्या में युवाओं को सम्मानजनक और स्थायी रोजगार दे सकें। भारत की युवा आबादी उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि उसे कौशल, शिक्षा, तकनीक और रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलते हैं तो यही युवा शक्ति भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की सबसे बड़ी ऊर्जा बन सकती है। भारत का लक्ष्य केवल आत्मनिर्भर बनना नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में नेतृत्वकारी भूमिका निभाना होना चाहिए। आत्मनिर्भरता का अर्थ दुनिया से अलग होना नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं को इतना मजबूत करना है कि भारत वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सके। आज दुनिया चीन के विकल्प के रूप में विभिन्न उत्पादन केंद्रों की तलाश कर रही है। भारत के पास विशाल बाजार, युवा मानव संसाधन, तकनीकी क्षमता और लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसी विशिष्ट ताकतें हैं। यदि भारत विनिर्माण, अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं में अपनी क्षमता बढ़ाता है, तो वह वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में कहीं अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है। 2047 का विकसित भारत केवल सरकार का संकल्प नहीं, बल्कि देशवासियों की सामूहिक आकांक्षा है। 7.8 प्रतिशत की विकास दर इस यात्रा में एक उत्साहजनक पड़ाव है, मंजिल नहीं। भारत को लगातार उच्च विकास दर, मजबूत वित्तीय व्यवस्था और स्थिर आर्थिक वातावरण के साथ-साथ बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उत्पादकता, कौशल विकास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर भी समान ध्यान देना होगा। भारत की आर्थिक कहानी अब केवल आंकड़ों की कहानी नहीं रह गई है। यह आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की कहानी बन रही है। दुनिया जब युद्ध और आर्थिक अस्थिरता की छाया में अपनी दिशा तलाश रही है, तब भारत का मजबूत आर्थिक प्रदर्शन उसे एक भरोसेमंद और संभावनाशील शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। 7.8 प्रतिशत की विकास दर निश्चित रूप से भारत के लिए गर्व का विषय है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि भारत ने यह संदेश दिया है कि वैश्विक संकटों के बीच भी उसकी आर्थिक बुनियाद मजबूत है।

युद्ध और टैरिफ के तूफान में भी भारत की अर्थव्यवस्था का बजा डंका

7.8 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि ने दुनिया को दिया भारत की आर्थिक ताकत का संदेश, सरकार की नीतियों और मजबूत कार्यप्रणाली का दिखा असर दुनिया इस समय आर्थिक और सामरिक अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद पैदा हुई वैश्विक परिस्थितियों ने पहले ही ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर रखा था। इसके बाद अमेरिका-ईरान तनाव और युद्ध ने वैश्विक बाजारों की चिंता बढ़ा दी। होर्मुज क्षेत्र में पैदा हुए संकट का असर तेल और समुद्री व्यापार पर पड़ा। भारत के आयात-निर्यात पर भी इसका दबाव महसूस किया गया। दूसरी ओर अमेरिका की ओर से भारत पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी और व्यापारिक दबाव ने परिस्थितियों को और चुनौतीपूर्ण बना दिया। इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जिस मजबूती का प्रदर्शन किया है, वह केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं बल्कि देश की आर्थिक क्षमता और नीतिगत स्थिरता का बड़ा संकेत है। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक के लगभग 7 प्रतिशत के अनुमान से भी बेहतर रहा। वैश्विक स्तर पर जब अनेक अर्थव्यवस्थाएं युद्ध, महंगाई, ऊर्जा संकट और व्यापारिक तनाव से जूझ रही हैं, तब भारत की अर्थव्यवस्था का इस गति से आगे बढ़ना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। भारत की इस आर्थिक तस्वीर को केवल बाजार की स्वाभाविक ताकत के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसके पीछे सरकार की लगातार बनाई गई आर्थिक रणनीति और उस रणनीति को जमीन पर लागू करने की कार्यप्रणाली भी महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने विकास का आधार केवल तत्काल राहत या उपभोग को नहीं बनाया, बल्कि बुनियादी ढांचे, सड़क, रेल, बंदरगाह, ऊर्जा, रक्षा, विनिर्माण और डिजिटल अर्थव्यवस्था में लगातार निवेश बढ़ाने पर जोर दिया है। यही पूंजीगत खर्च आज आर्थिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पहली तिमाही में सरकार के पूंजीगत खर्च में 18.6 प्रतिशत की वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि सरकार आर्थिक दबाव के समय भी विकास खर्च को रोकने के बजाय उसे आगे बढ़ाने की नीति पर कायम है। सरकार का यह दृष्टिकोण अर्थव्यवस्था के लिए दोहरा लाभ पैदा करता है। एक ओर बड़े स्तर पर निर्माण और आधारभूत ढांचे की परियोजनाओं से रोजगार और कारोबार को बढ़ावा मिलता है, वहीं दूसरी ओर सड़क, रेलवे, बिजली, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक ढांचे में सुधार से आने वाले वर्षों की आर्थिक क्षमता मजबूत होती है। भारत की अर्थव्यवस्था में सरकारी निवेश का असर निजी क्षेत्र की गतिविधियों पर भी दिखाई देता है। जब सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश करती है तो उससे सीमेंट, स्टील, मशीनरी, परिवहन, निर्माण और अनेक दूसरे क्षेत्रों में मांग पैदा होती है। इससे अर्थव्यवस्था में पैसा घूमता है और निजी क्षेत्र को भी विस्तार का अवसर मिलता है। यही कारण है कि वर्तमान आर्थिक वृद्धि को केवल सरकारी खर्च से जोड़ना उचित नहीं होगा। सरकार द्वारा तैयार किया गया वातावरण निजी निवेश और उपभोग दोनों के लिए आधार तैयार कर रहा है। आम लोगों की खपत भी आर्थिक वृद्धि का एक महत्वपूर्ण आधार बनी हुई है। पिछले वर्ष जीएसटी और आयकर से संबंधित राहतों के कारण लोगों के हाथ में खर्च करने योग्य आय बढ़ी। महंगाई की चुनौतियों के बावजूद उपभोक्ता मांग में अपेक्षित कमजोरी नहीं आई। इसका असर यात्री वाहनों की बिक्री में दिखाई दिया, जहां पहली तिमाही में 25.6 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज की गई। यह आंकड़ा बताता है कि घरेलू बाजार में उपभोक्ता विश्वास अभी भी मजबूत है। बिजली की मांग में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बिजली की मांग की वृद्धि दर 1.9 प्रतिशत से बढ़कर 8.4 प्रतिशत तक पहुंचना औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने का संकेत माना जा सकता है। जब उद्योग, सेवा क्षेत्र, निर्माण और घरेलू खपत में गतिविधियां बढ़ती हैं तो ऊर्जा की मांग भी बढ़ती है। इसलिए बिजली की मांग का यह आंकड़ा अर्थव्यवस्था की व्यापक गतिविधियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। सकल मूल्य वर्धित यानी जीवीए के आंकड़े भी भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती को रेखांकित करते हैं। पहली तिमाही में वास्तविक जीवीए वृद्धि 8.2 प्रतिशत रही, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 7.1 प्रतिशत थी। वहीं नॉमिनल जीवीए वृद्धि 11.5 प्रतिशत दर्ज की गई। नॉमिनल जीडीपी वृद्धि भी 8.1 प्रतिशत से बढ़कर 10.3 प्रतिशत हुई। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि आर्थिक गतिविधियों का विस्तार केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। सेवा क्षेत्र की मजबूती भी भारत की आर्थिक कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई 58.6 तक पहुंचना बताता है कि सेवा क्षेत्र में कारोबारी गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं। भारत लंबे समय से सेवा क्षेत्र की अपनी क्षमता के लिए दुनिया में पहचान रखता है। सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, डिजिटल सेवाओं, संचार, व्यापार और अन्य सेवा क्षेत्रों का विस्तार भारतीय अर्थव्यवस्था को लगातार नया आधार दे रहा है। सरकार की कार्यप्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उसने वैश्विक संकटों के बीच आर्थिक गतिविधियों को सामान्य बनाए रखने पर लगातार जोर दिया। रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान ऊर्जा और खाद्य बाजार में भारी उतार-चढ़ाव आया। बाद में पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा और समुद्री व्यापार तथा तेल आपूर्ति को लेकर चिंताएं पैदा हुईं। ऐसे समय में किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए आयात लागत और महंगाई को नियंत्रित रखना बड़ी चुनौती होती है। भारत ने ऐसी परिस्थितियों में आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए नीतिगत स्तर पर संतुलन साधने की कोशिश की। अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव भी भारत के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में आया। भारत पर भारी टैरिफ लगाने की धमकियों ने यह आशंका पैदा की कि इसका भारतीय निर्यात और औद्योगिक उत्पादन पर गंभीर असर पड़ सकता है। लेकिन भारत ने अपनी आर्थिक रणनीति को केवल किसी एक बाजार पर निर्भर नहीं रखा। निर्यात बाजारों के विविधीकरण, घरेलू मांग को मजबूत करने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने और विनिर्माण को प्रोत्साहन देने की दिशा में सरकार की नीतियां इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं। भारत की आर्थिक नीति में आत्मनिर्भरता का अर्थ दुनिया से अलग होना नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति मजबूत करना है। सरकार ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ विदेशी निवेश आकर्षित करने, विनिर्माण क्षमता बढ़ाने और रणनीतिक क्षेत्रों में देश की निर्भरता कम करने की दिशा में कदम उठाए हैं। रक्षा उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, मोबाइल निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में लगातार क्षमता निर्माण इसी सोच का हिस्सा है। आज भारत के सामने सबसे बड़ा अवसर यह है कि वैश्विक कंपनियां अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता चाहती हैं। यदि भारत इस अवसर को पूरी तरह भुना पाता है तो आने वाले वर्षों में विनिर्माण और निर्यात के क्षेत्र में उसकी भूमिका और मजबूत हो सकती है। इसके लिए सरकार की नीतिगत स्थिरता, तेज निर्णय लेने की क्षमता और परियोजनाओं को समय पर पूरा कराने की कार्यप्रणाली महत्वपूर्ण होगी। यह भी समझना जरूरी है कि 7.8 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि उत्सव का विषय जरूर है, लेकिन इसे अंतिम उपलब्धि नहीं माना जा सकता। भारत के सामने रोजगार सृजन, ग्रामीण मांग, महंगाई, निर्यात प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक व्यापार में बढ़ते संरक्षणवाद जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। इसलिए सरकार के सामने आगे भी यही चुनौती रहेगी कि आर्थिक वृद्धि को अधिक व्यापक बनाया जाए और उसका लाभ समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचे। फिर भी वर्तमान आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था ने बाहरी दबावों के सामने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है।

युद्ध हो, तेल संकट हो, वैश्विक व्यापार में तनाव हो या टैरिफ का दबाव— भारत की आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह पटरी से नहीं उतरीं। इसके पीछे मजबूत घरेलू बाजार, बढ़ता सरकारी पूंजीगत खर्च, सेवा क्षेत्र की क्षमता, सुधारों की निरंतरता और आर्थिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत आज विश्व शक्ति बनने की दिशा में केवल सामरिक या राजनीतिक आधार पर नहीं बढ़ रहा है। आर्थिक शक्ति किसी भी राष्ट्र की वैश्विक स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण आधार होती है। 7.8 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि इसी आर्थिक क्षमता का संकेत देती है। सरकार ने जिस तरह बुनियादी ढांचे, सउत्पादन, डिजिटल अर्थव्यवस्था, निवेश और घरेलू मांग को एक साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उसका परिणाम आर्थिक आंकड़ों में दिखाई देने लगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने संकटों के बीच अपनी गति बनाए रखने की क्षमता दिखाई है। दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता बनी हुई है और आगे भी अनेक चुनौतियां सामने आ सकती हैं। लेकिन यदि सरकार इसी तरह वित्तीय अनुशासन, पूंजीगत निवेश, नीतिगत स्थिरता और आर्थिक सुधारों के बीच संतुलन बनाए रखती है तो भारत की विकास यात्रा और तेज हो सकती है।

-कांतिलाल मांडोत

इंदौर बाजार भाव

इंदौर। एजेंसी। आयातित मालों की पड़तल ऊँची जाने से बुधवार को खाद्य तेलों में बाजार तेजी के रहे। तिलहनों में सोयाबीन बना रहा। दलहनों में चना पूर्वस्तर पर बना रहा। किराना जिंसों में शक्कर बाजार सुस्त रहे। सूखे मेवों में भी सुर्खी रही। व्यापारिक सूत्रों के अनुसार आयातित मालों में बनी तेजी के बाद खाद्य तेलों में बाजार सुर्ख है। अमेरिका-ईरान के मध्य जंग की ख़बरों के बाद आयातित मालों में बाजार चढ़ने लगे है। तिलहनों में सोयाबीन बाजार पूर्वस्तर पर रहे। दलहनों में चना 6600 रू. प्रति क्विटल पर मजबूत देखा गया। उधर, किराना जिंसों में शक्कर में नरमी रही। भाव इस प्रकार रहे-

किराना- शक्कर 4950-5150, खोपरा गोला 360-420, खोपरा बूरा 3200-6800 (15 कि.ग्रा.), जीरा राजस्थान 280-285, ऊंझा हल्का 290-295, बेस्ट 315-325, हल्दी निजामाबाद 230-250, सांगली 310-320, साबूदाना हल्का 5200-5350, मीडियम 5450-5600, बेस्ट 6000-6100, सच्चा मोती 5700, मोरधन 7200-8200, सौंफ मोटी 275-350, बेस्ट 350-400, सौंफ बारिक 180-300, एक्स्ट्रा बोल्ड 350-400, राई दाल 90-95, सरसो दाल 85-95, कालीमिर्च एटम 775-785, गारबल्ड 755-760, मटरदाना 800-900, खसखस अनक्लीन 1150-1250, क्लीन 1300-1350, दालचीनी 250-260, जायफल 725-750, वाद्यान फूल 405-600, शाहजीरा 350-400, तेजपान 90-100, पत्थर फूल 235-425, जावत्री 1675-1750, केसर 200-250, नाग केसर 925-975, सौंठ 325-500, धोली मूसली 1400-1600, लौंग 700-720, बेस्ट 760-790, हींग (वनदेवी 751) 3450, पाउच 10 ग्राम 3550, सिंघाडा छोटा 100-120, बड़ा 120-130, सिंदूर (25 कि.ग्रा. पैकिंग) 7300, देशी कपूर 850-860, बेस्ट 875-900, पूजा बादाम 115-125, बेस्ट 220-230, पूजा सुपारी 425-450, अरीठा 180-200, हरी इलायची शंकर 3500-3800, मीडि?यम 4000-4200, बेस्ट 4400-4600, एक्ट्रा बेस्ट 4600-4800, पानबार 3000-3500, बड़ी इलायची 1800-2100, तरबूज मगज 500-525, काजू (240) 940-960, काजू (320) 910-920, काजू डब्ल्यू (340) 850-870, काजू एस.डब्ल्यू (300) 850-900, काजू जे.एच. 840-870, टुकड़ी 780-820, बादाम मगज 1050-1200, सिंगापुरी 980-1025, बादाम टांच 700-725, अखरोट 590-850, अखरोट गिरी 1250-1550, जर्दालु 375-500, बेस्ट 550-650, किशमिश कंधारी 450-600, इंडियन 400-450, चारौली 1450-1750, मुनक्का 350-550, अंजीर 850-950, मखाना 900-1000, बेस्ट 1250-1300, खारक एवरेज 75-80, मीडियम 90-130, बेस्ट 140-260, पिस्ता पिशोरी 2900-3100, कंधारी 2500-2700, नमकीन पिस्ता 1000-1150, बेस्ट 1200-1250, गेहूँ आटा 1820, मैदा कट्टा 1850, रवा कट्टा 1880, बेसन 4675 (50 कि.ग्रा.), नारियल (120) 3200-3300, (160) 3900, (200) 4400, (250) 4800-5000,

तेल- सींगदाना 1710-1730, मुम्बई 1740, राजकोट तेलिया 2680, सोया साल्वेंट 1400-1405, सोया रिफाइंड 1465-1470, कपास्या 1610, धूलिया 1600, कड़ी 1600,

रात की धारणा- गुजरात लुज 1700, मुम्बई पाम 1505, मुम्बई सोया 1500,

खली- कपस्या खली (60 कि.ग्रा.) इन्दौर 2690, देवास-उज्जैन 2690, खंडवा-बुरहानपुर 2660, अकोला 3950 (प्रति क्विंटल)

तिलहन- सरसो 8000-8200, रायडा 7000-7200, सोयाबीन 6000, टोली (महुआ बीज) 5600-5800, करंज 4400-4500, अलसी 8500-9000, अरंडी 4500-4700, तिल्ली पुरानी 6500-7000, तिल्ली नई 7200-7500,

दलहन- चना कांटेवाला बेस्ट 6600, एवरेज 6500-6550, विशाल 6350-6400, महाराष्ट्र विशाल 5900-5950, काबूली चना डॉलर 7000-8300, काबूली चना रशियन 5600-5800, बिटकी 5200-5300, मसूर बेस्ट 6000, एवरेज 5850-5900, मूंग गर्मी बेस्ट नया 7000-7300, मूंग पुराना बोल्ड 7400-7600, मीडियम 7300-7400, तुअर निमाड़ी बेस्ट 7200-7400, एवरेज 6500-6600, हल्की 6400-6500, महाराष्ट्र सफेद 7400-7500, महाराष्ट्र लाल 7700-7900, उड़द बेस्ट 9100-9300, उड़द गर्मी 8600-9000, ग्रेविटी क्लीन 9300-9700, हल्की 5000-7000,

दाल- चना दाल एवरेज 7400-7500, मीडियम 7600-7700, बोल्ड 7900-8100, तुअर दाल सवा नं. 8200-8400, तुअर दाल 7300-7600, तुअर दाल मीडियम 8500-8800, बेस्ट 9900-10200, मसूर दाल 6800-7100, मूंग दाल 8700-8900, मूंग मोगर 10100-10600, उड़द दाल 9900-10300, मोगर 10800-11000,

अनाज- गेहूं मिल क्वालिटी 2500-2550, लोकवन एवरेज 2550-2650, बेस्ट 2750-2800, मालवराज 2600-2650, गेहूँ पूर्णा एवरेज 2400-2550, बेस्ट 2650-2750, मक्का पीली 1975-2000,

चावल- चावल हंसा सफेद 2900-3100, सेला 3500-3700, परमल 3400-3500, दुबराज 4500-5500, राजभोग 7500, काली मुंछ डिनर किंग 9000-9500, बासमती दुबार 8000-8500, मीनी दुबार 8000-8500, मोगरा 5000-7000, तिबार 10500-11800, बासमती (921) 12000-13000, बासमती सेला 7500-9500, पोहा 4500-5100,

मावा- इन्दौर 360, उज्जैन 300, रतलाम 290 रू. प्रति किलो।

इंदौर सर्राफा बाज़ार

इन्दौर। एजेंसी। बुधवार को स्थानीय सराफा बाजार में दोनों मूल्यवान धातुओं में बाजार गिरावट के रहे। भाव इस प्रकार रहे-

चाँदी (9999) 232000, चाँदी (99) 231800, टंच 231200, सिक्का 2600, सोना 10 ग्राम 148000,

रुपया गिरावट पर बंद

मुंबई। एजेंसी। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले दो पैसे की गिरावट के साथ ही 94.97 पर बंद हुआ, जो अपने पिछले बंद भाव 94.95 प्रति डॉलर से मामूली रूप से कमजोर था। वहीं अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में गत दिवस शुरुआती कारोबार के दौरान भारतीय रुपये में 26 पैसे की तेजी दर्ज की गई। 95.06 के स्तर पर खुलने के बाद यह मजबूत होकर 94.96 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि डॉलर के मुकाबले रुपये को निकट अवधि में 95.10-95.20 के आसपास मजबूत समर्थन मिलता दिख रहा है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.06 प्रति डॉलर पर खुला। इसके बाद इसमें तेजी आई और यह 26 पैसे की बढ़त दर्ज करते हुए 94.96 प्रति डॉलर पर पहुंच गया।

शेयर बाजार गिरावट पर बंद

मुम्बई। एजेंसी। भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को भी गिरावट रही। गत दिवस भी बाजार गिरावट पर बंद हुआ था। आज बाजार में ये गिरावट दुनिया भर से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवली हावी रहने से आई है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के साथ ही कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका से भी निवेशक बाजार से दूर हुए हैं। इससे भी वह टूटा है। दिनभर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 373.93 अंक गिरकर 76,570.35 पर आ गया। वहीं 50 शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 141.35 अंक नीचे आकर 23,914.45 पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान करीब 2323 शेयरों में गिरावट रही जबकि 1827 शेयरों में बढ़त दर्ज की गयी। वहीं 191 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज करने वाले शेयरों में आयशर मोटर्स, विप्रो, बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) शामिल थे, जिन्होंने निवेशकों को निराश किया। इसके विपरीत, कोल इंडिया, अदाणी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व, अदाणी एंटरप्राइजेज और

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स जैसे कुछ शेयरों ने बढ़त हासिल कर बाजार को संभालने का प्रयास किया। बाजार पर दबाव डालने वाले प्रमुख कारकों में वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें शामिल थीं। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 1 फीसदी बढ़कर 95.4 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं। इसके अलावा अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा जल्द ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका के कारण वैश्विक बॉन्ड यील्ड ऊंचे बने हुए हैं। अमेरिकी ब्याज दरों में वृद्धि से वैश्विक निवेशकों के लिए भारत जैसे उभरते हुए बाजार कम आकर्षक हो जाते हैं, जिससे विदेशी पूंजी का बहिर्प्रवाह बढ़ने का जोखिम रहता है। इससे भी घरेलू बाजार पर प्रभाव पड़ा है। कमजोर वैश्विक संकेतों ने भी भारतीय बाजार पर नकारात्मक असर डाला। एशियाई बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली; दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 3 फीसदी से अधिक गिरा, जबकि जापान का निक्केई 225 इंडेक्स भी लगभग 3 फीसदी नीचे आया। चीन का शंघाई एसएसई कंपोजिट इंडेक्स और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स भी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे, जिसने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता को उजागर किया और भारतीय निवेशकों के बीच चिंता पैदा की। वहीं इससे पहले आज सुबह बाजार गिरावट पर खुला।

केंद्र और राज्य सरकारों ने अगस्त में 1.68 लाख करोड़ का राजस्व प्राप्त किया

नई दिल्ली। एजेंसी। केंद्र और राज्य सरकारों ने अगस्त में 1.68 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध जीएसटी राजस्व प्राप्त किया। यह रकम पिछले अगस्त की तुलना में 8.3 फीसदी ज्यादा है जबकि उस दौरान कर की दर अपेक्षाकृत ज्यादा थी। सरकार ने खपत मांग को बढ़ाने के लिए पिछले साल सितंबर में जीएसटी दरों में बदलाव किया था। रिफंड से पहले का सकल जीएसटी संग्रह अगस्त में 1.99 लाख करोड़ रुपए रहा जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 14.8 फीसदी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में केंद्र और राज्य सरकारों ने 1.81 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध जीएसटी संग्रह अर्जित किया था। उस दौरान 29,968 करोड़ रुपए का कर रिफंड जारी किया गया था। व्यापारियों को उनके निर्यात पर लगने वाले कर का रिफंड मिलता है जबकि घरेलू आपूर्तिकर्ता अपने इस्तेमाल न किए गए कर क्रेडिट के लिए रिफंड का दावा करते हैं। अगस्त भी आयात से प्राप्त जीएसटी संग्रह की वृद्धि घरेलू कारोबार के मिले राजस्व की तुलना में ज्यादा रही। घरेलू जीएसटी राजस्व सालाना आधार पर 9.3 फीसदी बढ़कर 1.37 लाख करोड़ रुपए रहा जबकि आयात से मिलने वाला जीएसटी राजस्व 29 फीसदी बढ़कर 62,604 करोड़ रुपए रहा। ईवाई इंडिया के टैक्स पार्टनर ने कहा कि आयात से जुड़ी जीएसटी संग्रह में वृद्धि दर्शाती है कि कुछ क्षेत्रों में अभी भी बाहरी आपूर्ति पर निर्भरता बनी हुई है। इससे इन क्षेत्रों में ज्यादा स्थानीयकरण और आयातित वस्तुओं की जगह घरेलू उत्पाद को अपनाए जाने के लिए कुशल नीति की जरूरत का पता चलता है। अगस्त में जीएसटी रिफंड सालाना आधार पर 68 फीसदी बढ़कर 31,795 करोड़ रुपए रहा।

भारत में सेमीकंडक्टर क्रांति को मिलेगा बल, सरकार ने अधिसूचित की सेमीकान 2.0 योजना

नई दिल्ली। एजेंसी। भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी सेमीकॉन 2.0 योजना को अधिसूचित कर दिया है। यह योजना देश में चिप डिजाइन, सेमीकंडक्टर निर्माण, उपकरण और सामग्री विकास, उन्नत पैकेजिंग, शोध एवं विकास (आरऐंडडी) और प्रतिभा विकास से जुड़ी परियोजनाओं को व्यापक पात्रता मानदंड और वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस साल जुलाई में 1,27,500 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ स्वीकृत की गई यह योजना छह प्रमुख स्तंभों और 10 श्रेणियों पर आधारित है। नए दिशानिर्देशों के तहत सिलिकॉन वेफर फैब (निर्माण संयंत्र) को उनके पात्र पूंजीगत व्यय के 40 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। इस सहायता के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु, एक 300-मिमी सिलिकॉन फैब में प्रति माह कम से कम 40,000 वेफर स्टार्ट्स की स्थापित क्षमता होनी चाहिए। साथ ही, न्यूनतम 20,000 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश आवश्यक होगा और आवेदन से पहले के तीन वित्त वर्षों में से कम से कम एक में 7,500 करोड़ रुपये का न्यूनतम राजस्व दर्ज करना होगा। कंपाउंड सेमीकंडक्टर, फोटोनिक्स, सेंसर और डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब संयंत्रों के लिए, वित्तीय सहायता पात्र पूंजीगत व्यय के 35 प्रतिशत पर निर्धारित की गई है। इन संयंत्रों के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की सीमा 500 करोड़ रुपये है। दिशानिर्देशों में सेंसर/एमईएमएस फैब के लिए न्यूनतम 200 मिमी, कंपाउंड और डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब के लिए 150 मिमी और फोटोनिक्स अनुप्रयोगों के लिए 100 मिमी वेफर आकार तय किए गए हैं। उद्योग विशेषज्ञों ने सरकार के इस कदम का गर्मजोशी से स्वागत किया है।

मेष- आज किस्मत जैसे आपके अधूरे सपनों की फाइल खोलकर उन्हें पूरा करने के मूड में है। लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे तो मन खुशी से भर उठेगा। पैसों से जुड़ी परेशानियां भी धीरे-धीरे कम होती नजर आएंगी। सामाजिक क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और आपकी सोच लोगों को प्रभावित करेगी। घर की सजावट या रेनोवेशन का विचार उत्साह बढ़ाएगा। संतान की तरक्की देखकर आज गर्व के साथ चेहरे पर मुस्कान भी रहेगी।

वृषभ- आज आपका मन सेवा, दान-पुण्य और किसी के काम आने में खूब लगेगा। पुराने साथी से मुलाकात बीते दिनों की खूबसूरत यादें ताजा कर सकती है। वैवाहिक जीवन में चली आ रही दूरियां कम होंगी और रिश्ते में फिर से मिठास घुलेगी। रुका हुआ पैसा वापस मिलने से बड़ी राहत मिलेगी।

मिथुन- आज का दिन लाभ, राहत और खुशियों का खूबसूरत मेल लेकर आ सकता है। जीवनसाथी के साथ बिताया गया प्यार भरा समय रिश्ते में नई गर्माहट और मजबूती लाएगा। सेहत में सुधार होने से मन भी हल्का और प्रसन्न रहेगा। अतीत की कोई गलती आज आपके लिए सीख बनकर सही रास्ता दिखाएगी। विवादों से जितना दूर रहेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा।

कर्क- आज तरक्की के नए दरवाजे आपके सामने खुल सकते हैं। मुश्किल समय में दोस्तों का सहयोग आपको संभाल लेगा और किसी बड़ी परेशानी से बाहर निकलने में मदद करेगा। अविवाहित लोगों के जीवन में प्यार की नई दस्तक मन को खुश कर सकती है। सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी, लेकिन किसी भी काम में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छा अवसर मिल सकता है।

सिंह- आज कुछ उलझनें आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगी, लेकिन धैर्य बनाए रखा तो बाजी आपके हाथ में रहेगी। लंबे समय से अटके कामों को पूरा करने के लिए समय अनुकूल है। पूजा-पाठ और आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगाने से भीतर से शांति महसूस होगी। किसी जरूरतमंद की मदद करना आपको ऐसा संतोष देगा, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल होगा।

कन्या- आज कमाई और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना आपकी सबसे बड़ी समझदारी होगी। बढ़ते खर्च थोड़ी चिंता दे सकते हैं, लेकिन सही योजना बनाकर आप स्थिति को संभाल लेंगे। नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों के सामने नया और आकर्षक ऑफर आ सकता है। माता-पिता की सेवा और उनका आशीर्वाद आपके लिए भाग्य का मजबूत सहारा बनेगा।

तुला- आज आलस्य को पीछे छोड़कर सक्रिय होंगे तो सफलता खुद आपका रास्ता आसान करती नजर आएगी। खर्च करें, लेकिन जरूरत के हिसाब से, क्योंकि आज की छोटी लापरवाही आगे आर्थिक दबाव बना सकती है। जीवनसाथी को नौकरी के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। आपकी कला, रचनात्मकता और प्रतिभा लोगों का ध्यान खींचेगी।

वृश्चिक- आज कमाई के साथ खुशियों में भी इजाफा होने के संकेत हैं। घर की सजावट या कोई नई खरीदारी मन को उत्साह से भर सकती है। परिवार में चली आ रही गलतफहमियां खुलकर बातचीत करने से दूर होंगी। लंबे समय से अटका काम पूरा होने पर मन को बड़ी राहत मिलेगी। किसी विवाद में पड़ने के बजाय शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा।

धनु- आज आपकी सकारात्मक ऊर्जा आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगी। दोस्तों और परिवार का साथ आपको नई हिम्मत देगा। लंबी यात्रा की योजना बन सकती है और यह सफर भविष्य में यादगार साबित हो सकता है। हालांकि, बोलने से पहले थोड़ा रुककर सोचना जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में निकले शब्द रिश्तों में तनाव पैदा कर सकते हैं।

मकर- आज आप अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए पूरी ऊर्जा लगा देंगे और इसका परिणाम भी नजर आएगा। समाज सेवा और परोपकार के कार्य आपकी प्रतिष्ठा को और मजबूत करेंगे। भाई-बहनों का सहयोग मुश्किल समय में आपका हौसला बढ़ाएगा। अतीत में की गई कोई गलती आज एक महत्वपूर्ण सीख बनकर सामने आएगी और आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है।

कुंभ- आज का दिन आपसे थोड़ा धैर्य और संतुलन मांग सकता है। अचानक आने वाले खर्च बजट को हिला सकते हैं, इसलिए पैसे खर्च करने से पहले एक बार जरूर सोचें। छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने से परिवार का माहौल खराब हो सकता है। किसी बड़े फैसले को जल्दबाजी में लेने के बजाय हर पहलू पर विचार करें। अनजान व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना नुकसान दे सकता है।

मीन- आज आर्थिक मामलों में भाग्य आपका साथ देता नजर आएगा। कारोबार में अच्छी कमाई होने से मन प्रसन्न रहेगा और पार्टनरशिप भी मजबूत बनी रहेगी। व्यापार को अगले स्तर तक ले जाने की आपकी योजना सफल होने की संभावना है। लंबे समय से अटका पैसा वापस मिल सकता है, जिससे आर्थिक राहत मिलेगी। दोस्तों और परिवार के साथ बिताया गया समय दिन को खास बना देगा।

शब्दजाल - 8369

म	अ	मु	न	सी	ब	आ	ज	ग	ल	ट
रा	वि	ली	प्रे	दि	ला	व	र	ज	कां	ड़
न्यौ	छा	व	र	दी	छ	मि	आ	ब	वृ	ता
इं	नौ	ब	न	बा	वा	स	थु	ल	ष	क
डि	आ	मु	नी	श्व	र	न	न	न	भ	त
या	ल	मा	र	रा	क	ली	ट	ण	घ	व
द	स	न	न	ट्रे	जो	रा	व	र	व	र
क	रो	ऊ	ई	स	ब	क	र	चो	श	क
रा	व	तु	ला	रा	रो	ते	या	औ	र	आ
क	र	ल	प	लि	जी	व	भ	म	प	द
क	ड	क	अ	धी	श्व	र	र	ब	त	म

शब्द जाल में ऐसे 10 शब्द ढूंढिए जिनके पीछे 'वर' शब्द लगा हो. शब्द उपर से नीचे एवं तिरछे भी हैं.

दिलावर, सरोवर, जोरावर, नटवर, तेवर, अधीश्वर, मुनीश्वर, न्यौछावर,ताकतवर, मानसरोवर,

शब्दजाल - 8368 का हल

अ	ज	खी	रे	दा	र	रि	सि	या	र	ट
दा	वि	ल	ग	व	जी	ग	द	इ	ह	ली
गि	स	शे	ज	ग	न्ना	थ	ता	गा	क	क
री	ज	र	दो	पु	ज	न	म	न	त	ज
क	ग	ग	भा	लू	लं	ग	म	ग	व	न
जी	द	ल	जा	य	ज	पू	ना	हि	र	नी
ती	गु	म	ड्डी	हि	प	र	श	र	र	ल
क	रु	ल्जा	ई	धा	र	क	ज	ल	न	ण
ने	बा	म	न्न	ब्रा	ह	त्या	री	श	प	क
ज	ग	त	प	व	ज	ग	दा	चा	र्य	त
क	दु	ल्हे	रा	नी	ल	ज	ग	ख्या	त	थ

Jagrutidaur.com, Bangalore

फिल्म वर्ग पहेली- 7313

ऊपर से नीचे:-

१. दिलीप कुमार, मीना की 'दिल से तुझ को बेदिली है' गीत वाली फिल्म-३
२. 'संदेसे आते हैं' गीत वाली फिल्म-३
३. अजय देवगन, तब्बू की 'आ पपियाँ झपियाँ पा लें हम' गीत वाली फिल्म-४
४. 'जीवन से भरी तेरी आँखें' गीत वाली राजेश, शर्मिला की फिल्म-३
८. ऋषि, सनी, मीनाक्षी की 'बिन साजन झूला' गीत वाली फिल्म-३
१०. 'खुशी' में फरदीन की नायिका?-३
१२. 'गुस्सा इतना हसीन है तो' गीत वाली राजकुमार, राजेशखन्ना, मालासिन्हा की फिल्म-३
१४. 'जलते हैं जिसके लिये' गीत वाली सुनील दत्त, नूतन की फिल्म-३
१५. रेवती की पहली हिंदी फिल्म?-२
१६. 'साथिया बिन तेरे' गीत वाली सनी, तब्बू, शिल्पा की फिल्म-३
१७. विश्वजीत, बबीता की 'लाखों हैं यहाँ' गीत वाली फिल्म-३
१९. 'लंबी जुदाई' गीत वाली जैकी श्रॉफ, मीनाक्षी शेशाद्रि की फिल्म-२
२२. राजेंद्र, धर्मेन्द्र, नालासिन्हा की 'आज गालो मुस्करा लो' गीत वाली फिल्म-४
२३. 'तेरा मेरा साथ रहे' गीत वाली फिल्म-४
२४. राजेश खन्ना, श्रीदेवी की 'कह दे जमाने से' गीत वाली फिल्म-४
२८. 'दिलजले' में अजय का नाम?-२
२९. प्रशांत और ऐश्वर्या की एक फिल्म-२
३०.'मिलती है झुकती है' गीत वाली फिल्म-२

बायें से दायें:-

१. 'चाँद तारे तोड़ लाऊं' गीत वाली शाहरूख, जूही की फिल्म-२,२
३. सैफ, काजोल की 'नीला दुपट्टा पीला सूट' गीत वाली फिल्म-३
५. 'क्या यही प्यार है' गीत वाली संजयदत्त, टीना मुनीम की फिल्म-२
६. संजयदत्त, शरद, मनीषा, रवीना की 'ओ गोरी तू चली' गीत वाली फिल्म-२
७. 'चमन में रहके वीराना' गीत वाली दिलीप, निम्मी की फिल्म-३
९. ऋषि, चंकी, नीलम की 'देखा जो हुस्न आपका' गीत वाली फिल्म-३
११. 'कोई नहीं तेरे जैसा' गीत वाली अक्षय, सैफ अली की फिल्म-३
१३. फिल्म 'मिलाप' की नायिका-२
१४. 'गोपी किशन' में किस की दोहरी भूमिका थी?-३
१६. ऋषि कपूर, जेबा, अश्विनी भावे की 'आजा वे माही' गीत वाली फिल्म-२
१८. फिल्म 'धरती' में राजेंद्र कुमार के साथ नायिका कौन थी?-३
२०. 'जादू है नशा है' गीत वाली फिल्म-२
२१. 'इस टूटे दिल की' गीत वाली अनिल अक्षय, ऐश्वर्या की फिल्म-२
२३. राजेश, टीना, पद्मिनी की 'जिंदगी प्यार का' गीत वाली फिल्म-३
२५. 'मेघा रे मेघा' गीत वाली फिल्म-२
२६. विकास भल्ला, सुमीत सहगल, नीलम की एक फिल्म-२
२७. 'जवानी दीवानी' में रणधीरकपूर के साथ नायिका कौन थी?-२
२८. फिल्म 'फूल और पत्थर' में धर्मेन्द्र के किरदार का क्या नाम था?-२
३१. संजय दत्त, मनीषा की 'हो रब्बा तू ही बचा' गीत वाली फिल्म-४
३२. फिल्म 'स्टम्प्ड' में अली खान के साथ नायिका कौन है?-३

फिल्म वर्ग पहेली- 7312

अ	जू	बा	■	जो	र	■	दा	मि	नी
ल	■	बा	जी	■	क्ष	त्रि	य	■	तू
बे	टा	■	न	म	क	■	रा	जा	■
ला	■	अं	त	■	■	गे	■	लि	■
■	दा	दा	■	नू	■	जा	ने	म	न
मे	■	ज	ह	री	ले	■	हा	■	गिं
री	मा	■	त्या	■	कि	ला	■	द	स
जं	■	सू	■	म	न	■	म	र्द	■
ग	द	र	■	द	■	आ	ह	■	डॉ
■	म	ज	बू	र	■	■	ल	गा	न

Jagrutidaur.com, Bangalore

दैनिक पंचांग

3 सितम्बर 2026 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

ग्रह	स्थिति	लग्नारंभ समय	
सूर्य	सिंह में	कन्या	06.46 बजे से
चंद्र	वृष में	तुला	08.57 बजे से
मंगल	मिथुन में	वृश्चिक	11.12 ब.से
बुध	सिंह में	धनु	13.28 बजे से
गुरु	कर्क में	मकर	15.33 बजे से
शुक्र	तुला में	कुंभ	17.19 बजे से
शनि	मीन में	मीन	18.52 बजे से
राहु	कुंभ में	मेष	20.22 बजे से
केतु	सिंह में	वृष	22.03 बजे से
राहुकाल		मिथुन	00.01 बजे से
1.30 से 3.00		कर्क	02.14 बजे से
बजे तक		सिंह	04.30 बजे से

गुरुवार 2026 वर्ष का 246 वा दिन **दिशाशूल** दक्षिण **ऋतु** वर्षा। **विक्रम संवत्** 2083 **शक संवत्** 1948 **मास** भाद्रपद (दक्षिण भारत में श्रावण) **पक्ष** कृष्ण **तिथि** सप्तमी 02.26 बजे रात्र को समाप्त। **नक्षत्र** कृत्तिका 00.30 बजे रात्र को समाप्त। **योग** व्याघात 18.33 बजे को समाप्त। **करण** विष्टि 15.28 बजे तदनन्तर बव 02.26 बजे रात्र को समाप्त। **चन्द्रायु** 21.3 घण्टे **रवि क्रान्ति** उत्तर 07° 37' **सूर्य** दक्षिणायन **कलि अहर्गण** 1872821 **जूलियन दिन** 2461286.5 **कलियुग संवत्** 5128 **कल्पारंभ संवत्** 1972949128 **सृष्टि ग्रहारंभ संवत्** 1955885128 **वीरनिर्वाण संवत्** 2552 **हिजरी सन्** 1448 **महीना** रवि उलावल **तारीख** 20 **विशेष** शीतला सातम, मासिक कार्तिगाई।

दिन का चौघड़िया		रात का चौघड़िया	
शुभ	05.54 से 07.22 बजे तक	अमृत	05.40 से 07.11 बजे तक
रोग	07.22 से 08.51 बजे तक	चर	07.11 से 08.43 बजे तक
उद्वेग	08.51 से 10.19 बजे तक	रोग	08.43 से 10.15 बजे तक
चर	10.19 से 11.47 बजे तक	काल	10.15 से 11.47 बजे तक
लाभ	11.47 से 01.15 बजे तक	लाभ	11.47 से 01.19 बजे तक
अमृत	01.15 से 02.43 बजे तक	उद्वेग	01.19 से 02.51 बजे तक
काल	02.43 से 04.11 बजे तक	शुभ	02.51 से 04.23 बजे तक
शुभ	04.11 से 05.40 बजे तक	अमृत	04.23 से 05.55 बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, **मध्यम** चर, **अशुभ** उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अत: आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। Jagrutidaur.com, Bangalore

प्रसंगत: मनुष्यता का पाठ

यह घटना उस समय की है , जब क्रांतिकारी रोशन सिंह को काकोरी कांड में मृत्युदंड दिया गया। उनके शहीद होते ही उनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में एक जवान बेटी थी और उसके लिए वर की तलाश चल रही थी। बड़ी मुश्किल से एक जगह बात पक्की हो गई। कन्या का रिश्ता तय होते देखकर वहां के दरोगा ने लड़के वालों को धमकाया और कहा कि क्रांतिकारी की कन्या से विवाह करना राजद्रोह समझा जाएगा और इसके लिए सजा भी हो सकती है। किंतु वर पक्ष वाले दरोगा की धमकियों से नहीं डरे और बोले, 'यह तो हमारा सौभाग्य होगा कि ऐसी कन्या के कदम हमारे घर पड़ेंगे, जिसके पिता ने अपना शीश भारत माता के चरणों पर रख दिया।' वर पक्ष का दृढ़ इरादा देखकर दरोगा वहां से चला आया पर किसी भी तरह इस रिश्ते को तोड़ने के प्रयास करने लगा। जब एक पत्रिका के संपादक को यह पता लगा तो वह आगबबूला हो गए और तुरंत उस दरोगा के पास पहुंचकर बोले, 'मनुष्य होकर जो मनुष्यता ही न जाने वह भला क्या मनुष्य? तुम जैसे लोग बुरे कर्म कर अपना जीवन सफल मानते हैं किंतु यह नहीं सोचते कि तुमने इन कर्मों से अपने आगे के लिए इतने कांटे बो दिए हैं जिन्हें अभी से उखाड़ना भी शुरू करो तो अपने अंत तक न उखाड़ पाओ। अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते तो उससे छीनने का प्रयास भी न करो।' संपादक की खरी-खोटी बातों ने दरोगा की आंखें खोल दीं और उसने न सिर्फ कन्या की मां से माफी मांगी, अपितु विवाह का सारा खर्च भी खुद वहन करने को तैयार हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगीं। कन्यादान के समय जब वधू के पिता का सवाल उठा तो वह संपादक उठे और बोले, 'रोशन सिंह के न होने पर मैं कन्या का पिता हूं। कन्यादान मैं करूंगा।' वह संपादक थे- महान स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी।

सूडोकु नवताल- 7622

★☆☆☆☆ सरल

2	9			5				4
4			2		7		8	
	1	6		8				3
8		5		9				7
3	6			2			1	9
1				3		5		2
5				7		6	3	
	3		1		8			5
9				6			2	1

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते .
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -7621 का हल

7	8	1	6	9	4	2	5	3
2	6	4	5	3	6	1	7	9
5	3	9	1	2	7	4	6	8
9	5	8	7	4	1	3	2	6
1	2	3	9	5	6	7	8	4
4	7	6	3	8	2	9	1	5
3	9	7	2	6	5	8	4	1
6	4	2	8	1	9	5	3	7
8	1	5	4	7	3	6	9	2

शब्द पहेली - 8837

बाएँ से दाएँ

1. परिचय, जानना-2,4
5. वायु रोग-2
7. उत्साह, जिज्ञासा
9. कांटा, शूल
10. पिता, साधू-2
11. योद्धा जाति, राजपूत-3
14. थकान-4
16. मिसाल के तौर पर-4
20. ध्वजा, पताका-3
22. सीमा, बार्डर-2
23. बुरी आदत-2
24. समस्या, मुद्दा-3
27. जोर, दम, ताकत-2
28. दिखावटीपन, आडंबर, -3,3

ऊपर से नीचे

1. सीतापति, रामचंद्र-5
2. लम्हा, क्षण-2
3. धोखेबाज, दगाबाज-4
4. नलका, टौंटी-2
6. पुत्र, लड़का-3
8. कमरा, रूम-2
12. तीनों काल-3
13. पार्थिव शरीर, लाश-2
15. कजरा, अंजन-3
17. सच्चाई, सच-2
18. सेंधमार-5
19. पुचकारना, हाथ फेरना-4
20. धोखा, दगा-3
21. जरा, थोड़ा-2
25. सभी, संपूर्ण-2
26. राजेश खन्ना व मुमताज की बेहतरीन फिल्म-2

शब्द पहेली -8836 का हल

■	दा	न	व	■	अ	व	रो	ध
मा	न	■	ल	गा	म	■	ज	ड़
न	■	रा	य	■	र	वा	■	क
स	ला	ह	का	र	■	द	ह	न
■	य	■	र	■	प	■	ल	■
म	न	का	■	आ	तं	क	वा	द
द	■	म	य	■	ग	म	■	स्त
हो	श	■	शो	र	बा	■	ना	क
श	ह	जा	दा	■	जी	व	न	■

Jagrutidaur.com, Bangalore

हलषष्ठी पर महिलाओं ने रखा व्रत, हरछठ माता की पूजा कर संतान की सुख-समृद्धि की कामना की

पद्मेश न्यूज। लांजी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पर नगर एवं क्षेत्र में हलषष्ठी (हरछठ) का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। संतान की दीर्घायु, सुख-समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और मंगलकामना के लिए महिलाओं ने व्रत रखकर हरछठ माता का पूजन किया। प्राचीन परंपरा के अनुसार महिलाओं ने पूजन सामग्री एकत्रित कर सामूहिक रूप से कथा श्रवण किया और संतान की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना की। हलषष्ठी का पर्व भगवान श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्मोत्सव से भी जुड़ा माना जाता है। इस दिन महिलाओं द्वारा विशेष रूप से ऐसे अन्न एवं खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिनकी खेती हल से न की गई हो। इसी परंपरा के चलते पूजन के दौरान लाई, चना, महुआ, फल एवं अन्य पारंपरिक सामग्री अर्पित की गई।

महुए के पत्तों से बनाए दोने-पत्तल, पलाश की डाल और काश के फूलों से सजाया पूजन स्थल

नगर के वार्ड क्रमांक 3 में पेट्रोल पंप के पीछे श्रीमती वंदना वैष्णव के निवास पर महिलाओं ने सामूहिक रूप से एकत्रित होकर विधि-विधान से हरछठ माता का पूजन किया। पूजन के लिए महुए के पत्तों से दोने और पत्तल तैयार किए गए। इनमें लाई, चना और महुआ रखकर माता को अर्पित किया गया। वहीं पलाश की डाल के साथ काश के फूल रखकर हरछठ माता का पूजन किया गया। पूजन के दौरान भैंस का दूध, दही, घी एवं फल आदि अर्पित कर संतान की दीर्घायु और परिवार की सुख-शांति की कामना की गई। महिलाओं ने व्रत रखकर पारंपरिक नियमों का पालन किया तथा बिना हल से जुते हुए अन्न एवं फल का उपयोग किया।

कथा वाचन के बाद हुई आरती, महिलाओं ने बांटी प्रसादी

हलषष्ठी पर्व पर कई स्थानों पर पंडितों द्वारा हरछठ माता की कथा का वाचन किया गया, वहीं अनेक स्थानों पर वरिष्ठ महिलाओं ने नई पीढ़ी की महिलाओं और बेटियों को संतान से संबंधित पारंपरिक कथाएं सुनाईं। कथा श्रवण के बाद सामूहिक रूप से आरती एवं पूजन किया गया। पूजन के समापन पर महिलाओं ने एक-दूसरे को कुमकुम लगाकर पर्व की शुभकामनाएं दीं। इसके बाद टुकनियों और दोनों में लाई, चना, महुआ, नारियल सहित अन्य प्रसादी रखकर महिलाओं ने आपस में आदान-प्रदान किया। पारंपरिक विधि से मनाए गए इस पर्व में महिलाओं की आस्था और उत्साह देखते ही बना। हलषष्ठी के माध्यम से क्षेत्र में वर्षों से चली आ रही लोक परंपरा और मातृशक्ति की संतान के प्रति मंगलकामना की भावना एक बार फिर देखने को मिली।

बैगा बच्चों की मौतों और मूलभूत अधिकारों के मुद्दे पर लांजी बंद की रणनीति बनेगी

गोड़वाना भवन में 6 सितंबर को होगी बैठक, 3 सितंबर के बालाघाट बंद में शामिल होने की अपील

पद्मेश न्यूज। लांजी। क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों तथा बैगा बच्चों की मौतों के संवेदनशील मुद्दे को लेकर शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने और संवैधानिक अधिकारों एवं बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है। इसी बात को लेकर 2 सितंबर को गोंडवाना भवन लांजी में एक औपचारिक बैठक की गई। बैठक में धनीराम इनवाती, रोशनलाल दल्लेमाल, ऋषिकेश घोरमारे, एम के मड़ामे, संजय कुमार धारणे, डेमेश्वर घोरमारे, दीपक घोरमारे, धनीराम उइके, रूपेश मड़ावी, मोतीराम उइके, मोहनसिंह कोकोड़े, अशोक मर्सकोले, टुमनलाल घोरमारे, संजय सैयाम आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। बैठक में लांजी बंद को लेकर आगामी 6 सितंबर को गोड़वाना भवन, लांजी में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित किया जाना तय किया गया। बैठक दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होगी। बैठक में क्षेत्र के सामाजिक संगठनों, आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित सभी सहयोगियों की उपस्थिति में लांजी बंद की रूपरेखा एवं रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आयोजकों का कहना है कि बैगा समुदाय के बच्चों की मौतों जैसे संवेदनशील विषय पर शासन-प्रशासन को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए तथा आदिवासी समाज को संविधान प्रदत्त अधिकारों के साथ आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

3 सितंबर को बालाघाट बंद का आह्वान

इसी मुद्दे को लेकर 3 सितंबर को बालाघाट बंद का आह्वान किया गया है। जिला स्तरीय बंद कार्यक्रम में लांजी सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों के सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं समाज के लोगों से शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई है।

दवा दे रहे डॉक्टर, हौसला दे रहा पूरा लांजी

बीमारी से जूझते बैगा परिवारों को अस्पताल में इलाज के साथ मिला अपनापन, 60 में 29 मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर, युवा डॉक्टरों की फौज मुस्तैद, प्रभार के दूसरे दिन ही अस्पताल पहुंचे एसडीएम तिवारी

पद्मेश न्यूज। लांजी। दवा डॉक्टर दे रहे हैं, हौसला पूरा लांजी दे रहा है..... वनांचल के मछुरदा, कोरका, धर्मशाला, गठिया सहित अन्य गांवों से बीमारी की मार झेलकर सिविल अस्पताल लांजी पहुंचे बैगा समुदाय के मरीजों के लिए यह अस्पताल महज इलाज की जगह नहीं, बल्कि उम्मीद और अपनत्व का ठिकाना बन गया है। सहमे हुए परिजन जब बीमार बच्चों को लेकर यहां पहुंचे तो युवा चिकित्सकों की टीम ने पूरी मुस्तैदी से मोर्चा संभाला। डॉक्टर दिन में तीन बार मरीजों की सुध ले रहे हैं, प्रशासन अस्पताल की हर व्यवस्था पर नजर रख रहा है और समाजसेवी विधान जोगी अपने खर्च पर मरीजों को शुद्ध भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। बीमारी के बीच सामने आई यह तस्वीर इलाज से कहीं आगे बढ़कर सेवा, संवेदना और इंसानियत की कहानी कह रही है। जिसमें 2 सितंबर तक 60 मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 29 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। 3 मरीजों को बेहतर उपचार के लिए रेफर किया गया है, जबकि 22 मरीज अभी सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। भर्ती मरीजों में अधिकांश को मलेरिया, सर्दी-खांसी और बुखार की शिकायत है।

दिन में तीन बार मरीजों के बीच पहुंच रहे डॉक्टर

अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों ने बताया कि चिकित्सक सुबहए दोपहर और शाम नियमित रूप से मरीजों को देखने पहुंच रहे हैं। दवाइयों के साथ लगातार निगरानी की जा रही है और अस्पताल में मरीजों के लिए पर्याप्त बेड भी उपलब्ध हैं। परिजनों का कहना है कि उन्हें यहां बेहतर उपचार मिल रहा है और डॉक्टर उनकी बात भी गंभीरता से सुन रहे हैं। बच्चों के टीकाकरण को लेकर परिजनों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा गांव में ही बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है। वनांचल से लगातार मरीजों के पहुंचने के बीच बीएमओ डॉ. अक्षय उपराड़े, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉ. अंकित खरोले सहित युवा चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की टीम पूरी जिम्मेदारी से उपचार में जुटी है। बच्चों की स्थिति पर खास नजर रखी जा रही है। चिकित्सकों की सक्रियता और नियमित निगरानी ने मरीजों के परिजनों के बीच भरोसा कायम किया है।

प्रभार के दूसरे दिन ही अस्पताल पहुंचे एसडीएम

किरनापुर से स्थानांतरित होकर आए नवागत एसडीएम आदित्य नारायण तिवारी ने प्रभार संभालने के दूसरे दिन ही सिविल अस्पताल लांजी पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। उनके साथ तहसीलदार संजय बारस्कर भी मौजूद रहे। एसडीएम ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और भर्ती मरीजों से सीधे बातचीत कर उनके इलाज की स्थिति जानी। इस दौरान बीएमओ डॉ. अक्षय उपराड़े, डॉ. अंकित खरोले एवं मनीष पांडे ने अस्पताल की व्यवस्थाओं और मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति से उन्हें अवगत कराया। निरीक्षण के बाद एसडीएम तिवारी ने अस्पताल की स्थिति को संतोषजनक बताते हुए कहा कि मरीजों को बेहतर उपचार मिल रहा है। उन्होंने चिकित्सकों को बच्चों की निरंतर मॉनिटरिंग करने और स्थिति गंभीर होने पर बिना देरी जिला अस्पताल रेफर करने के निर्देश दिए।

इलाज के साथ भोजन, विधान जोगी की सेवा भी चर्चा में

इस पूरी मुहिम में आशा सामाजिक संगठन के सदस्य विधान जोगी की पहल भी काबिले तारीफ है। अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों की जरूरत को देखते हुए जोगी लगातार अपने निजी खर्च पर शुद्ध भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। बीमारी और परेशानी के बीच किसी परिवार को भोजन की चिंता न हो, इसके लिए लगातार सेवा करना मानवता की वह मिसाल है, सिविल अस्पताल लांजी में इस वक्त तीन तस्वीरें एक साथ दिखाई दे रही हैं- डॉक्टरों की मुस्तैदी, प्रशासन की संवेदनशील निगरानी और समाज की सेवाभावना। शायद यही वजह है कि बीमारी के बीच भी यहां उम्मीद जिंदा है और कई मासूम चेहरे स्वस्थ होकर फिर अपने गांव लौट चुके हैं।

सितंबर माह में आस्था और भक्ति का रंग, कई बड़े हिंदू पर्व मनाए जाएंगे

4 को जन्माष्टमी, 14 को गणेशोत्सव व हरतालिका तीज और अनंत चतुर्दशी तक रहेगा उत्सव का माहौल; 27 सितंबर से शुरू होगा पितृपक्ष

पद्मेश न्यूज। लांजी। सितंबर माह हिंदू धर्मावलंबियों के लिए आस्था, भक्ति, व्रत और धार्मिक अनुष्ठानों से भरा रहेगा। इस माह भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव से लेकर गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज, ऋषि पंचमी, राधाष्टमी, विश्वकर्मा पूजा, परिवर्तिनी एकादशी, अनंत चतुर्दशी और पितृपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाएंगे। महीने के अंतिम दिनों में पितरों के प्रति श्रद्धा और तर्पण का विशेष क्रम शुरू होगा। पंचांग के अनुसार सितंबर 2026 में प्रमुख पर्वों की शुरुआत 4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से होगी, जबकि 27 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ होगा।

4 सितंबर — श्रीकृष्ण जन्माष्टमी

सितंबर माह का पहला बड़ा धार्मिक पर्व श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर, शुक्रवार को मनाई जाएगी। यह पर्व भगवान विष्णु के आठवें अवतार भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों से पृथ्वी और प्रजा को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्रीकृष्ण ने देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। मान्यता है कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्यरात्रि में भगवान श्रीकृष्ण का अवतार हुआ। इसी कारण जन्माष्टमी की रात मंदिरों और घरों में भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु उपवास रखते हैं, भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना करते हैं और मध्यरात्रि में जन्म आरती के बाद प्रसाद वितरित किया जाता है। कई स्थानों पर मटकी सजाने, भजन-कीर्तन और झांकियों का भी आयोजन होता है।

7 सितंबर — अजा एकादशी

7 सितंबर, सोमवार को अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि अजा एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियमपूर्वक करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति तथा भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है।

10 सितंबर — पोला पर्व- अन्नदाता और पशुधन के प्रति कृतज्ञता का पर्व

महाराष्ट्र सीमा से सटे लांजी क्षेत्र में सितंबर माह का पोला पर्व विशेष उत्साह और ग्रामीण परंपराओं के साथ मनाया जाएगा। वर्ष 2026 में पोला पर्व 10 सितंबर को मनाया जाएगा। यह पर्व किसानों के जीवन में बैलों और पशुधन के महत्व को रेखांकित करता है। पोला के दिन किसान अपने बैलों को स्नान कराकर उन्हें सजाते-संवारते हैं, सींगों पर रंग लगाते हैं तथा फूल-मालाओं, घंटियों और आकर्षक वस्त्रों से श्रृंगारित कर उनकी पूजा-अर्चना करते हैं। इस दिन बैलों को खेती के काम से विश्राम दिया जाता है। पोला केवल पशु पूजा का पर्व नहीं, बल्कि किसान और उसके पशुधन के बीच वर्षों पुराने आत्मीय संबंध का प्रतीक है। खेत में हल चलाने से लेकर कृषि कार्यों में किसान का साथ देने वाले बैलों के प्रति आभार व्यक्त करने की यह परंपरा ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति की गहरी जड़ों को दर्शाती है।

14 सितंबर — हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी

सितंबर की धार्मिक गतिविधियों का सबसे महत्वपूर्ण दिन 14 सितंबर, सोमवार रहेगा। इस दिन हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी दोनों पर्व मनाए जाएंगे।

हरतालिका तीज

हरतालिका तीज भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र दांपत्य का प्रतीक मानी जाती है। विवाहित महिलाएं पति की दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से व्रत करती हैं, जबकि कई स्थानों पर कुंवारी कन्याएं भी अच्छे जीवनसाथी की कामना से इस व्रत को करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थीं। उन्होंने कठोर तपस्या की। उनके पिता हिमवान उनका विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते थे। तब माता पार्वती की सखी उन्हें वन में ले गईं, जहां उन्होंने भगवान शिव की आराधना करते हुए कठिन तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसी मान्यता से हरतालिका तीज का पर्व जुड़ा है।

गणेश चतुर्थी

इसी दिन गणेश चतुर्थी का पर्व भी मनाया जाएगा। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धि, ज्ञान और शुभता का देवता माना जाता है। गणेश चतुर्थी पर घरों और सार्वजनिक पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजा-अर्चना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने उबटन से गणेशजी की रचना की और उन्हें अपने द्वार की रक्षा का दायित्व दिया। भगवान शिव के आने पर गणेशजी ने उन्हें रोक दिया। बाद में भगवान शिव ने गणेशजी को अपना पुत्र स्वीकार किया और उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। तभी से किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है।

15 सितंबर — ऋषि पंचमी

15 सितंबर, मंगलवार को ऋषि पंचमी मनाई जाएगी। यह पर्व सप्तऋषियों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर माना जाता है। धार्मिक परंपरा में इस दिन ऋषियों का स्मरण, पूजन और व्रत किया जाता है।

17 सितंबर — विश्वकर्मा पूजा

17 सितंबर, गुरुवार को भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाएगी। उन्हें देवताओं का शिल्पकार और निर्माण, वास्तु तथा तकनीकी कौशल का अधिष्ठाता माना जाता है। औद्योगिक संस्थानों, कारखानों, कार्यशालाओं और विभिन्न निर्माण कार्यों से जुड़े प्रतिष्ठानों में इस दिन मशीनों, औजारों और उपकरणों की पूजा की परंपरा है। यह पर्व श्रम, हुनर और निर्माण की शक्ति के प्रति सम्मान का संदेश देता है। इसी दिन कन्या संक्रांति भी होगी।

19 सितंबर — राधाष्टमी

19 सितंबर, शनिवार को राधाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। यह दिन भगवान श्रीकृष्ण की परम भक्त और प्रेम-भक्ति की प्रतीक मानी जाने वाली राधारानी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। राधाष्टमी पर राधा-कृष्ण मंदिरों में विशेष पूजा, भजन-कीर्तन और श्रृंगार किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि राधारानी की आराधना से भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है।

22 सितंबर — परिवर्तिनी एकादशी

22 सितंबर, मंगलवार को परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। भगवान विष्णु को समर्पित इस एकादशी को विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की आराधना और व्रत करने से पुण्य की प्राप्ति होती है।

25 सितंबर — अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन

25 सितंबर, शुक्रवार को अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी। इसी दिन गणेशोत्सव का समापन करते हुए गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। अनंत चतुर्दशी भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप को समर्पित मानी जाती है। इस दिन श्रद्धालु अनंत भगवान की पूजा कर हाथ में अनंत सूत्र धारण करते हैं। धार्मिक कथा में पांडवों के वनवास के दौरान भगवान श्रीकृष्ण द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को अनंत व्रत का महत्व बताए जाने का उल्लेख मिलता है। वहीं, गणेशोत्सव के दौरान स्थापित प्रतिमाओं का विसर्जन श्रद्धालु भावपूर्ण वातावरण में करते हैं। इसके साथ भगवान गणेश से अगले वर्ष फिर आने की प्रार्थना की जाती है।

26 सितंबर — भाद्रपद पूर्णिमा

26 सितंबर, शनिवार को भाद्रपद पूर्णिमा रहेगी। यह तिथि धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसी के अगले दिन से पितृपक्ष की शुरुआत होगी।

27 सितंबर — पितृपक्ष का शुभारंभ

27 सितंबर, रविवार से पितृपक्ष प्रारंभ होगा। हिंदू धर्म में पितृपक्ष को अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और स्मरण का विशेष समय माना जाता है। पितृपक्ष में परिवार के दिवंगत पूर्वजों का स्मरण करते हुए उनके निमित्त तर्पण, श्राद्ध और दान-पुण्य किया जाता है। मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक किए गए कर्मों से पितरों के प्रति कर्तव्य पूरा होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत के कर्ण से जुड़ी कथा पितृपक्ष के महत्व को समझाती है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद कर्ण को पर्याप्त अन्न नहीं मिला, क्योंकि जीवन में उन्होंने मुख्य रूप से धन-संपत्ति का दान किया था, लेकिन पूर्वजों के निमित्त अन्नदान नहीं किया। इसके बाद उन्हें पृथ्वी पर लौटकर पितरों के लिए अन्न और जल अर्पित करने का अवसर मिला। इसी कथा को श्राद्ध और अन्नदान की परंपरा से जोड़ा जाता है।

आस्था, परंपरा और संस्कारों का संदेश देगा सितंबर

सितंबर 2026 का महीना धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक ओर भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव और गणपति आराधना के साथ भक्ति और उल्लास का वातावरण बनेगा, वहीं हरतालिका तीज दांपत्य प्रेम और तपस्या का संदेश देगी। विश्वकर्मा पूजा श्रम और हुनर के सम्मान का अवसर बनेगी तो राधाष्टमी प्रेम और भक्ति की भावना को मजबूत करेगी। महीने के अंतिम दिनों में पितृपक्ष की शुरुआत के साथ वातावरण श्रद्धा, स्मरण और संस्कारों से जुड़ जाएगा। इस तरह सितंबर का पूरा महीना भक्ति, व्रत, उत्सव, परंपरा और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का संदेश देता नजर आएगा।

अब तालाबों की जमीन पर नहीं चलेगी मनमानी!

एनजीटी के सख्त निर्देश के बाद सरकार ने शुरू की तैयारी, हर महीने होगी निगरानी; अफसरों की जवाबदेही भी तय होगी -13,565 झीलों-वेटलैंड की होगी पैमाइश, छह महीने में मुनार लगाने का आदेश

भोपाल। मध्य प्रदेश में तालाबों, झीलों और वेटलैंड की जमीन पर अतिक्रमण और निर्माण को लेकर अब सरकार को जमीन पर उतरकर काम करना होगा। प्रदेश में चिह्नित 13,565 वेटलैंड का सीमांकन कर उनकी सीमाओं पर मुनार यानी बाउंड्री पिलर लगाने का काम छह महीने में पूरा करना होगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देश के बाद अब वेटलैंड संरक्षण की व्यवस्था सिर्फ रिकॉर्ड और नक्शों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मौके पर भी इसकी सीमा दिखाई देगी। इस पूरे अभियान की निगरानी राज्य वेटलैंड अथॉरिटी हर महीने करेगी, जबकि संबंधित विभागों के बीच समन्वय कर तय समयसीमा में काम पूरा कराने की जिम्मेदारी मुख्य सचिव स्तर पर रहेगी। यानी अब किसी तालाब या वेटलैंड की सीमा को लेकर भविष्य में विवाद खड़ा होता है तो सरकारी रिकॉर्ड के साथ जमीन पर लगाए गए मुनार भी महत्वपूर्ण प्रमाण होंगे।

प्रदेश में बड़ी संख्या में तालाब और जल संरचनाएं ऐसी हैं, जिनकी सीमाएं मौके पर स्पष्ट नहीं हैं। यही स्थिति कई जगह अतिक्रमण और निर्माण के विवाद की वजह बनती रही है। एनजीटी के निर्देश के बाद अब सबसे बड़ा बदलाव यही होगा कि चिह्नित वेटलैंड की सीमा को जमीन पर स्थायी रूप से चिन्हित किया जाएगा। छह महीने में सीमांकन और मुनार लगाने का काम पूरा होने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि किस क्षेत्र को वेटलैंड का हिस्सा माना गया है। इससे निर्माण, भूमि उपयोग परिवर्तन और अतिक्रमण से जुड़े मामलों में प्रशासन के सामने भी स्पष्ट आधार रहेगा।

13,565 वेटलैंड पर नजर, हर महीने रिपोर्ट

यह काम एक बार सीमांकन करके खत्म नहीं होगा। राज्य वेटलैंड अथॉरिटी को इसकी मासिक निगरानी करनी होगी। इसका मतलब है कि सीमांकन के बाद भी यह देखना होगा कि कहीं मुनार हटाए तो नहीं गए, सीमा के भीतर नया अतिक्रमण तो नहीं हुआ और प्रतिबंधित गतिविधियां तो शुरू नहीं हो गईं। एनजीटी ने वेटलैंड संरक्षण में लापरवाही को भी गंभीरता से लिया है। संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय किए जाने के निर्देश से प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही बढ़ेगी। अब किसी जल क्षेत्र में अतिक्रमण होने के बाद सिर्फ कार्रवाई करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि यह भी देखा जाएगा कि उसकी निगरानी के लिए जिम्मेदार अधिकारी ने समय रहते क्या कदम उठाए।

भोपाल के भोज वेटलैंड पर भी सख्ती

एनजीटी के आदेश का असर सिर्फ प्रदेश के हजारों वेटलैंड तक सीमित नहीं है। राजधानी भोपाल के भोज वेटलैंड, बड़े तालाब, छोटे तालाब, केरवा और कलियासोत जैसे महत्वपूर्ण जल क्षेत्रों को लेकर भी स्पष्ट सीमांकन और जलस्तर तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। खास तौर पर बड़े तालाब और भदभदा डैम को लेकर निर्देश महत्वपूर्ण हैं। फुल टैंक लेवल तक पानी पहुंचे बिना भदभदा डैम के गेट खोलने की अनुमति नहीं होगी। पानी एफटीएल तक पहुंचने के बाद वास्तविक परिस्थितियों को देखते हुए सीमांकन की स्थिति का दोबारा आकलन किया जाएगा। इसके लिए सात सदस्यीय समिति गठित की गई है, जिसे 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देनी होगी।

भदभदा के गेट से जुड़ा फैसला अब नियमों के दायरे में

भोपाल के बड़े तालाब का जलस्तर लंबे समय से शहर की चर्चा का विषय रहा है। बारिश के दौरान तालाब का जलस्तर बढने पर भदभदा डैम के गेट खोलने की प्रक्रिया को लेकर अलग-अलग स्तर पर सवाल उठते रहे हैं। एनजीटी के निर्देश के बाद अब इस पूरी व्यवस्था को निर्धारित एफटीएल से जोड़ दिया गया है। इसका सीधा अर्थ है कि जलस्तर और तालाब की सीमा से जुड़े तकनीकी मानकों को नजरअंदाज कर निर्णय लेना आसान नहीं होगा। सात सदस्यीय समिति के सामने चुनौती सिर्फ सीमा तय करने की नहीं, बल्कि जल संसाधन, पर्यावरण और शहर की जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की भी होगी।

असली परीक्षा अब अमल की

मध्य प्रदेश में वेटलैंड की सुरक्षा के लिए यह आदेश महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन इसकी सफलता छह महीने की समयसीमा में जमीन पर होने वाले काम से तय होगी। प्रदेश में 13,565 वेटलैंड का सीमांकन कोई छोटा प्रशासनिक अभियान नहीं है। इसके लिए राजस्व रिकॉर्ड, जल संसाधन विभाग के नक्शे, स्थानीय निकायों के रिकॉर्ड और मौके की स्थिति का मिलान करना होगा। कई जगह वेटलैंड की सीमा के आसपास पहले से आबादी, सड़क, खेती या अन्य गतिविधियां हो सकती हैं। ऐसे में सीमांकन के दौरान विवाद भी सामने आ सकते हैं। प्रशासन के सामने चुनौती होगी कि वह राजनीतिक या स्थानीय दबाव से ऊपर उठकर वैज्ञानिक और रिकॉर्ड आधारित सीमा तय करे।

मुनार लगने के बाद बढ़ेगी प्रशासन की जिम्मेदारी

वेटलैंड पर मुनार लग जाना अपने आप में संरक्षण की गारंटी नहीं है। असली सवाल उसके बाद शुरू होगा। यदि किसी जल क्षेत्र की सीमा तय होने के बावजूद वहां अतिक्रमण होता है तो कार्रवाई कितनी तेजी से होती है, यही व्यवस्था की वास्तविक परीक्षा होगी। यही वजह है कि एनजीटी ने निगरानी और अधिकारियों की जवाबदेही को भी आदेश का हिस्सा बनाया है। हर महीने निगरानी की व्यवस्था से सरकार के पास प्रगति की नियमित रिपोर्ट रहेगी और छह महीने की समयसीमा के भीतर काम पूरा कराने का दबाव भी बना रहेगा।

शहरों के विकास और जल क्षेत्रों के बीच संतुलन जरूरी

मध्य प्रदेश के शहर तेजी से फैल रहे हैं। भोपाल जैसे शहरों में आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार लगातार हो रहा है। ऐसे में तालाबों, झीलों और प्राकृतिक जल क्षेत्रों पर दबाव बढना स्वाभाविक है। दूसरी ओर, यही वेटलैंड शहरों के पर्यावरणीय संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बारिश के पानी को रोकने, भूजल पुनर्भरण और जैव विविधता के संरक्षण में मदद करते हैं। इसलिए वेटलैंड की सीमा स्पष्ट करना केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि भविष्य के शहरी नियोजन का भी हिस्सा है।

अब कागज से निकलकर जमीन पर दिखेगा संरक्षण

मध्य प्रदेश में 13,565 वेटलैंड का सीमांकन और मुनार लगाने की कवायद का सबसे बड़ा असर यही हो सकता है कि आने वाले समय में तालाब और जल क्षेत्र की सीमा को लेकर अस्पष्टता कम हो। अभी तक कई मामलों में सरकारी नक्शे और मौके की स्थिति के बीच अंतर विवाद की वजह बनता रहा है। यदि छह महीने में सभी चिह्नित वेटलैंड की सीमा जमीन पर स्पष्ट कर दी जाती है और उसके बाद नियमित निगरानी होती है, तो अतिक्रमण पर कार्रवाई का आधार भी मजबूत होगा। अब निगाहें इस बात पर हैं कि एनजीटी के निर्देश के बाद प्रदेश सरकार और संबंधित विभाग कितनी तेजी से जमीन पर काम शुरू करते हैं। क्योंकि मुनार लगाने का आदेश केवल सीमा चिन्हित करने का आदेश नहीं है; यह इस बात की परीक्षा भी है कि मध्य प्रदेश अपने जल स्रोतों को भविष्य के लिए कितना सुरक्षित रख पाता है।

वेटलैंड के 50 मीटर दायरे से हटेंगे निर्माण, प्रदेश के सभी कलेक्टरों को 15 दिन में कार्रवाई के निर्देश

भोपाल। प्रदेश के सभी जिलों में वेटलैंड (आर्द्रभूमि) के आसपास 50 मीटर के दायरे में किए गए अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई होगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। वह वेटलैंड की सीमा का सत्यापन कर 50 मीटर क्षेत्र में हुए निर्माण की जांच करें, और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसके लिए 15 दिन की समय-सीमा तय की गई है।

एनजीटी के निर्देशों के तहत कलेक्टरों को संबंधित राजस्व, नगरीय निकाय, पंचायत और पर्यावरण अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर स्थल निरीक्षण कराने को कहा गया है। वेटलैंड की सीमा का सीमांकन कर उसका रिकॉर्ड तैयार करने तथा संवेदनशील क्षेत्र में नए निर्माण की अनुमति नहीं देने के निर्देश भी दिए गए हैं।

जांच में यदि 50 मीटर दायरे में अवैध निर्माण पाए जाते हैं, तो उन्हें नियमानुसार हटाने की कार्रवाई की जाए। साथ ही वेटलैंड में मिट्टी भराव, जल प्रवाह रोकने, अतिक्रमण अथवा भू-उपयोग में अनधिकृत परिवर्तन पर भी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।

एनजीटी ने स्पष्ट किया है, नियमों के उल्लंघन या आदेशों की अनदेखी पर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी । कलेक्टरों को कार्रवाई की रिपोर्ट निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

9 हजार के कर्ज में 10 एकड़ जमीन नीलाम, दो अधिकारियों को 3-3 साल की सजा

भोपाल। 8775 रुपए के मामूली कर्ज की वसूली के लिए 10 एकड़ जमीन नीलाम करने वाले सहकारिता विभाग के दो अधिकारियों को करोड़ों रुपये की जमीन को लाखों रुपये में बेचने के मामले में लोकायुक्त की विशेष अदालत ने दो अधिकारियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोनों आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अदालत ने मामले में भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग को गंभीर अपराध माना है।

मामला उस समय सामने आया जब जमीन मालिक पर करीब ?9 हजार की देनदारी थी। आरोप है कि संबंधित अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी करते हुए उसकी करीब 10 एकड़ जमीन की नीलामी प्रक्रिया आगे बढ़ाई। जमीन का वास्तविक बाजार मूल्य करोड़ों रुपये बताया गया, अधिकारियों ने इसे बेहद कम कीमत में बेच दिया गया।

शिकायत के बाद लोकायुक्त ने मामले की जांच शुरू की। जांच में अधिकारियों की भूमिका, नीलामी प्रक्रिया और जमीन के मूल्यांकन में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य प्रमाण प्रस्तुत किए।

विशेष अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोनों अधिकारियों को दोषी माना और तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। यह फैसला सरकारी पद का दुरुपयोग, आम नागरिक की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले मामलों में महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है।

अफसरों की जवाबदेही तय करे सरकार

भोपाल में नगर निगम की कार्रवाई से व्यापारी परेशान, पूर्व विधायक ने सीएम मोहन यादव से लगाई न्याय की गुहार

भोपाल । राजधानी भोपाल के आवासीय क्षेत्रों में लंबे समय से संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ नगर निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर व्यापारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। इस मामले में हुजूर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार डागा ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर हजारों व्यापारियों के साथ न्याय करने और व्यावसायिक गतिविधियों को वैध करने की मांग की है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए डागा ने कहा कि पिछले करीब एक माह से भोपाल में व्यापार करने वाले हजारों व्यापारी और उनसे जुड़े लाखों कर्मचारी नगर निगम की कार्रवाई से परेशान हैं। नगर निगम द्वारा आवासीय क्षेत्रों में संचालित प्रतिष्ठानों को लेकर तालाबंदी से लेकर नोटिस चस्पा करने तक की कार्रवाई की जा रही है। इससे व्यापारियों में आक्रोश और असंतोष व्याप्त है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दाखिल करेंगे। डागा ने पत्र में उल्लेख किया कि इनमें से अनेक व्यापारी पिछले 30-40 वर्षों से नगर निगम क्षेत्र में अपना व्यवसाय संचालित कर रहे हैं। इस दौरान नगर निगम द्वारा आवासीय क्षेत्रों में खुली दुकानों के मालिकों को गुमास्ता लाइसेंस दिए गए, संपत्ति कर वसूला गया तथा उनके व्यवसाय को नियमित रूप से चलने दिया गया। अब वर्षों बाद इन्हीं प्रतिष्ठानों को आवासीय क्षेत्र का हवाला देकर बंद करने के नोटिस दिए जा रहे हैं।

नगर निगम की भूमिका की भी जांच की जाए

पूर्व विधायक ने कहा कि अचानक व्यावसायिक गतिविधियां बंद होने से व्यापारी, कर्मचारी और उनके परिवार प्रभावित होंगे। उन्होंने मांग की कि कार्रवाई से पहले पूर्व में दी गई अनुमतियों और नगर निगम की भूमिका की भी जांच की जाए। पत्र में उन्होंने अधिकारियों की जवाबदेही तय करने, जिन अधिकारियों के कार्यकाल में ऐसे व्यवसाय शुरू हुए उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई करने तथा आवासीय क्षेत्रों में लंबे समय से संचालित दुकानदारों को पहले नियमित करने की मांग की है। साथ ही भविष्य के लिए स्पष्ट और सख्त नियम बनाए जाने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि हजारों दुकानदारों की परेशानी को देखते हुए मामले की जानकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी दी जाए तथा वर्तमान व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कम से कम एक बार के लिए आवश्यक अनुमति प्रदान की जाए।

अब 19 सितंबर को इंदौर आएंगे राहुल गांधी

भोपाल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का इंदौर दौरा अब 12 सितंबर की जगह 19 सितंबर को होगा। राहुल गांधी के प्रस्तावित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के लिए कांग्रेस ने पहले नेहरू स्टेडियम को चुना था और जिला प्रशासन से इसकी अनुमति मांगी थी। हालांकि, प्रशासन ने कोर्ट का हवाला देते हुए नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद कांग्रेस ने कार्यक्रम का स्थल बदलने का फैसला किया है।

अब राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम 19 सितंबर को इंदौर के रीजनल पार्क में आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस की ओर से कार्यक्रम की नई तारीख और नए स्थल को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों और युवाओं के शामिल होने की संभावना है।

नेहरू स्टेडियम पर प्रशासन ने नहीं दी अनुमति

कांग्रेस ने राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए नेहरू स्टेडियम की अनुमति मांगी थी। पार्टी की ओर से कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई थीं, लेकिन जिला प्रशासन ने नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। प्रशासन की ओर से इसके लिए कोर्ट से जुड़े मामले का हवाला दिया गया। अनुमति नहीं मिलने के बाद कांग्रेस के सामने कार्यक्रम का स्थान बदलने का विकल्प बचा।

अब रीजनल पार्क में जुटेंगे छात्र

नेहरू स्टेडियम की जगह अब रीजनल पार्क को कार्यक्रम स्थल बनाया गया है। कांग्रेस का फोकस छात्रों और युवाओं को कार्यक्रम से जोडने पर है। 'छात्रों की गूंज' के जरिए राहुल गांधी छात्रों से सीधे संवाद करेंगे और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। राहुल गांधी के इंदौर कार्यक्रम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी भी शुरू हो गई थी। कार्यक्रम स्थल को लेकर प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने के बाद राजनीतिक हलकों में भी इसे लेकर चर्चा तेज हुई। कांग्रेस ने अब विवाद को आगे बढ़ाने के बजाय कार्यक्रम का स्थल बदलकर रीजनल पार्क करने का निर्णय लिया है।

बारिश से भी तैयारियों में आई दिक्कत

कार्यक्रम की तारीख आगे बढ़ाने के पीछे लगातार हो रही बारिश भी एक वजह बताई जा रही है। इंदौर में बारिश के कारण खुले स्थान पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों में दिक्कतें आ रही थीं। ऐसे में कांग्रेस ने तैयारियों के लिए अतिरिक्त समय लेते हुए कार्यक्रम को 12 सितंबर से बढ़ाकर 19 सितंबर करने का फैसला किया है।

पहले राहुल गांधी का इंदौर दौरा 12 सितंबर को प्रस्तावित था। अब यह कार्यक्रम 19 सितंबर को होगा। यानी कार्यक्रम को एक सप्ताह आगे बढ़ाया गया है।

मप्र में पुलिस भर्ती का बड़ा मौका, 9 सितंबर से आवेदन

एसआई और सूबेदार के 507 पदों पर होगी भर्ती

भोपाल। मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। कर्मचारी चयन मंडल ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर और सूबेदार भर्ती परीक्षा-2026 का विज्ञापन जारी कर दिया है। भर्ती प्रक्रिया के जरिए 507 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 सितंबर से शुरू होकर 23 सितंबर 2026 तक चलेगी। अभ्यर्थियों को आवेदन में सुधार के लिए 28 सितंबर तक का समय दिया गया है। भर्ती परीक्षा 28 अक्टूबर 2026 से दो पालियों में आयोजित की जाएगी।

भर्ती में सबसे ज्यादा पद उप निरीक्षक (जिला पुलिस बल) के हैं। 312 पद उप निरीक्षक, जिला पुलिस बल, 81 पद सूबेदार, 69 पद उप निरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल, और 45 पद आर्म्स, फोटो, फिंगरप्रिंट समेत अन्य तकनीकी शाखाएं इस तरह पुलिस विभाग की अलग-अलग शाखाओं में कुल 507 पद भरे जाएंगे।

विशेष सशस्त्र बल में सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी

भर्ती नियमों में पद के अनुसार पात्रता अलग-अलग रखी गई है। विशेष सशस्त्र बल के उप निरीक्षक पद पर केवल पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। अन्य पदों पर महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा। इसलिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों के लिए पदवार पात्रता और आरक्षण नियमों को ध्यान से देखना जरूरी होगा। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 500 रुपये रखा गया है। मध्य प्रदेश के निवासी ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को 250 रुपये शुल्क देना होगा। इसके अतिरिक्त आवेदन के माध्यम के अनुसार शुल्क भी लगेगा। कियोस्क के माध्यम से आवेदन पर 60 रुपये अतिरिक्त और एमपी ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन करने पर 20 रुपये अतिरिक्त लगेंगे। विभागीय उम्मीदवारों के लिए शुल्क अलग रखा गया है। अनारक्षित वर्ग के विभागीय उम्मीदवारों को 200 रुपये, जबकि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये शुल्क देना होगा।

कर्मचारी चयन मंडल ने अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण, मूल निवास और जरूरी दस्तावेजों से संबंधित पात्रता जांचने की सलाह दी है।

गरुड़ बताएगा बाढ़ आई तो कितने घर डूबेंगे

भोपाल । मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जहां सभी 413 नगरीय निकायों के हर घर और शहरी व्यवस्थाओं का त्रङ्घस् डेटा तैयार किया गया है। 'गरुड़ एमपी' सिस्टम के जरिए अब बाढ़ आने से पहले ही संभावित खतरे का पता लगाया जा सकेगा। इंदौर, भोपाल समेत सभी छोटे-बड़े शहरों में नदी-नालों का जलस्तर बढने पर प्रभावित होने वाले इलाकों, घरों और आबादी का पहले ही नक्शा तैयार किया जाएगा। इससे राहत और बचाव की तैयारी समय रहते की जा सकेगी।

गरुड़ ऐप में अलग-अलग जलस्तर के आधार पर सिमुलेशन की सुविधा विकसित की गई है। पानी तय स्तर से ऊपर बढने पर सिस्टम नक्शे पर बता सकेगा कि कौन सा वार्ड प्रभावित होगा, कितने घर और संपत्तियां पानी की चपेट में आ सकती हैं और कितनी आबादी प्रभावित होगी। इसके साथ ही संभावित बाढ़ की चपेट में आने वाले स्कूल, अस्पताल और दूसरी जरूरी सुविधाओं की भी पहचान की जा सकेगी। इससे प्रशासन राहत और बचाव की तैयारी पहले से कर सकेगा।

413 निकायों का डेटा एक सिस्टम में

मध्यप्रदेश ने सभी 413 नगरीय निकायों के भौगोलिक आंकड़ों को एक ही सिस्टम में जोड़ा है। इसमें इंदौर, भोपाल समेत बड़े शहरों और छोटे कस्बों के घरों के साथ सड़क, पानी की पाइपलाइन, सीवरेज, जलाशय और जमीन के उपयोग से जुड़ी जानकारी शामिल है। इस डेटा के जरिए किसी इलाके को उसके वास्तविक स्थान और आसपास की शहरी व्यवस्थाओं के साथ देखा जा सकेगा।

टैक्स और अवैध निर्माण की भी निगरानी

गरुड़ का इस्तेमाल सिर्फ बाढ़ प्रबंधन के लिए नहीं होगा। इसके जरिए संपत्ति कर की वसूली, अवैध निर्माण, मास्टर प्लान के उल्लंघन, पानी और सीवरेज की पाइपलाइन की निगरानी तथा झुग्गी बस्तियों के सर्वे का काम भी किया जाएगा।

हर सोमवार कलेक्टरों को देनी होगी कामकाज की रिपोर्ट

सीएम ने लॉन्च किया जन विश्वास अभियान पोर्टल, एक महीने में 5.64 लाख शिकायतें निपटाईं

भोपाल । प्रदेश में जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण और अधिकारियों की मैदानी सक्रियता की निगरानी के लिए शुरू किए गए जन विश्वास अभियान के तहत अब जिलों की गतिविधियों और उपलब्धियों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान पोर्टल शुरू किया गया है। सीएम डॉ मोहन यादव ने आज मंत्रालय में इस पोर्टल को लॉन्च किया। इस अभियान की शुरुआत 7 अगस्त 2026 को हुई थी और अब तक चार सप्ताह पूरे हो चुके हैं।

अभियान के पहले महीने में 5 लाख 64 हजार से अधिक सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का निराकरण किया गया है। वहीं, लोक सेवा गारंटी के तहत दर्ज 8 लाख 6 हजार से अधिक आवेदनों का भी निराकरण किया जा चुका है। अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक सप्ताह में एक दिन फील्ड में जाकर जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं।

हर सोमवार पोर्टल पर अपडेट होगी जिले की रिपोर्ट

पोर्टल पर जिलों से हर सप्ताह अभियान के दौरान किए गए कामों की जानकारी दर्ज की जाएगी। इसमें अधिकारियों के भ्रमण, निरीक्षण, जनसंवाद, उद्यम संवाद, यशस्वी संवाद और मीडिया संवाद के साथ जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों की जानकारी भी शामिल होगी। इसके अलावा नीतिगत विषय, अभियान के दौरान दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश, जिले के प्रमुख नवाचार और राज्य सरकार को भेजे जाने वाले प्रमुख सुझाव भी पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे।

संभागायुक्त करेंगे नियमित मॉनिटरिंग

अभियान के दौरान शुक्रवार तक किए गए कार्यों की जानकारी संबंधित जिला कलेक्टर को अगले सोमवार तक अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। संभागायुक्त इसकी नियमित मॉनिटरिंग करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक सोमवार को जिलों की पूरी जानकारी अपलोड हो गई है।

विभागों को भी मिलेगी निगरानी की जिम्मेदारी

पोर्टल की मॉनिटरिंग के लिए सभी विभागों को लॉगिन आईडी दी जा रही हैं। कलेक्टरों द्वारा हर सप्ताह दर्ज की जाने वाली जानकारी की उच्च स्तर पर नियमित समीक्षा होगी। इसके जरिए जिलों से जुड़े ऐसे मामलों को चिह्नित किया जाएगा, जिनके निराकरण के लिए राज्य स्तर पर समन्वय की जरूरत है।

नाम बदलने से इतिहास नहीं बदलेगा...उमंग ने कहा- ये महान नेताओं के खिलाफ साजिश

भोपाल। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) को तीन हिस्सों में बांटने और उसका नाम बदलने के फैसले को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए इसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के योगदान को मिटाने की कोशिश बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आरजीपीवी के नाम से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाना भाजपा सरकार की 'ओछी मानसिकता' का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के कार्यकाल में देश ने आधुनिक तकनीक की दुनिया में प्रवेश किया और सूचना क्रांति व कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई।

कमलनाथ ने भाजपा पर कांग्रेस सरकार के समय किए गए कार्यों की सिर्फ नाम पट्टिकाएं बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय से राजीव गांधी का नाम नहीं हटाया जाना चाहिए। कमलनाथ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि नाम बदलकर इतिहास नहीं बदल सकते। अच्छे और बुरे हर काम का हिसाब होता है, हम भी हिसाब करेंगे।

कंप्यूटर क्रांति के जनक का नाम हटाना दुर्भाग्यपूर्ण

वहीं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी सरकार के फैसले की घोर निंदा की। उन्होंने कहा कि देश में सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति लाने और कंप्यूटर युग की शुरुआत करने में राजीव गांधी का महत्वपूर्ण योगदान था। सिंघार ने सवाल उठाया कि जिन नेताओं ने देश के लिए अपना समय दिया, योगदान दिया और शहादत दी, उनके नाम हटाना क्या उचित है? सिंघार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं था, क्या भाजपा की मोहन यादव सरकार उनके नाम पर संस्थानों के नाम रखना चाहती है? उन्होंने इसे देश के महान नेताओं के खिलाफ साजिश बताया। उन्होंने कहा कि नाम दिलों से नहीं हटाया जा सकता। सिंघार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से नाम हटाने की मानसिकता बदलने की मांग की और कहा कि राजीव गांधी ने देश में सूचना क्रांति की जो नींव रखी, उसी का परिणाम है कि आज भारत आईटी के क्षेत्र में पूरी दुनिया में जाना जाता है।

इंदौर में 11 अक्टूबर को भारत-वेस्टइंडीज टी-20, टिकट दर घोषित

1000 से 12,500 रुपये तक कीमत; ऑनलाइन बिक्री की तारीख का इंतजार, अधिकतम चार टिकट खरीद सकेंगे

इंदौर। होलकर स्टेडियम में 11 अक्टूबर को होने वाले भारत-वेस्टइंडीज टी-20 अंतरराष्ट्रीय के टिकटों की दरें घोषित हो गई हैं। दर्शकों को टिकट के लिए 1000 से 12,500 रुपये तक खर्च करने होंगे, जबकि ऑनलाइन बिक्री शुरू होने की तारीख अभी तय नहीं हुई है। भारत-वेस्टइंडीज का यह मुकाबला इंदौर में होने वाला इस श्रृंखला का तीसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय है।

एमपीसीए के मानद सचिव सुधीर असनानी ने बताया कि टिकट केवल ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। इसके लिए 'डिस्ट्रिक्ट बाय जोमैटो' को आधिकारिक ऑनलाइन टिकटिंग एजेंसी बनाया गया है। टिकट मोबाइल ऐप और ह्टह्ड्ढ़-ह्लह्वह्म्ह्य.द्बद्ध वेबसाइट के माध्यम से खरीदे जा सकेंगे।

ईस्ट गैलरी के ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर-रेगुलर और फर्स्ट फ्लोर-प्रीमियम के टिकट क्रमशः 1000, 1250, 1400 और 1700 रुपये होंगे। वेस्ट गैलरी में यही दरें क्रमशः 1100, 1350, 1500 और 1800 रुपये रहेंगी।

साउथ पवेलियन में थर्ड फ्लोर 5500, लोअर 6500, सेकंड फ्लोर 7500 और फर्स्ट फ्लोर 8500 रुपये का होगा। फर्स्ट फ्लोर-फूड बॉक्स हॉस्पिटैलिटी टिकट 11,000 रुपये, जबकि लोअर-लाइव हॉस्पिटैलिटी टिकट 12,500 रुपये का होगा।

एक व्यक्ति अधिकतम चार टिकट खरीद सकेगा

एक व्यक्ति अधिकतम चार टिकट खरीद सकेगा। टिकट एक ही या अलग-अलग श्रेणियों के हो सकते हैं। ऑनलाइन बिक्री की तारीख के साथ छात्र रियायत और विशेष रूप से दिव्यांग दर्शकों के सेक्शन की टिकट दरें भी घोषित की जाएंगी।

टिकट कीमत में प्रवेश

जावी हर्नांडेज ने संभाली नीदरलैंड फुटबॉल टीम के कोच पद की कमान

स्थानीय लोगों को कोचिंग स्टाफ में शामिल करेंगे

एम्सटर्डम । नीदरलैंड फुटबॉल संघ ने स्पेन के पूर्व फुटबॉलर जावी हर्नांडेज को अपनी फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच बनाया है। अब उन्हें टीम को आगे ले जाने की जिम्मेदारी मिली है। वह साल 2030 तक फीफा विश्व कप तक टीम के कोच बने रहेंगे। जावी ने पद संभालते हुए अपनी टीम के लिए अपनी योजनाओं का भी खुलासा किया, जिसमें स्थानीय ज्ञान को शामिल करने पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने कहा, हमारा इरादा एक ऐसा कोचिंग स्टाफ बनाने का है जिसमें डच लोग भी शामिल हो।

नये कोच ने कहाकि एफसी बार्सिलोना एकेडमी में रहने और जोहान क्रूफ तथा रिनस मिशेल्स जैसे डच दिग्गजों से मिली सीख के कारण, वह डच फुटबॉल से एक विशेष संबंध महसूस करते हैं। उन्होंने यहां तक कहा, आप कह सकते हैं कि मैं एक तरह से डच फुटबॉल का ही एक बेटा हूं। उन्होंने लुइस वैन गाल, जिनके नेतृत्व में उन्होंने बार्सिलोना में अपना डेब्यू किया, और फ्रैंक रिजकार्ड जैसे अन्य महान कोचों को भी याद किया, जिन्होंने उन्हें एक खिलाड़ी और एक कोच, दोनों के तौर पर बेहतर बनाया।

गौरतलब है कि एक खिलाड़ी के तौर पर, जावी को फुटबॉल की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर्स में से एक माना जाता है। वह 2010 में फीफा विश्व कप जीतने वाली स्पेन टीम के अभिन्न अंग थे, जहाँ उन्होंने अपनी असाधारण पासिंग रेंज और खेल को नियंत्रित करने की क्षमता का प्रदर्शन किया। दिग्गज क्लब बार्सिलोना के लिए उन्होंने कुल 17 सीजन खेले और अपने क्लब करियर में भी उन्होंने अपार सफलता हासिल की जावी को कोचिंग का भी अच्छा अनुभव है। उन्होंने साल 2019 में अपना कोचिंग करियर शुरू किया, पहले 2019 से 2021 तक अल साद का प्रबंधन किया, और फिर 2021 से 2024 तक अपने पूर्व क्लब बार्सिलोना के कोच रहे। अपने कोचिंग करियर में भी उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की है, क्लब के साथ कई घरेलू ट्रॉफियां जीती हैं, जिसमें 2022-23 में बार्सिलोना को स्पैनिश सुपर कप का खिताब दिलाना शामिल है।

मेसी की कमाई के सामने दूर-दूर तक नहीं टिकते क्रिकेटर

बार्सिलोना। अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनल मेसी ने अचानक ही खेल से संन्यास लेकर सभी को हैरान कर दिया है। मेसी ने मैदान में जिस तेजी से गोल किये हैं। उसी तेजी से अपने दो दशक के करियर में कमाई भी की है। वह विश्व के सबसे धनी खिलाड़ियों में से एक है। फुटबॉल दुनिया के सबसे लोकप्रिय और देखे जाने वाले खेलों में से एक है, और इसमें शीर्ष खिलाड़ियों को भारी भरकम राशि मिलती है और ये क्रिकेटरों को मिलने वाली रकम से कई गुना अधिक है या यूं कहें तो स्टार क्रिकेटर जितनी रकम अपने करियर में कमा पाते हैं उतनी तो दिग्गज फुटबॉलर एक साल में ही कमा लेते हैं।

ऐसे में मेसी जैसे दिग्गज खिलाड़ी की उनकी कमाई और संपत्ति कितनी होगी इसके अनुमान लगाये जा सकते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मेसी की

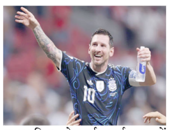

अनुमानित नेटवर्थ वर्तमान में लगभग 1.1 अरब डॉलर है। भारतीय मुद्रा में यह आंकड़ा 10,450 करोड़ रुपये के करीब बैठता है। यह राशि उनके पिछले दो दशकों के शानदार करियर और खेल जगत में उनके अद्वितीय प्रभाव को दिखाती है।

केवल उनकी कुल संपत्ति ही नहीं, बल्कि उनकी सालाना कमाई भी जानकार आप हैरान हो जाएंगे। फोर्ब्स की 2026 की सूची के अनुसार, मेसी विश्व के तीसरे सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट थे, जिनकी सालाना आय 140 मिलियन डॉलर बताई गई थी। भारतीय रुपये में यह 1300 करोड़ रुपये से अधिक है। वहीं अगर भारतीय स्टार क्रिकेटरों से तुलना करें तो विराट कोहली की कुल नेटवर्थ करीब 1050 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसका मतलब यह है कि मेसी एक साल में जितना कमाते हैं, वह विराट कोहली की पूरी संपत्ति से भी ज्यादा है। वहीं, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की नेटवर्थ लगभग 230 करोड़ रुपये बताई जाती है, जो मेसी की सालाना कमाई से लगभग छह गुना कम है। यह आंकड़े बताते हैं कि फुटबॉल और क्रिकेट के शीर्ष खिलाड़ियों की कमाई में कितना बड़ अंतर है।

मेसी की सालाना कमाई का 140 मिलियन डॉलर की कमाई का आधा हिस्सा, तकरीबन 70 मिलियन डॉलर, मैदान में खेलकर आता है जबकि बचा हुआ 70 मिलियन डॉलर अन्य स्रोतों से आता है।

पुजारा ने अपनी पसंदीदा टीम में इन तीन दिग्गजों को शामिल नहीं किया

मुम्बई। पूर्व टेस्ट क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने अपनी पसंदीदा अंतिम ग्यारह टीम घोषित की है। पुजारा ने इस टीम में उन्हीं खिलाड़ियों को शामिल किया है। जिनके साथ उन्होंने अपने करियर में खेला था। पुजारा ने साल 2010 से 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 103 टेस्ट मैचों में 7195 रन बनाए। उन्होंने हालांकि पांच एकदिवसीय मैच भी खेले पर वह इस प्रारुप में आगे नहीं खेल पाये। पुजारा ने अपने दौर की टीम के , पांच वर्तमान खिलाड़ियों और छह पूर्व दिग्गजों को अपनी पसंदीदा टीम में शामिल किया है पर हैरानी की बात ये है कि उनकी इस टीम में तीन दिग्गज खिलाड़ियों महेन्द्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे के नाम नहीं हैं।

इस टीम में पुजारा ने केवल उन्हीं खिलाड़ियों को रखा है जिनके साथ उन्होंने अपने 13 साल के करियर में खेला था। सलामी बल्लेबाज के तौर पर उन्होंने राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग को रखा है। द्रविड़ ने साल 1996 से 2012 तक भारत के लिए 13265 टेस्ट रन बनाए, और आक्रामक बल्लेबाज वीरेन्द्र सहवाग के साथ उन्होंने साल 2001 से 2013 तक 103 टेस्ट में 8503 रन बनाये। पुजारा ने अपनी इस टीम में खुद को अपनी पसंदीदा तीसरे नंबर पर रखा है।

मध्यक्रम में उन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को चौथे और विराट कोहली को पांचवें नंबर पर रखा है। वहीं छठे नंबर पर पुजारा ने वीवीएस लक्ष्मण को चुना, जो अजिंक्य रहाणे की जगह लेते दिख रहे हैं। यह फैसला थोड़ा आश्चर्यजनक है क्योंकि पुजारा ने अपने टेस्ट करियर में काफी समय तक रहाणे के साथ खेला।

वहीं विकेटकीपर के रूप में

पुजारा ने महेंद्र सिंह धोनी के बजाय युवा ऋषभ पंत को तरजीह दी है, जिसकी वजह ऑस्ट्रेलिया में इस बल्लेबाज के साथ उनकी कुछ यादगार साझेदारियां बताई जाती हैं।

गेंदबाजी में उन्होंने दो स्पिनरों रवींद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन को शामिल किया है। तेज गेंदबाज के तौर पर उन्होंने जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को रखा है।

पुजारा ने ईशांत शर्मा को 12वें खिलाड़ी के रूप में रखा और कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए वे तीन तेज गेंदबाजों के साथ भी जा सकते हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की जरूरत पड़ी तो हार्दिक पांड्या उनकी सूची में शामिल हो सकते हैं। इस चयन से यह स्पष्ट है कि पुजारा ने उन खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी है जिनके साथ उन्होंने मैदान पर और बाहर गहरा संबंध साझा किया और जिनके खेल से वह व्यक्तिगत रूप से प्रभावित रहे।

पुजारा की अंतिम ग्यारह - राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, चेतेश्वर पुजारा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, वीवीएस लक्ष्मण, ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी।

सभी प्रारुपों में बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं गुरनूर

बेंगलुरु। श्रीलंका दौरे में अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करने वाले भारतीय टीम के युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बरार का लक्ष्य सभी प्रारुपों में अच्छा प्रदर्शन कर टीम में जगह बनाना है। गुरनूर ने श्रीलंका में टेस्ट प्रारुप में जबरदस्त गेंदबाजी की थी। उनका कहना है कि वह किसी एक प्रारुप तक ही सीमित नहीं रहना चाहते हैं। साथ ही कहा कि पिछले तीन महीनों में अनुभवी खिलाड़ियों जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के साथ समय बिताने से उन्हें अपनी गेंदबाजी में निरंतरता हासिल करने में सहायता मिली है। बरार का अगला लक्ष्य अब एक ऐसा तेज गेंदबाज बनना है जो सभी प्रारुपों में खेल सके और काम के बोझ को प्रभावी ढंग से संभाल सके।

बरार ने अपने राष्ट्रीय करियर की शुरुआत अच्छे से की है, जहां उन्होंने छह एकदिवसीय मैचों में 11 विकेट लिए हैं, जिसमें उनकी इकॉनमी रेट लगभग 7 रहा है। अफगानिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज के दौरान राष्ट्रीय टीम के साथ बिताए गए समय और लीग के बारे में मिली नई जानकारियों के बाद, बरार को लगता है कि वे अपने प्रदर्शन में और सुधार कर सकते हैं।

उन्होंने जोर देकर कहा, शुरू से ही मेरा एक ही लक्ष्य रहा है। मुझे अपने शरीर को इस तरह से तैयार करना है कि चाहे मैं कितने भी ओवर या कितनी भी गेंदें फेंकूं, मेरे शरीर पर कोई बुरा असर न पड़े। मुझे गेंदबाजी करने में बहुत मजा आता है।

भारतीय टीम के मुख्य कोच कोच गौतम गंभीर, बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल और जसप्रीत बुमराह जैसे सीनियर साथियों के साथ बातचीत से उन्हें अपनी गेंदबाजी को बेहतर बनाने में सहायता मिली है।

लक्ष्य पहले ही दौर में बाहर हुए, श्रीकांत दूसरे दौर में पहुंचे

ध्रुव कपिला और तनीशा क्रास्टो की जोड़ी भी जीती

शेनझेन। भारत के लक्ष्य सेन चीन के शेनझेन में खेली जा रही चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले ही दौर में हार के साथ ही बाहर हो गये हैं। लक्ष्य को पुरुष एकल में कनाडा के विक्टर लाई ने सीधे गेम में 14-21 7-21 से हराया। ये मुकाबला आधे घंटे से कुछ अधिक समय में ही समाप्त हो गया। यह लक्ष्य की कनाडाई खिलाड़ी के हाथों तीसरी हार थी। उन्होंने विक्टर के खिलाफ एकमात्र जीत इसी साल मार्च में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में हासिल की थी।

वहीं एक अन्य पुरुष एकल मुकाबले में भारत के ही अनुभवी खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के ची यू जेन को 21-16 21-15 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनायी। इसके अलावा मिश्रित युगल में भारत के ध्रुव कपिला और तनीशा क्रास्टो की जोड़ी भी जीत के साथ ही अगले दौर में पहुंच गयी। ध्रुव कपिला और तनीशा क्रास्टो ने थाईलैंड के टोम्माकोर्न साएहेंग और टोनिचा साएहेंग को 21-8 21-9 से हराया। विश्व चैंपियनशिप 2021 के कांस्य पदक विजेता भारत के लक्ष्य ने लगातार गलतियां कीं और विश्व में नौवें नंबर के खिलाड़ी लाई से 38 मिनट में 14-21 7-21 से हार गए। स्टार खिलाड़ी लक्ष्य इस बार लय में नहीं दिखे। कनाडाई खिलाड़ी विक्टर के खिलाफ वह शुरु से ही सहज नहीं दिखे। उन्होंने लगातार कई गलतियां कीं जिसका कनाडाई खिलाड़ी ने पूरा लाभ उठाया। पहले गेम में ही लक्ष्य ने 4-0 से शुरुआती बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद लाई ने जल्द ही नियंत्रण हासिल कर लिया। उन्होंने लक्ष्य को लय हासिल नहीं करने दी और आसानी से पहला गेम जीत लिया। इसके बाद लक्ष्य दूसरे गेम में भी किसी भी टिक नहीं पाये और कनाडाई खिलाड़ी ने लगातार दबाव बनाए रखकर उन्हें किसी प्रकार का कोई अवसर नहीं दिया। लक्ष्य शुरुआत में ही पिछड़ गये और ये अंतर बीच के ब्रेक के दौरान 4-11 तक पहुंच गया ऐसे में लक्ष्य के पास वापसी का कोई अवसर नहीं बचा।

अमृतसर सूरमा 250 से अधिक रन बनाने के बाद भी हारी

मोहाली। शेरे पंजाब टी20 लीग में अभिषेक शर्मा की अमृतसर सूरमा टीम को 264 रन बनाकर भी हार का सामना करना पड़ा है। इस साल शुरु हुई शेर-ए-पंजाब टी20 लीग के 5वें ही मैच में अमृतसर सूरमा को जलंधर वारियर्स ने हराया। इस मैच में अभिषेक की कप्तानी वाली अमृतसर टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 264 रन बनाये। इसके बाद भी उसे हार का सामना करना पड़ा। टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा की टीम को लगातार दूसरी हार मिली है। वहीं सत्र के पहले मैच में भी अभिषेक की टीम 250 रन से ज्यादा बनाने के बाद भी जीत नहीं पायी।

वही जलंधर की टीम टी20 इतिहास में दूसरी बार किसी बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए जीती है।

अमृतसर सूरमा की ओर से जहां कप्तान अभिषेक शर्मा ने 36 गेंदों में 82 रनों की पारी खेली थी। वहीं नमन धीर ने 117 रन बनाये थे। अपनी इस पारी में नमन ने 56 गेंदों में 10 छक्के और 7 चौके भी लगाए। वहीं, अभिषेक ने 7 छक्के और 5 चौके लगाये। टीम की ओर से जसप्रीत सिंह ने भी 12 गेंद में 33 रन बनाए थे। इन तीन के अलावा और कोई भी बल्लेबाज अधिक रन नहीं बना पाया।

इसके बाद जीत के लिए मिले लक्ष्य को जलंधर वारियर्स की टीम ने 16.5 ओवर में ही 265 रन बनाकर हासिल कर लिया। जलंधर की ओर से कप्तान प्रभसिमरन सिंह ने 47 गेंद में नाबाद 125 रनों की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 14 चौके और 8 छक्के भी लगाये। वहीं अनमोल मल्होत्रा ने भी पांच चौक और तीन छक्के लगाकर 23 गेंद में 53 रन बनाए।

आईसीसी ने श्रीलंका से महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी वापस ली

कोलंबो। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने श्रीलंका से साल 2027 में होने वाली पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी वापस ले ली है। इस बारे में हालांकि अंतिम फैसला आईसीसी की अगली बैठक में होगा पर इतना तय है कि महिला चैम्पियंस ट्रॉफी अब श्रीलंका में नहीं होगी। अब इसकी मेजबान किये मिलती है ये देखना होगा।

आईसीसी के इस फैसले से श्रीलंकाई बोर्ड को करारा झटका लगा है। इस टूर्नामेंट का आयोजन 14 से 28 फरवरी 2027 तक श्रीलंका में होना था। जिसके लिए बोर्ड ने तैयारियां भी शुरू कर दीं थीं।

आईसीसी ने यह फैसला श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) प्रशासन में सरकारी हस्तक्षेप को देखते हुए किया है। आईसीसी का मानना है कि सदस्य बोर्डों का कामकाज स्वतंत्र रुप से चलना चाहिये। वह सरकार के हस्तक्षेप के खिलाफ है। क्रिकेट का संचालन सरकार द्वारा नियुक्त ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी कर रही है।

गौरतब है कि पहले भी आईसीसी ने साल 2023 में भी सरकारी हस्तक्षेप के चलते श्रीलंकाई क्रिकेट को निलंबित कर दिया था। इसके बाद साल 2024 पुरुष अंडर-19 विश्व कप की मेजबानी भी उससे वापस लेते हुए दक्षिण अफ्रीका में स्थानांतरित कर दी गयी थी। आईसीसी का कहना है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के चुनाव शीघ्र कराये जायें जिससे उसका कामकाज सही से चले।

आईसीसी के मेजबानी वापसी लेने के फैसले से श्रीलंकाई बोर्ड की साख तो प्रभावित हुई है।

पीसीबी ने पिछले तीन साल में बदले आधा दर्जन कोच, हेसन कितने समय रहेंगे ?

लाहौर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इंग्लैंड दौरे पर खराब प्रदर्शन के बाद टीम ने एक बार फिर मुख्य कोच सहित सात खिलाड़ियों को बदल दिया है। पिछले तीन साल में पाक क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने 6 कोच बदल दिये हैं। मुख्य कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी उनके पदों से हटा दिया गया है। यहां तक कि मुख्य चयनकर्ता मिस्बाह उल हक भी बाहर कर दिये गये हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी पाक बोर्ड की किरकिरी हुई है।

इसी बीच न्यूजीलैंड के माइक हेसन ने सरफराज अहमद की जगह हेड कोच का पद संभाला है। हेसन पिछले महज तीन सालों में पाकिस्तान टेस्ट टीम के छठे कोच बने हैं। पीसीबी लंबे समय से कोच बदलता रहा है। पीसीबी ने अपने देश के कुछ पूर्व क्रिकेटरों पर भी कोच बनाय पर सभी को एक के बाद एक बाहर कर दिया। वहीं इससे पहले के सभी विदेशी कोच पाक क्रिकेट में सम्मान नहीं मिलने से छोड़कर चले गये थे। इसमें जैसन गिलेस्पी भी शामिल थे। इससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य कोच की कुर्सी किसी म्यूजिकल चेयर जैसी हो गयी है। इसमें किसी को भी पर्याप्त समय और अधिकार नहीं मिलता। न्यूजीलैंड के ग्रांट ब्रैडबर्न मई 2023 में हेड कोच बने थे पर नवंबर 2023 में, यानी छह महीने से भी कम समय में, उन्हें हटा दिया गया। ब्रैडबर्न के बाद पाकिस्तान के ही मोहम्मद हफीज ने कमान संभाली, लेकिन उनका कार्यकाल भी नवंबर 2023 से फरवरी 2024 तक ही सीमित रहा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के जेसन गिलेस्पी को अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक के लिए, मुख्य कोच बनाया गया। गिलेस्पी ने पद छोड़ने के बाद बोर्ड पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे, जिससे अंदरूनी खींचतान और स्पष्ट हो गई। गिलेस्पी के बाद अजहर महमूद को संक्षिप्त अवधि के लिए कोच बनाया गया। फिर सरफराज अहमद को इसी साल अप्रैल में कोच बनाया गया, जिन्हें मात्र तीन महीने में ही, यानी 135 दिन भी पूरे होने से पहले, हटा दिया गया।

डी कॉक के शतक के बाद भी हारी बारबाडोस, सेंट किट्स 6 विकेट से जीती

सेंट किट्स। कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) 2026 के में सेंट किट्स ने यहां हुए रोमांचक मुकाबले में बारबाडोस ट्राइडेंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। इस मैच में बारबाडोस की ओर से विकेटकीपर-बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने शतक लगाया पर इसके बाद भी उनकी टीम को हार का सामना करन पड़ा है।

इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बारबाडोस ट्राइडेंट्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट पर 217 रन बनाये। बारबाडोस की ओर से बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने तेज से शतक लगाया जबकि जैकरी कार्टर ने अर्धशतक लगाया। डी कॉक ने 57 गेंदों पर ही 11 चौकों और 6 छक्कों के साथ ही 106 रन बना दिये। सलामी बल्लेबाज जैकरी कार्टर ने भी 36 गेंदों में 7 छक्कों की सहायता से 57 रन बनाए। शेफरन रदरफोर्ड ने 26 और कप्तान क्रिस ग्रीन ने 18 रन बनाये, जिससे बारबाडोस ने एक बड़ा लक्ष्य सेंट किट्स को दिया। सेंट किट्स की ओर से नसीम शाह ने 2 विकेट जबकि कप्तान जेसन होल्डर और वानिंदु हसरंगा ने 1-1 विकेट लिया। 218 रनों का पीछा करते हुए सेंट किट्स और नेविस पैट्रियट्स की टीम ने अच्छी शुरुआत की। सलामी बल्लेबाज जॉनसन चार्ल्स और काइल मायर्स ने पहले विकेट के लिए केवल 10.2 ओवर में ही 112 रन बना दिये। मायर्स ने 27 गेंदों पर 29 रन बनाए वहीं चार्ल्स ने केवल 45 गेंदों पर 6 चौकों और 7 छक्कों की सहायता से 78 रन बनाकर अपनी टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचा दिया। दासुन शनाका ने भी तेजी से रन बनाये और 22 गेंदों पर 2 छक्कों और 2 चौकों के साथ 36 रन बनाए। कप्तान जेसन होल्डर ने भी 11 गेंदों पर 18 रन बनाये। वहीं अंतिम ओवरों में आंद्रे फ्लेचर और वानिंदु हसरंगा ने भी तेजी से रन बनाकर सेंट किट्स को जीत दिलाई। फ्लेचर ने 8 गेंदों पर 3 छक्कों की सहायता से नाबाद 22 रन बनाए, वहीं हसरंगा ने 4 गेंदों पर 1 छक्का और 3 चौकों के साथ नाबाद 18 रन बनाकर टीम को 19.1 ओवर में ही 4 विकेट के नुकसान पर 220 रन तक पहुंचाकर जीत दिलायी।

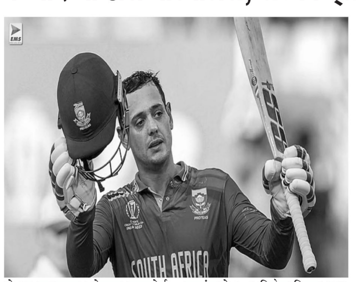

चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर, 400 दुकानें और 20 होटल जलमग्न

उत्तराखंड में बारिश से जुड़े हादसों में 11 की मौत, बिहार के 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में मानसूनी बारिश का तांडव जारी है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। रामघाट क्षेत्र में करीब 400 दुकानें और 20-25 होटल जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन ने तटवर्ती 36 गांवों में हाई अलर्ट जारी किया है। वहीं एक नाविक के तेज बहाव में बहने की सूचना है, जिसकी तलाश जारी है। यूपी के सहारनपुर में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं, जिससे कई संपर्क मार्ग और पुल डूब गए हैं। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर से रत्नेश्वर महादेव मंदिर का लगभग पानी में डूब गया है।

वहीं उत्तराखंड में बारिश से जुड़े हादसों में 11 लोगों की जान चली गई है। मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर नैनीताल, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों में सभी स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। हल्द्वानी में गौला नदी पूरे उफान पर है। पटना सहित कई इलाकों में तेज बारिश से जलभराव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने पटना समेत राज्य के 14 जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रोहतास के मांझर कुंड झरने में फंसे दो युवकों को पानी घटने के बाद सुरक्षित निकाला गया।

झारखंड के पलामू में सोन नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के सेमरिया गांव में बाढ़ के चलते ग्रामीणों को कमर तक पानी में चलकर अंतिम संस्कार के लिए जाना पड़ा। 3 सितंबर को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश का अनुमान है। 4 सितंबर को मध्य प्रदेश में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है।

उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से आम लोगों को जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। बीते कई दिनों से प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर हो रही बारिश के चलते तमाम नदियों को जलस्तर बढ़ गई हैं। गंगा-यमुना नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। यूपी में बीते 24 घंटों में पूर्वांचल के कई जिलों में मूसलाधार बारिश देखने को मिली है। पीलीभीत में शारदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। वहीं बनबसा बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की आशंका है। ऐसे में हालात और खराब हो सकते हैं।

वाराणसी में वरुणा नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह अब पानी तटवर्ती इलाकों में घुस गया है। तमाम घाट पानी में डूब गए हैं। कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। पानी बढ़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने आज भी बांदा, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, झांसी, बरेली समेत 30 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी बारिश का दौर जारी रहेगा।

अंकित शर्मा हत्याकांड

हुसैन की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व आम आदमी पार्टी (आप) पार्षद ताहिर हुसैन द्वारा 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में अपनी सजा और उम्रकैद को चुनौती देने वाली अपील पर दिल्ली पुलिस को नोटिस दिया है। यह मामला समाज में काफी चर्चा में रहा था और बड़े पैमाने पर राजनीतिक एवं सामाजिक बहस को जन्म दिया था।

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की पीठ ने आदेश दिया कि हुसैन की अपील पर दो अन्य दोषियों की अपील के साथ ही सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (एसपीपी) रजत नायर ने कहा कि अभियोजन पक्ष चाहता है कि सभी संबंधित अपीलों पर एक साथ सुनवाई हो, ताकि अदालत का समय बचे और भूमिकाओं का आकलन बेहतर तरीके से हो सके। हाईकोर्ट ने इन सभी मामलों को 2 दिसंबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

इसके पहले, कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन और चार अन्य- जावेद, अनस, नाजिम और कासिम को शर्मा की हत्या का दोषी ठहराया था और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने इन पांचों को आपराधिक साजिश के आरोप से बरी कर दिया था। इसके अतिरिक्त, छह अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया गया था, यह कहते हुए कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ उचित संदेह से परे अपराध साबित करने में विफल रहा। दिल्ली पुलिस ने संकेत दिया है कि वह इन छह आरोपियों को बरी करने के फैसले को चुनौती देने की प्रक्रिया में है।

सजा सुनाते समय, एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह ने इस अपराध को बहुत गंभीर बताया था और कहा था कि अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या की गई थी और उनके शव को जानवर की तरह छोड़ दिया गया था, जिसने समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया था। दिल्ली पुलिस ने हुसैन और अन्य दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए ठंडे दिमाग से की गई और बर्बर हत्या बताया था, उनके शरीर पर मिले 51 घावों का हवाला दिया था। हालांकि, बचाव पक्ष ने तर्क दिया था कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में नहीं आता है। अब, हाईकोर्ट में इस मामले पर आगे की सुनवाई होगी।

मणिपुर विधानसभा : कुकी-ज़ो विधायकों की वापसी, सामुदायिक विरोध के बावजूद

इंफाल। 3 साल से अधिक के अंतराल के बाद, मणिपुर विधानसभा में महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिला। जब कुकी-ज़ो समुदाय के दो विधायक व्यक्तिगत रूप से सत्र में शामिल हुए। यह 3 मई, 2023 को राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद पहली बार है कि पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित इन विधायकों ने कार्यवाही में भाग लिया। सैतु विधानसभा क्षेत्र से विधायक हाओखोलेट किपगेन और साइकुल विधानसभा क्षेत्र से विधायक किमनेओ हाओकिप हैंगशिंग ने विधानसभा के 12वें सत्र की आठवें बैठक के दौरान मौजूद रहे। विधानसभा में प्रवेश करते हुए, विधायक किपगेन ने लंबे समय बाद सत्र में भाग लेने पर अपनी खुशी व्यक्त की। हालांकि, उपमुख्यमंत्री नेमचा किपगेन ने वर्चुअल माध्यम से सत्र में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने पहल का स्वागत कर राज्य में एकता और शांति को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने कहा, जन प्रतिनिधियों की ओर से यह एक अच्छा संकेत है और यह एक स्वागत योग्य कदम है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि समाज के सभी वर्गों के सामूहिक प्रयासों से मणिपुर शांति और सुलह के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने प्रगति का श्रेय राज्य सरकार के विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास बहाली के निरंतर प्रयासों को दिया और समावेशी संवाद, सुलह तथा स्थायी शांति की बहाली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। यह उपस्थिति तब हुई है जब कुकी आदिवासी समुदाय की सर्वोच्च संस्था, कुकी इनपी मणिपुर (केआईएम) ने 31 अगस्त को सभी कुकी-ज़ो विधायकों को एक निर्देश जारी किया था। केआईएम ने विधायकों से कुकी-ज़ो लोगों के लिए अलग प्रशासन की मांग का राजनीतिक समाधान होने तक मणिपुर विधानसभा के आठवें सत्र में भाग लेने के लिए इंफाल की यात्रा न करने को कहा था। केआईएम ने अपने बयान में स्पष्ट किया था कि मणिपुर विधानसभा में कुकी-ज़ो विधायकों की भागीदारी ऐसे समय में, जब कुकी-ज़ो लोगों के भविष्य से संबंधित मूलभूत राजनीतिक प्रश्न अनसुलझे हैं, उनकी सामूहिक राजनीतिक स्थिति और आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं होगी। संस्था ने जोर दिया कि अलग राजनीतिक प्रशासन की उनकी मांग एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे सामान्य विधायी कार्यवाही फिर से शुरू करते समय यूं ही दरकिनार किया जा सके, मानो मौजूदा राजनीतिक संकट पहले ही हल हो चुका हो। इसके बावजूद, इन दो विधायकों की व्यक्तिगत उपस्थिति ने राज्य की जटिल राजनीतिक स्थिति में एक नई परत जोड़ दी है।

पीएम मोदी ने की अपील, जरूरी न हो तो सोना न खरीदें, विदेश घूमने भी न जाएं

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक उथल-पुथल, भू-राजनीतिक टकराव और आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों के बावजूद चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में 7.8 फीसदी की बढ़ोतरी बेहद प्रभावशाली है और उन्होंने इसका श्रेय देश की जनता को दिया। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक से एक वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने देशवासियों से ज्यादा आत्मनिर्भर बनने 'स्वदेशी' को अपनाने की अपनी अपील दोहराई। उन्होंने लोगों से यह आग्रह किया कि जब तक बेहद जरूरी न हो वे विदेश घूमने न जाएं, विदेश में शादियों का आयोजन न करें और सोना भी न खरीदें।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में एक कार्यक्रम से इतर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विदेशी मुद्रा की गैर-जरूरी खर्च को कम करने की सरकार की अपील ऐसे समय में आई है जब भारत कच्चे तेल और उर्वरक के बड़े आयातक के तौर पर बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है। पीएम मोदी ने 'झूठ की गूंज' फैलाने वालों की आलोचना की। शायद उनका तंज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' अ ?भियान पर था। उन्होंने कहा कि जीडीपी वृद्धि दर ने भारतीय

7.8 फीसदी की आर्थिक वृद्धि दर बढ़ते आर्थिक आत्मविश्वास को दर्शाती है

अर्थव्यवस्था के बारे में फैलाए जा रहे 'निराशावाद' के विमर्श को खारिज कर दिया है। मोदी ने कहा कि स्वदेशी और आत्मनिर्भरता से देश के युवाओं के लिए 2047 में आजादी के 100वें साल में विकसित भारत बनाने में मदद मिलेगी।

पीएम मोदी ने कहा कि जून तिमाही में 7.8 फीसदी की आर्थिक वृद्धि दर बढ़ते आर्थिक आत्मविश्वास को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि हमें इस गति को बनाए रखना होगा। इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना जरुरी है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8 फीसदी की दर से बढ़ी। उन्होंने कहा कि यह उनकी सामूहिक प्रतिबद्धता और प्रयासों के कारण संभव हुआ है। भारत ने संघर्षों, युद्धों, अस्थिरता और दुनिया भर में व्याप्त आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद यह उपलब्धि हासिल की है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही हैं, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह बाधित है और 2020 के कोविड काल से अब तक, कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है। उसके बावजूद भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।

वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सरकार द्वारा जारी जीडीपी आंकड़ों को 'आंकड़ों की कलाबाजी' बताया है। ये आंकड़े बार-बार पद्धति बदलकर हासिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नॉमिनल और वास्तविक जीडीपी के बीच का अंतर मुद्रास्फीति को दर्शाता है और सरकार के मुताबिक यह अंतर केवल 2.3 फीसदी है जबकि जून तिमाही में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 9 फीसदी से अधिक रही है। रमेश ने कहा कि यह स्पष्ट विसंगति है। इस विसंगति को मोदी सरकार ने पैदा किया है, जिसने इस साल जीडीपी की गणना की पद्धति में दो बार बदलाव किया है। जून में ठीक जीडीपी के अनुमान के समय सरकार ने अपनी गणना के लिए थोक मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल करना छोड़ दिया।

अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजेगा इसरो, रचेगा नया इतिहास

इस प्रक्षेपण को आम लोग भी देख सकेंगे, ऑनलाइन कराना होगा पंजीकरण

नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 4 सितंबर 2026 को जीएसएलवी-एफ17/ईओएस-05 मिशन के तहत अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में है। इस मिशन का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रात 2:55 बजे तय किया गया है। इस मिशन को धरती के विस्तृत अवलोकन और उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें उपलब्ध कराने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

मीडया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर मिशन की जानकारी साझा की। ईओएस-05 से प्राप्त आंकड़ों का इस्तेमाल कृषि, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में किया जा सकेगा। जियो-इमेजिंग उपग्रह पृथ्वी की सतह की विस्तृत तस्वीरें और जरूरी आंकड़े उपलब्ध कराते हैं। इससे फसलों की स्थिति पर नजर रखने, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों का आकलन करने और बदलती भौगोलिक परिस्थितियों को समझने में मदद मिलती है। उपग्रह से मिलने वाला डेटा सरकारी एजेंसियों को कई अहम फैसले लेने में मदद कर सकता है। विशेष रूप से बाढ़, भूस्खलन, जंगल की आग और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों से मिलने वाली जानकारी राहत एवं बचाव अभियानों के लिए उपयोगी साबित होती है।

इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी और बुनियादी ढांचे की योजना बनाने में भी ऐसे उपग्रहों की भूमिका अहम होती है। इस प्रक्षेपण को आम लोग भी देख सकेंगे। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में मौजूद लॉन्च व्यू गैलरी से रॉकेट के प्रक्षेपण को देखने की सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए इच्छुक लोगों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। रात के अंधेरे में रॉकेट के आसमान की ओर तेजी से बढ़ने का दृश्य दर्शकों के लिए खास अनुभव होगा। इसरो पिछले कई वर्षों से संचार, मौसम, नेविगेशन और पृथ्वी अवलोकन से जुड़े उपग्रहों के जरिए देश की तकनीकी क्षमताओं को मजबूत कर रहा है। जीएसएलवी-एफ17/ईओएस-05 मिशन भी इसी प्रयास का हिस्सा है। इस मिशन की सफलता से पृथ्वी अवलोकन क्षमता को मजबूती मिलने के साथ कृषि, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में अंतरिक्ष आधारित सेवाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

आज दिल्ली में मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की बैठक, सेवा संकल्प अभियान पर करेंगे चर्चा

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने और उनके जन्मदिन के मौके पर बीजेपी देशभर में एक महीने तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान की तैयारी कर रही है। इसकी तैयारियों को लेकर बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के चुनिंदा मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की बुधवार को दिल्ली में बैठक होगी। बैठक बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में उनके आवास पर होगी। देशभर से बीजेपी शासित राज्यों के करीब 25 मंत्री और मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। बैठक में प्रशिक्षण शिविर के दौरान पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन और अब तक किए गए बड़े कामों की जानकारी दी जाएगी, साथ ही इन उपलब्धियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से देशभर में एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। इसका मुख्य फोकस सेवा, जनकल्याण और जनसंपर्क गतिविधियों पर रहेगा।

चार्जशीट तुरंत, फॉरेंसिक रिपोर्ट में दो साल की देरी : सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की चिंता

नई दिल्ली। देश में फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज के लिए राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में फॉरेंसिक जांच के बुनियादी ढांचे की कमी पर गहरी चिंता जाहिर की है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने बताया कि कई बार चार्जशीट, 48 घंटे के भीतर दाखिल हो जाती है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में करीब दो साल लग जाते हैं, जिसका सीधा असर आपराधिक न्याय व्यवस्था पर पड़ता है।

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पहले जमीनी स्तर पर राज्य स्तरीय फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं और उनकी क्षमता को मजबूत करने की जरूरत है, उसके बाद ही नियामक मानकों पर बात हो सकती है। पीठ ने चिंता व्यक्त की कि कई राज्यों में भारी संख्या में मामलों के बावजूद फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं और मानव संसाधनों की भारी कमी है। विशेष रूप से मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में, जहां जांच के लिए प्रयोगशालाओं की कमी के कारण रिपोर्ट आने में लंबा समय लगता है। पंजाब जैसे राज्य का उदाहरण देकर पीठ ने कहा कि वहां ड्रग्स से जुड़े मामलों की संख्या काफी अधिक है, इसकारण प्रयोगशालाओं में लंबी कतार देखने को मिलती है और आरोपी इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि जांच एजेंसियां आरोपी को वैधानिक जमानत का लाभ मिलने से रोकने के लिए कई बार फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किए बिना चार्जशीट दाखिल कर देती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यह आकलन करना आवश्यक है कि वास्तव में देश में कितनी फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं डीएनए विश्लेषण जैसी महत्वपूर्ण जांच करने में सक्षम हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने टिप्पणी की कि यह स्थिति बताती है कि कानून की किताब में क्या व्यवस्था है और जमीन पर उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। याचिकाकर्ता ने ब्रिटेन की तर्ज पर फॉरेंसिक लैब के लिए स्वतंत्र नियामक संस्था बनाने और सभी प्रयोगशालाओं के लिए एक समान मानक तय करने की मांग की थी। इस पर न्यायालय ने संकेत दिया कि सिर्फ नियामक संस्था बनाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि पहले राज्य स्तर पर पर्याप्त संख्या में प्रयोगशालाएं, प्रशिक्षित कर्मचारी और आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी।

न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने स्थिति को प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था किए बिना ही आईआईटी स्थापित करने की मांग जैसा बताया। सुनवाई के दौरान फॉरेंसिक क्षमता बढ़ाने के एक संभावित रास्ते पर भी चर्चा हुई, जिसमें देश के सरकारी कॉलेजों में रसायन विज्ञान और जैव रसायन जैसे विषयों के पीएचडी स्तर के विशेषज्ञों का उपयोग करने का सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि भारत में पहले से मौजूद मजबूत विज्ञान शिक्षा व्यवस्था का उपयोग फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए क्यों नहीं हो सकता।

सुनवाई के अंत में, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी जनहित याचिका में संशोधन करने को कहा, ताकि फोकस केवल राष्ट्रीय नियामक संस्था बनाने की मांग पर नहीं, बल्कि राज्यों में फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की संख्या, मानव संसाधन, डीएनए जांच क्षमता और रिपोर्ट में होने वाली देरी जैसी जमीनी समस्याओं पर भी होना चाहिए।

राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट!

32665 करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी 1899 करोड़ में बिकी, बैंक में 900 करोड़ कैश

मुंबई । भारतीय एडटेक सेक्टर में कभी अरबों डॉलर की वैल्यूएशन हासिल करने वाली अनअकेडमी अब अपग्रेड के हाथों महज 200 मिलियन डॉलर भारतीय मुद्रा में 1899 करोड़ में बिक गई है। यह सौदा कंपनी की 2021मे करीब 3.44 अरब डॉलर यानी लगभग 32,665 करोड़ रुपए का मूल्यांकन किया गया था। इस कंपनी को वैल्यूएशन से करीब 94 फीसदी कम पर ट्रांसफर किया गया है।

रॉनी स्क्रूवाला की अगुवाई वाली अपग्रेड ने अनअकेडमी का अधिग्रहण 100 फीसदी शेयर-स्वैप सौदे के तहत किया गया है। विभिन्न रिपोर्टों में अंतिम सौदे का मूल्य करीब 1,955 से 2,055 करोड़ रुपए के बीच बताया गया है।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है, अनअकेडमी के सह-संस्थापक और सीईओ गौरव मुंजाल के मुताबिक कंपनी के पास करीब 900 करोड़ रुपए नकद थे। उनका सालाना कारोबार लगभग 400 करोड़ रुपए था। अधिकांश कारोबार लाभदायक या लाभ के करीब था। इसके बावजूद कंपनी ने स्वतंत्र रूप से चलने के बजाय अपग्रेड के साथ विलय का रास्ता चुना है।

यह सौदा एडटेक कंपनियों की 2021 की आसमान छूती वैल्यूएशन और आज के वास्तविक बाजार मूल्य के बीच का बड़ा अंतर है। अपग्रेड को इससे यूपीएससी, जी, नीट और गेट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के ऑनलाइन टेस्ट-प्रिपरेशन कारोबार में कंपनी की स्थिति मजबूत होगी यह कारण बताया जा रहा है।

झारखंड में स्वाइन फ्लू का बढ़ता प्रकोप, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

रांची। झारखंड में पिछले 30 दिनों में स्वाइन फ्लू (एच1एन1) संक्रमण के 36 मामले सामने आने से स्वास्थ्य महकमा चिंतित है और पूरी तरह अलर्ट हुआ है। इन मामलों में से 18 मरीज बच्चे और किशोर हैं, जिससे चिंता और बढ़ गई है। बढ़ते खतरे को देखकर राज्य के सभी प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं।

संक्रमण के प्रसार का एक प्रमुख कारण दूसरे राज्यों से यात्रा कर लौटने वाले लोग बताए जा रहे हैं। दिल्ली, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में मौसमी फ्लू के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखकर झारखंड में अंतरराज्यीय आवाजाही पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों और अंतरराज्यीय बस स्टैंडों जैसे उच्च आवाजाही वाले स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है, साथ ही जिला स्तर से रोजाना रिपोर्ट भी मांगी जा रही है। राज्य में संक्रमण की सटीक पहचान के लिए रांची स्थित रिम्स और जमशेदपुर स्थित एमजीएम में एच1एन1 तथा एच3एन2 वायरस की जांच की आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध है। राज्य स्वास्थ्य निदेशालय ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों को संदिग्ध मरीजों की त्वरित पहचान, जांच और समुचित इलाज सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, तमाम मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और सदर अस्पतालों में कम से कम 10-10 अतिरिक्त बेड आरक्षित रखने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई, आवश्यक दवाइयों का स्टॉक, आईसीयू/एचडीयू तथा 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। विभाग द्वारा इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों वाली बीमारियों और गंभीर श्वसन संक्रमण के मामलों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है।

डॉक्टर ने बताया कि एच1एन1 एक इन्फ्लुएंजा वायरस है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन बुजुर्गों, छोटे बच्चों और पहले से गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर से ग्रस्त मरीजों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। चिकित्सकों के मुताबिक तेज बुखार, ठंड लगना, खांसी, गले में खराश, शरीर दर्द और बच्चों में उल्टी-दस्त इसके प्रमुख लक्षण हैं। लक्षण दिखने पर खुद से दवा लेने के बजाय तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी गई है।

दक्षिण सतपुड़ा
राजनीति | समाज | देशकाल
और गांव कनेक्शन की खबरें

पदमेश न्यूज़
शहर | समाज | गांव

बालाघाट एक्सप्रेस

/padmeshmedia /padmeshmedia epaper.balaghatexpress.in E-mail: balaghatexpress@gmail.com

न्यूज गैलरी

ट्रक की टक्कर से कार क्षतिग्रस्त-दवा दुकान संचालक घायल

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। बैहर रोड स्थित लोगुर घाटी में बुधवार दोपहर तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार दवा दुकान संचालक घायल हो गया। घायल प्रतीक पिता प्रवीण जैन 35 वर्ष न्यू हॉस्पिटल कॉलोनी बैहर निवासी है। जिन्हें निजी एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर उपचार के लिए भर्ती कराया गया। जहां उसका इलाज किया गया। कार में सवार एक अन्य युवक को हादसे में चोट नहीं आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रतीक जैन दवा की दुकान संचालित करते हैं। 2 सितंबर को दोपहर के समय प्रतीक जैन अपने साथ एक युवक को लेकर कार से बैहर से बालाघाट आ रहे थे। इसी दौरान लोगुर और बंजारी के बीच सामने से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी।टक्कर लगने से कार क्षतिग्रस्त हो गई और प्रतीक जैन घायल हो गए। दुर्घटना के बाद उन्हें निजी एंबुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती कराया गया। वहीं, कार में उनके साथ मौजूद युवक को किसी प्रकार की चोट नहीं आई। जिला अस्पताल पुलिस ने घायल प्रतीक जैन के बयान दर्ज किए हैं। इसके बाद मामले को आगे की कार्रवाई के लिए घटनास्थल से संबंधित रूपझर थाना को भेज दिया गया है।

बच्चों की लगातार मौत के मामले में बड़ा दबाव, हटाए गए सीएमएचओ उपलप

डिंडोरी सीएमएचओ मनोज पांडेय को सौंपी गई जिला स्वास्थ्य व्यवस्था की कमान, आदिवासी अंचलों में स्वास्थ्य सेवाओं पर उठ रहे सवालों के बीच प्रशासनिक फेरबदल, नए अधिकारी के सामने व्यवस्था सुधारने की बड़ी चुनौती

सिटी रिपोर्टर।
पदमेश न्यूज़। बालाघाट।

जिले के आदिवासी अंचलों में बच्चों की लगातार मौत के मामले ने अब स्वास्थ्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करा दिया है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार उठ रहे सवालों और बढ़ते दबाव के बीच मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) परेश उपलप को उनके पद से हटा दिया गया है।उनकी जगह जिला डिंडोरी के सीएमएचओ मनोज पांडेय को एक बार फिर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की कमान सौंपी गई है।आपको बताए कि आदिवासी क्षेत्रों में पिछले दिनों बड़ी संख्या में बच्चों के बीमार होने और उपचार के दौरान मौतों के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में थी। मामले को लेकर आदिवासी समाज, राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों की ओर से लगातार जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठाई जा रही थी। इसी बीच सीएमएचओ के पद पर बदलाव को स्वास्थ्य विभाग में महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। ज्ञात हो कि डॉ पांडेय इसके पूर्व भी जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की कमान संभाल चुके हैं।

लगातार उठ रहे थे स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल

बच्चों की मौत के मामले के सामने आने के बाद से ही जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हुए। खासकर दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में समय पर उपचार, स्वास्थ्य अमले की उपलब्धता, बीमारी की पहचान और ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल उठते रहे हैं। मामले को लेकर विरोध-प्रदर्शन भी हुए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज होती गई। हालांकि यह एक प्रशासनिक प्रक्रिया बताई गई है लेकिन जानकारों का मानना है कि लगातार हो रही बच्चों की मौत वाले मामले और विभिन्न पार्टियों व संगठनों के बढ़ते दबाव के चलते हैं डॉ उपलप को हटाया गया है और उनकी जगह पूर्व सीएचएमओ डॉ पांडेय को जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की कमानसन की गई है

स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर कार्रवाई

जानकारी के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के निर्देश पर सीएमएचओ परेश उपलप को हटाने की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही डिंडोरी के सीएमएचओ मनोज पांडेय को जिला स्वास्थ्य अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। प्रशासनिक बदलाव के बाद अब जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नए सिरे से काम शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है।

नए सीएमएचओ के सामने कई चुनौतियां

मनोज पांडेय के सामने सबसे बड़ी चुनौती आदिवासी अंचलों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना होगी। दूरस्थ गांवों तक स्वास्थ्य अमले की नियमित पहुंच, बीमार बच्चों की समय पर पहचान, बेहतर उपचार व्यवस्था और गंभीर मरीजों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था को प्रभावी बनाना अहम होगा। वहीं, बच्चों की मौत के मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे लोगों की नजर अब इस बात पर भी रहेगी कि प्रशासनिक बदलाव के बाद स्वास्थ्य विभाग की जमीनी व्यवस्था में कितना सुधार आता है। सीएमएचओ को हटाए जाने की कार्रवाई को लगातार बढ़ते जनदबाव के बीच सरकार के महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

तेज रफ्तार ऑटो की टक्कर से 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत

वारासिवनी थाना क्षेत्र के ग्राम चिल्लोद में हुआ हादसा

पद्मेश न्यूज। बालाघाट/वारासिवनी। वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम चिल्लोद में बुधवार दोपहर तेज रफ्तार ऑटो की टक्कर से एक 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल इस व्यक्ति को 108 एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल बालाघाट लाया गया लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो चुकी थी। जिला अस्पताल पुलिस ने मृतक दुलीचंद पिता गोवारी लाल कोले 55 वर्ष ग्राम चिल्लोद निवासी का शव पोस्टमार्टम करवा कर उसके परिजनों को सोप दिया है प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम चिल्लोद निवासी दुलीचंद अपने परिवार के साथ मछली पकड़ने का काम करता था। 2 सितंबर को दोपहर करीब 12 बजे दुलीचंद घर से छाता लेकर तालाब में मछली देखने के लिए निकला था। इसी दौरान मुख्य मार्ग पर चिल्लोद सोसाइटी और राघोटोला के बीच सामने से तेज रफ्तार में आ रहे ऑटो ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। ऑटो की टक्कर से दुलीचंद गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसके सिर में गंभीर चोट आई थी। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर 108 एंबुलेंस की सहायता से घायल दुलीचंद को जिला अस्पताल बालाघाट ले लाया गया लेकिन अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।जिला अस्पताल पुलिस के प्रधान आरक्षक बारेलाल पांचे ने पंचनामा कार्रवाई के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया शव परिजनों को सौंप दिये और धारा 194 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मर्ग कायम कर मामले को आगे की कार्रवाई के लिए घटना स्थल से संबंधित वारासिवनी थाना पुलिस को भेज दिया गया है।

फोर व्हीलर की टक्कर से वनरक्षक घायल जिला अस्पताल में भर्ती

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बैहर रोड पर ग्राम देवटोला नहर के पास एक फोर व्हीलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार वनरक्षक घायल हो गया। घायल को राहगीरों की मदद से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती कराया गया। घायल नरेश पिता लक्ष्मण सिंघनधुपे 31 वर्ष ग्राम बहेराभाटा थाना बिरसा निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नरेश पिता सिंघनदुपे वन विभाग में वनरक्षक के पद पर पदस्थ है। नरेश के पिता इन दिनों बालाघाट नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। बताया गया कि 1 सितंबर को नरेश अपने जीजा के घर भरवेली आया था। रात करीब 10:30 बजे वह अपने पिता के लिए खाना लेकर मोटरसाइकिल से बालाघाट स्थित अस्पताल जा रहा था। इसी दौरान बैहर रोड पर ग्राम देवटोला नहर के पास सामने से तेज रफ्तार से आ रही फोर व्हीलर क्रमांक एमपी 50 एडी सी 0158 ने नरेश की मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से नरेश मोटरसाइकिल से गिरकर घायल हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। राहगीरों ने घायल नरेश को मोटरसाइकिल से जिला अस्पताल बालाघाट पहुंचाया, जहां उसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल पुलिस ने घायल नरेश के बयान दर्ज कर लिए हैं। मामले को आगे की कार्रवाई के लिए कोतवाली थाना पुलिस को भेजा गया है। पुलिस द्वारा दुर्घटना की जांच कर फोर व्हीलर चालक के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

इंस्टाग्राम पर दोस्ती का झांसा देकर युवक का अपहरण, बंधक बनाकर मारपीट और लूट-5 आरोपी गिरफ्तार

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गर्रा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। लालबर्रा निवासी एक युवक को इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बहाने बुलाकर अपहरण कर बंधक बनाने, मारपीट और जबरन वसूली का मामला दर्ज किया गया है। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी गर्रा बालाघाट के रहने वाले बताए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडित युवक लालबर्रा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। करीब एक सप्ताह पहले उसकी गर्रा निवासी रजत यादव से इंस्टाग्राम के माध्यम से पहचान हुई थी। 31 अगस्त को रजत यादव ने पीड़ित को फोन कर मिलने के बहाने गर्रा बुलाया शाम 7 बजे पीड़ित गर्रा पहुंचा रात करीब 9 बजे रजत यादव उसे मोटरसाइकिल से एकोड़ी स्थित यात्री प्रतीक्षालय ले गया। आरोप है कि वहां रजत ने अपने साथियों मयंक, अमित नाई, रुपेश, गोलटू भाऊ और हर्षित राहंगडाले को बुला लिया। आरोपियों ने उसका मोबाइल और 700 रुपये छीन लिए, मोबाइल का पासवर्ड मांगने पर मना करने पर उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद आरोपी उसे दारु भट्टी ले गए और फिर वापस प्रतीक्षालय ले आए, जहां शराब पीने के बाद उसके साथ शारीरिक और यौन उत्पीड़न किया गया और मोबाइल की रोशनी में वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर रुपयों की मांग की गई। पीड़ित जब मौका पाकर सड़क की ओर भागा तो आरोपियों ने उसे पकड़कर फिर से प्रतीक्षालय में ले जाकर रात 12 से 3 बजे तक बंधक बनाकर रखा, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। बाद में उसे गर्रा के एक सुनसान मकान में ले जाया गया। वहां भी उसके साथ मारपीट और यौन प्रताड़ना की गई और घर से पैसे मंगवाने का दबाव बनाया गया। आरोपियों ने उसकी घड़ी, बैग और बैग में रखे दस्तावेज भी लूट लिए।अगली सुबह 1 सितंबर को पीड़ित ने भूख लगने की बात कही तो आरोपी मयंक, हर्षित और रुपेश उसे बुलेट से चाय पिलाने के बहाने गर्रा ले गए और फिर कनकी बटालियन पेट्रोल पंप की ओर ले गए। वहां बाथरूम जाने के बहाने पीड़ित ने चकमा देकर भागने में सफलता पाई और कनकी बटालियन में मौजूद पुलिसकर्मियों को आपबीती बताई। पुलिसकर्मियों ने तत्काल डायल 112 को सूचना दी। जिसके बाद पीड़ित को कोतवाली लाया गया।कोतवाली पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर आरोपी रजत यादव, रूपेश बनवाले, मयंक डहरवाल, गोलटू भाऊ, अमित नाई और हर्षित राहंगडाले के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 127(2), 140(3), 296(बी), 308(3), 309(6), 351(3) के तहत अपराध दर्ज कर पांच आरोपियों को हिरासत में ले लिया है मामले की विवेचना जारी है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक उमेश बागरेचा द्वारा पद्मेश पब्लिकेशन, वार्ड नं.9, गुजरी चौक, बालाघाट (म.प्र.) से मुद्रित कराकर दैनिक बालाघाट एक्सप्रेस कार्यालय, काली पुतली चौक, बालाघाट(म.प्र.) से प्रकाशित,
प्रधान संपादक : उमेश बागरेचा, मो.नं. :9425138710, , ई-मेल- balaghatexpress@gmail.com पंजीयन क्रं. MPHIN/2009/32311, न्यायालयीन क्षेत्राधिकार बालाघाट